रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28, 1984/माघ 8, 1905
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 1984/MAGHA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1984

का० आ० 252.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 6 की उप-धारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत डा० पी०एस० संघवी ने अपने पांच साल के कार्य काल की समाप्ति पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के सदस्य के पद का कार्य भार 17 दिसम्बर, 1983 अपराह्न को त्याग दिया।

[सं० पी एफ जी (416) सी एल ए/78-प्रशा०-1]

आर० डी० मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affirs)

New Delhi, the 10th January, 1984

S.O. 252.—Under the Proviso to Sub-section (1) of Section 6 of the M.R.T.P. Act, 1969 (54 of 1969), Dr. P. S. Sanghvi, on completion of his tenure of five years, relinquished charge of the office of Member, Monopolies & Restrictive Trade Practices Commission, on the afternoon of 17th December, 1983.

[No. PFG (416) CLA/78-Admn. I]

R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984

का०आ० 253.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभागों की, जिनके कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. महासागर विकास विभाग।
2. परमाणु ऊर्जा विभाग, मुख्य सचिवालय, बम्बई।
3. परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली।

[संख्या 12022/1/78-रा०भा० (ख-2)]

सुन्दर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 9th January, 1984

S.O. 253.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Departments, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi :—

1. Department of Ocean Development

2. Department of Atomic Energy, Main Sectt., Bombay

3. Department of Atomic Energy, Branch Sectt., New Delhi

[No. 12022/1/78-O.I. (B2)]

SUNDAR SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 13 जुलाई, 1982

आयकर

का० आ० 254.—इस कार्यालय की दिनांक 20-4-80 की अधिसूचना सं० 3229 (फा० सं० 203/109/80-आ०क० नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि दक्षिण शुगर इन्स्टीट्यूट, पुणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

दक्षिण चीनी संस्थान, पुणे

यह अधिसूचना 1-4-1982 से 31-3-1985 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4797 (फा० सं० 203/135/82-आ०का०नि० II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th July, 1982

INCOME TAX

S.O. 254.—In continuation of this Office Notification No. 3239 (F. No. 203/109/80-ITA. II) dated 2-4-80 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Deccan Sugar Institute, Pune, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June, each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Deccan Sugar Institute, Pune

This notification is effective for a period of three years from 1-4-1982 to 31-3-1985.

[No. 4797 F. No. 203/135/82-ITA.II)]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 255.—इस कार्यालय की दिनांक 20-8-81 की अधिसूचना सं० 4177 (फा० सं० 203/129/81-आ०क०नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि संगम, लखनऊ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत

करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

मंगलम्, लखनऊ

यह अधिसूचना 28-7-83 से 26-7-85 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5462 (फा० सं० 203/207/83-आ०क०नि०-II)]

New Delhi, the 17 November, 1983

INCOME TAX

S.O. 255.—In continuation of this Office Notification No. 4177 (F. No 203/129/81-ITA. II) dated 20-8-81, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incom-tax Rules. 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Mangalam, Lucknow will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority for every financial year in such forms audited annual accounts showing their total income expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Mangalam, Lucknow

This notification is effective for a period from 28-7-83 to 26-7-1985.

[No. 5462 (F. No. 203/207/83-ITA II)]

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

आयकर

का०आ० 256.—इस कार्यालय की अधिसूचना के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् [illegible] ने निम्नलि[illegible] संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा [illegible] में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि अन्ना इंस्टिट्यूट आफ मेनेजमेंट, मद्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

अन्ना इंस्टिट्यूट आफ मेनेजमेंट, मद्रास

यह अधिसूचना 21-9-1983 से 31-12-1983 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5570 (फा०सं० 203/110/83-आ०क०नि०-II)]

New Delhi, the 6th January, 1983

INCOME TAX

S.O. 256.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act. 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Anna Institute of Management, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Instituition will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Anna Institute of Management, Madras

This notification is effective for a period from 21-9-1983 to 31-12-1985.

[No. 5570 (F. No. 203/110/83-ITA. II)]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984

आयकर

का०आ० 257.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 35(2) (क) के अंतर्गत अनुमोदित "डिवेलपमेंट आफ इंडिजिनस टेक्नालोजी फार दी मैन्यूफैक्चर आफ बाइमेटलिक सेंट्रिफ्यूगली कास्ट रोल्स—आर०एण्ड डी० प्रोजेक्ट" अनुसंधान परियोजना की अवधि को अक्तूबर, 1983 तक बढ़ा दिया गया है तदनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 19-9-1981 की अधिसूचना सं० 4227 में "जनवरी 1981 से जनवरी, 1983" के शब्दों और आंकड़ों को "जनवरी, 1981 से अक्तूबर 1983" पढ़ा जाये।

[सं० 5573 (फा० सं० 203/132/81-आ०क०नि०-II)]

मदन गोपाल चन्द गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 1984

S.O. 257.—It is hereby notified for general information that the duration of the research project "Development of Indigenous Technology for the manufacture of Bimetallic Centrifugally Cast Rolls—R&D Project" approved under section 35(2A) of the Income-tax Act, read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 has been extended upto October, 1983; accordingly in this Ministry's Notification No. 4227 and 19-9-1981, the words & figures "January, 1981 to January, 1983" be read as "January, 1981 to October, 1983".

[F. No. (5573/203/132-81-ITA II)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 258.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (II) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश सरकार के विशेष पुलिस स्थापन के पुलिस अधीक्षकों तथा इससे ऊपर के पद वाले सभी अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करती है।

[फा० सं० 5504/सं० 225/113/83-आ०क०नि०-II]

New Delhi, the 9th December, 1983

INCOME TAX

S.O. 258.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies all Officers of and above the rank of Superintendent of Police of the Special Police Establishment, Government of Madhya Pradesh for the purposes of the said sub-clause.

[No. 5504/F. No. 225/113/83-ITA. II]

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 259.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य सतर्कता आयोग बंगलौर अथवा इस संबंध में आयोग की ओर से विशेषतया प्राधिकृत किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 5540/फा०सं० 225/96/83-आ०क०नि०-II]

पी० सक्सैना, उप सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1983

INCOME TAX

S.O. 259.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Karnataka State Vigilance Commission, Bangalore, or any officer specifically authorised by the commission in this behalf for the purposes of the said sub-clause.

[No. 5540 F. No. 225/96/83-ITA-II]

P. SAXENA, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984

का० आ० 260.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० एन० शरण को शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-11-83 से प्रारम्भ होकर 30-11-86 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर० एन० शरण अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 2-29/82-आर०आर०बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 19th January, 1984

S.O. 260.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri R.N. Sarna as the Chairman of Shekhawati Gramin Bank, Sikar and specifies the period commencing on the 29th November, 1983 and ending with the 30th November, 1986 as the period for which the said Shri R. N. Sarna shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-29/82-RRB]

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1984

का०आ० 261.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० सी० चौबे को संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आजमगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-10-83 से प्रारंभ होकर 31-10-86 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस० सी० चौबे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 2-7/82-आर०आर०बी०]

एस० एस० हसुरकर, उप सचिव

New Delhi, the 12th January, 1984

S.O. 261.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri S. C. Chaubey as the Chairman of Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh and specifies the period commencing on the 29th October, 1983 and ending with the 31st October, 1986 as the period for which the said Shri S. C. Chaubey shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-7/82-RRB]

S. S. HASURKAR, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : कानपुर

अधिसूचना सं० 4/कानपुर/1983

कानपुर, 24 दिसम्बर, 1983

का० आ० 262.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जी० एस० मैंगी, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानपुर एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय कानपुर के सहायक समाहर्ताओं को उनके अपने क्षेत्राधिकार में समाहर्ता की उन शक्तियों का प्रयोग करने को प्राधिकृत करता हूं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 173 पी०पी० 5 और 173पी०पी०पी० (6) में प्रदत्त की गयी है।

[पत्रांक वा(8) (सभी उत्पाद-शुल्क) प्रा० 1/200/83/34956]

जी० एस० मैंगी, समाहर्ता

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कानपुर

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, KANPUR

NOTIFICATION NO. 4/KNP/1983

Kanpur, the 24th December, 1983

S.O. 262.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 I, G. S. Maingi, Collector of Central Excise, Kanpur, hereby authorise all the Assistant Collectors of Central Excise in the Collectorate of Kanpur, to exercise within their respective jurisdiction, the powers of the Collector, under Rule 173-PP(5) and 173-PPP(6) of Central Excise Rules, 1944.

[C. No. V(8) All Excis.s/T. IV|200|83|349561]

G. S. MAINGI, Collector

Central Excise Kanpur.

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 9, जनवरी, 1984.

का० आ० 263.—सर्वश्री वेलकम ग्रुप, होटल मौर्य शेराटन, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, नई दिल्ली को जिन और बीयर, नॉक्स और रम्स को छोड़कर व्हिस्की/वाइन/कॉग्नेक/लिक्योर/शैम्पेन/बिटर्स सहित शराब के आयात के लिए 16,53,444 रु० लागत बीमा भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1459532/सी/एक्स एक्स/85/एच/82/एम एल एस दिनांक 7-12-82 प्रदान किया गया था जो कि जारी करने की तारीख से 12 मास के लिए वैध था। अब पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि सीमा शुल्क प्रति उनसे खो गई है। पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार आवश्यक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उपर्युक्त आयात लाइसेंस सीमा शुल्क कार्यालय, बम्बई के पास पंजीकृत था और 5,01,148.04 रु० तक उपयोग में लाया जा चुका था और अब लाइसेंस के मद्दे शेष धनराशि 11,52,295.96 रु० है। शपथ पत्र घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया गया है कि यदि आयात लाइसेंस की उक्त सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति बाद में मिल गई या पा गई तो उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा देंगे। मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को 11,52,295.96 रु० की शेष धनराशि के लिए आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[मिसिल सं० 18/189/82-83/एम० एल० एस०/220]

एन० एस० कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक,

आयात एवं निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 9th January, 1984

S.O. 263.—M/s. Welcom group, Hotel Maurya Sheraton, Diplomatic Enclave, New Delhi were granted an import licence No. P|A|1459532|C|XX|85|H/82/MLS dated 7-12-82 for a cif value of Rs. 16,53,444 for import of Liquor including Whisky/Wine/Cognac/Liqueures|Champagne|Bitters excluding Gin & Beer, Necks and Rums, valid for 12 months from the

date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate Customs Purpose Copy for the aforesaid import licence on the ground that the Customs Copy has been lost by them. The party have furnished necessary affidavit as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid import licence was registered with Customs House, Delhi and was utilised for Rs. 501,148.04 and the balance against the licence is Rs. 11,52,295.96. It has also been incorporated in the affidavit declaration that if the said Customs Purpose Copy of the import licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs Purpose Copy of the Import licence has been lost and direct that a Duplicate Customs Purpose Copy of the import licence for the balance amount of Rs. 11,52,295.96 should be issued to the applicant. The original Customs Purpose copy of the licence is hereby cancelled.

[F. No. 18/189/82-83/MLS/220]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller Imports & Exports.

For Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

बंगलौर, 29 जून, 1983

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

का०आ० 264.—सर्वश्री बी० डी० एस० इलेक्ट्रोनिक्स, 132, I मेन रोड, सेशाद्रीपुरम, बंगलौर-560029 को (1) मिश्र धातु, इस्पात स्ट्रिप्स, (2) स्थाई चुम्बक के आयात के लिए 12 मास की वैधता अवधि के साथ 5,22,000 रु० (पांच लाख, बाइस हजार रुपए मात्र) का आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1940998/सी/एक्स एक्स/83/एक्स/82 दिनांक 5-4-1982 प्रदान किया गया था। इसके बाद उक्त लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने की तारीख से 6 मास के लिए पुनःवैध किया गया था।

आवेदक ने आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1983-84 के पैरा 352 के अंतर्गत अपेक्षित शपथ दाखिल किया है जिसमें यह कहा गया है कि अप्रैल/मार्च, 1982 के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति, सीमा शुल्क प्राधिकारी, मद्रास के पास पंजीकृत कराने तथा आंशिक रूप अर्थात् 3,09,907 रुपये के लिए उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गयी है। अब उसमें अप्रयुक्त मूल्य अर्थात 2,12,093 रु० शेष है।

मैं, तदनुसार, संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 2,12,093 रु० मूल्य के लिए जारी की जानी चाहिए लाइसेंस सं० पी/एस/1940998/सी/एक्स एक्स/83/एक्स/82, दिनांक 5-4-1982 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

विषय : लाइसेंस संख्या पी/एस/1940998/सी/एक्स एक्स/83/एक्स/82 दिनांक 5-4-1982 के मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के स्थान पर लाइसेंस सं० 2469713 दिनांक 30-6-1983 की अनुलिपि जारी करना।

सर्वश्री बी डी एस इलैक्ट्रोनिक्स, 132, I मेनरोड, सेशाद्रीपुरम, बंगलौर को लाइसेंस सं० पी/एस/1940998/सी/एक्स एक्स/83/82 दिनांक 5-4-1982 की मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी कर दी गई है। अनुरोध है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति (जिसका विवरण नीचे दिया गया है), यदि प्रस्तुत किया जाता है, को वैध नहीं माना जाए और उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रति के प्रस्तुत/उपयोग करने की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भेजी जाए।

लाइसेंस सं० और दिनांक	जिसने जारी किया	मदें	समयावधि	वैधता अवधि	क्षेत्र	प्रयुक्त मूल्य	बकाया मूल्य
पी/एस/1940998/सी/एक्स/एक्स/83/एक्स/81 दिनांक 5-4-1982	सं०मु०नि० आ०नि० मद्रास	1. मिश्रधातु इस्पात स्ट्रिप्स 2. स्थाई चुम्बक	ए०एम०82	12 मास 6 मास के लिए पुनर्वैधीकृत	सामान्य मुद्रा क्षेत्र	3,09,907/-	2,12,093 रु०

[मिसिल सं० आई टी सी/एस एल आई/100/आपूर्ति/ए एम-82/बंग]

Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports

Bangalore, the 29th June, 1983

CANCELLATION ORDER

S.O. 264.—M/s. BDS Electronics, 132, I main Road, Seshadripuram Bangalore-560029 was granted an Import Licence No. P/S/1940998 C/XX/83/X/82 dated 5-4-1982 for a value of Rs. 5,22,000/- (Rupees Five lakhs twenty two thousands only) for import of 1. Alloy Steel/Strips. 2. Permanent Magnets with a validity period of 12 months. Subsequently the licence was revalidated for a further period of 6 months from the date of expiry.

The applicant has filed an affidavit as required under para 352 of Hand Book of Import and Export Procedures 1983-84. Wherein they have stated that the Exchange Control Purposes copy of the said licence for the April/March-82 period has been lost, misplaced after having been registered with the customs authority Madras and utilised partly for a value of Rs. 3,09,907/-. There is a balance unutilised value of Rs. 2,12,093/-.

I am satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost misplaced and direct that the duplicate Exchange Control Purposes copy of the licence should be issued to the applicant for a value of Rs. 2,12,093/- The Original Exchange Control Purposes copy of licence No. P/S/1940998/C/XX/83/X/82 dated 5-4-1982 is cancelled.

Sub: Issue of duplicate copy of licence No. 2469713 dt 30-6-83 in lieu of original Exchange Control copy of licence No. P/S/1940998/C/XX/83/X/82 dated 5-4-1982

The duplicate Exchange Control Purposes copy of licence No. P/S/1940998/c/xx/83/x/82 dated 5-4-1982 has been issued to M/S. BDS Electronics 139 I Main Road Seshadripuram Bangalore. It is requested that the Exchange Control Purposes copy of licence (Particulars given below) should not be treated as valid if produced and that information should be sent to this office immediately of the Original copy of the above said licence presented utilised.

Licence No. and date	Issued by	Item	Period
P/S/1940998/c/xx/83/x/81 dt. 5-4-1982.	JCCI&E MADRAS.	*1. Alloy Steel Strip . 2. Permanent Magnets AM. 82.	
Valid for	**Area**	**Value of Utilised**	**Balance**
12 Months Revalidated for six month .	G.C.A.	Rs. 3,09,907/-	Rs. 2,12,093/-

[F. No. ITC/SSI/109/Suppl/AM-82/Bang.]

बंगलौर, 28 जुलाई, 1983

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

विषय : सर्वश्री आनंद अगरबत्ती मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, 7, दूसरा तल, गांधीपुरम, बंगलौर-560019 को जारी किए गए आयात-लाइसेंस सं० पी/एम/1941528 दिनांक 15-6-1983 की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करना।

का०आ० 265.—सर्वश्री आनन्द अगरबत्ती मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, 7, दूसरा तल, गांधीपुरम, बंगलौर-19 को आयात नियति नीति, 1983-84 जिल्द-1 के परिशिष्ट-5 में दी गई मदों का आयात करने के लिए 15,980 रु० का आयात लाइसेंस सं० पी०/एस/1941528 दिनांक 15-6-1983 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है। अपने आवेदन के समर्थन में प्रार्थी ने एक शपथ-पत्र छोटी अदालत, बंगलौर शहर के समक्ष विधिवत सांध्यांकित करा कर दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि 15,980 रु० के लिए लाइसेंस सं० पी/एस/1941528 दिनांक 15-6-1983 की प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की दोनों सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि आवेदक फर्म को जारी की जानी चाहिए।

उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

विषय :—15,980 रु० के आयात लाइसेंस सं० पी/एम/1951528 दिनांक 13-6-1983 की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करना।

मेसर्स दिए गए विवरणों के अनुसार सर्वश्री आनंद अगरबत्ती मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, 7, दूसरा तल, गांधीपुरम, बंगलौर-560019 को सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए अनुलिपि लाइसेंस सं० डी० 2469716 जारी कर दिया गया है। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रति उसके द्वारा उसकी फर्म के द्वारा प्रस्तुत करने पर तुरन्त इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

मिसिल सं० एवं दिनांक	जिसने जारी किया	मदें	लाइसेंस का मूल्य	वैधता	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
आई टी सी/एस एस/आई/आटो/41/ए०एम-84/बंग	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, बंगलौर	1983-84 की आयात-निर्यात नीति जिल्द-1 के पैरा 34(1) और परिशिष्ट-5 में दर्शाई गई मदें।	15,980 रुपए	12 मास	सामान्य मुद्रा क्षेत्र

[सं० आई टी सी /एस एस आई/आटो/41/ए० एम-84/बंग]

Bangalore, the 28th July, 1983

CANCELLATION ORDER

Sub : Cancellation of Customs Purpose Copy and Exchange Control Purpose Copy of Import Lic. P/S/1941528 dated 15-6-1983 for Rs. 15,980/- issued in favour of M/s. Anand Agarbathi Mfg. Co. 7, II Floor, Gavipuram, Bangalore-560 019.

S.O. 265.—M/s. Anand Agarbathi Mfg. Co. 7 II Floor, Gavipuram, Bangalore-19 have been granted an Import Lic. No. P/S 1941528 dated 15-6-1983 for Rs. 15,980/- for import of items figuring in Appendix—5 of Import Export Policy Vol. I 1983-84. They have requested for issue of duplicate copy of Customs Purpose Copy and Exchange Control Purpose Copy of the said licence on the ground that the original licence have been lost without having been registered with any customs authority and not utilised at all. In support of their request, the applicant have filed an affidavit duly sworn before the Court of Small Causes, Bangalore City.

I am satisfied that both the Customs purpose copy and Exchange Control Purpose Copy of the Lic. No. P/S/1941528 dated 15-6-1983 for Rs. 15,980/- have been lost/misplaced and that a duplicate customs purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence may be issued to the applicant firm.

The original customs purposes copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence is hereby cancelled.

Sub: Issue of duplicate copy of Customs Purpose Copy and Exchange Control Purpose copy Lic. No. P/S 1941528 dated 15-6-1983 for Rs. 15,980/-.

The duplicate copy of Import Licence No. D 2469716 for Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy have been issued to M/s. Anand Agarbathi Mfg. Co. 7, II Floor, Gavipuram Bangalore-560 019 as per the particulars given below the same should be sent to this office immediately the original copy of the above licence has been presented to him/his firm/her.

File No. & Date	Issued by	Items	Value of the lic.	Validity	Area
ITC/SSI/Auto/41 AM-84/Bang	J.C.C. I&E Bangalore	Items figuring in Appx. 5 and Para 34(1) of Import Export Policy Vol. I 1983-84.	Rs. 15,980/-	12 mths	GC

[No. ITC/SSI/Auto/41/AM-84/Bang.]

बंगलौर, 29 जुलाई, 1983

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

विषय :—सर्वश्री संगीत कार्पोरेशन, बंगलौर-19 को जारी किए गए 68,640 रु० के आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1941529 दिनांक 15-6-1983 की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करना।

का०आ० 266.—सर्वश्री संगीत कार्पोरेशन, सं० 31/2, गाविपुरम वेस्ट, बंगलौर-19 को आयात निर्यात नीति, 1983-84 (जिल्द-1) के परिशिष्ट 5 में दर्शाई गई मदों का आयात करने के लिए 68,640 रु० का आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1941529 दिनांक 15-6-1983 जारी किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस किसी सीमा-शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है। अपने आवेदन के समर्थन में प्रार्थी ने छोटी अदालत, बंगलौर शहर के समक्ष विधिवत साक्ष्यांकित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि 68,640 रु० के आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1941529 दिनांक 15-6-1983 की दोनों सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और इन दोनों की अनुलिपि आवेदक फर्म को जारी कर दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त लाइसेंस की मूल-सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

विषय :—68,640 रु० के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1941529/सी एक्स एक्स/87 एक्स/83 दिनांक 15-6-1983

• की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करना।

सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए सर्वश्री संगीत कार्पोरेशन, सं० 31/2, गाविपुरम वेस्ट बंगलौर-560019 को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार अनुलिपि आयात लाइसेंस सं० डी-2469715 जारी कर दिया गया है उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रति इनको/उसकी फर्म द्वारा प्रस्तुत करने पर उसे इस कार्यालय को तुरन्त भेजी जानी चाहिए।

मिसिल सं० एवं दिनांक	जिसने जारी किया	मदें	लाइसेंस का मूल्य	वैधता	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
आई टी सी/एस एस आई/आटो/42/ए०एम-84/बंग	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बंगलौर	1983-84 की आयात-निर्यात नीति जिल्द-1 के पैरा 34(1) और परिशिष्ट-5 में दर्शाई गई मद।	68,640 रुपए	12 मास	सामान्य मुद्रा क्षेत्र

[सं० आई टी सी/एस एस आई/आटो/42/ए०एम०-84/बंग]

Bangalore, the 29th July, 1983

CANCELLATION ORDER

Sub : Cancellation of Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of Import Lic. P/S/1941529 dated 15-6-1983 for Rs. 68,640/- issued in favour of M/s. Sangeeth Corporation, Bangalore-19.

S.O. 206.—M/s. Sangeeth Corporation U 31/2 Gavipuram, West Bangalore-19 have been granted an Import Lic. No. P/S 1941529 dated 15-6-1983 for Rs. 68,640/- for import of items figuring in Appendix-5 of Import Export Policy Vol. I 1983-84. They have requested for issue of duplicate copy of Customs purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence on the ground that the original licence has been lost without having been registered with any customs authority and not utilised at all. In support of their request the applicant have filed an Affidavit duly sworn before the Court of Small Causes, Bangalore City.

I am satisfied that both the Customs purpose copy and Exchange Control Purpose Copy of the Lic. No. P/S 1941529 dated 15-6-1983 for Rs. 68,640/- have been lost/misplaced and that a duplicate customs purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence may be issued to the applicant firm.

The original customs purposes copy and Exchange Control purpose copy of the said licence is hereby cancelled.

Sub: Issue of duplicate copy of Customs Purpose copy and Exchange Control purpose copy of Lic. No. P/S 1941529/C/XX/87/X/83 dated 15-6-1983 for Rs. 68,640/-.

The duplicate copy of Import Licence No. D 2469715 for Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy have been issued to M/s. Sangeeth Corporation U 31/2 Gavipuram, West Bangalore-560019 as per the particulars given below the same should be sent to this office immediately the original copy of the above licence has been presented to him/his firm/her.

File No. & date	Issued by	Items	Value of the Lic.	Validity	Area
ITC/SSI/Auto/42/AM-84 Bang.	J.C.C.I&E. Bangalore	Items figuring in Appx. 5 and Para 34(1) of Import Export Policy Vol. I 1983-84	68,640/-	12 months	GCA

[No. ITC/SSI/Auto/42/AM 84//Bang.[

बंगलौर, 18 अगस्त, 1983

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

का० आ० 267.—सर्वश्री एशियन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, 2/16, छठवां ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलौर-560010 को 12 मास की वैध अवधि के साथ 26 एस डब्ल्यू जी के हस्तोकृत (जी० आई० वायर) के आयात के लिए 66,000 रु० का आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1940994/सी/एक्स एक्स/83/एक्स/81 दिनांक 5-4-82 प्रदान किया गया था।

आवेदक ने 1983-84 की आयात तथा निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक की कंडिका 352 के अन्तर्गत यथा पेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अप्रैल-मार्च, 82 अवधि के लिए उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति मद्रास के सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराने और उसे आंशिक रूप से उपयोग में लाने के पश्चात् खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई और निदेश देता हूं कि 27,403/- रु० की शेष धनराशि को पूरा करने के लिए आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए।

लाइसेंस सं० पी/एस/1940994/सी/एक्स एक्स/83/एक्स 81 दिनांक 5-4-1982 को मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

विषय :—मूल लाइसेंस सं० पी/एस/1940994 दिनांक 5-4-1982 के बदले में लाइसेंस सं० डी/2469718 दिनांक 19-8-1983 की अनुलिपि प्रति जारी करना।

आपको यह सूचित किया जाता है कि सर्वश्री एशियन ट्रेडिंग एण्ड मैन्यफैक्चरिंग कम्पनी, बंगलौर-560010 को लाइसेंस सं० पी/एस/1940994/सी/एक्स एक्स/83/एक्स/81 दिनांक 5-4-1982 की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की गई है। यह अनुरोध है कि यदि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति (जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है) प्रस्तुत की जाए तो वैध न माना जाए और यदि उक्त लाइसेंस की मूल प्रति पहले ही आपके पत्तन पर प्रस्तुत कर दी गई है/उपयोग में लाई गई है तो उसकी तत्काल सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

लाइसेंस सं० एवं दिनांक	जारीकर्ता	मद	अवधि
पी/एस 1940994 दिनांक 5-4-1982	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, बंगलौर-9	जस्तकृत (जी आई वायर्स)	अप्रैल-मार्च, 82

वैधता अवधि	क्षेत्र	प्रयुक्त मूल्य	शेष धनराशि
12 मास	सामान्य मुद्रा क्षेत्र	रु० 38,596.49	रु० 27,403.51

[मिसिल सं० आईटीसी/एसएसआई/105/सप्लाई/एएम-82/[बंग०

Bangalore, the 18th August, 1983

CANCELLATION ORDER

S.O. 267.—M/s. Asian Trading and Manufacturing Company 9/16 6th Block Rajajinagar Bangalore-560 010 were granted an Import licence No. P/S/1940994/C/XX 83/X/81 dated 5-4-82 for Rs. 66,000/- for import of Galvanised (G.I. Wire) of 26 SWG with a validity period of 12 months.

The applicant has filed an affidavit as required under para 352 of Hand Book of Import and Export Procedure 1983-84 wherein they have stated that the Customs Purposes copy of the said licence for April-March, 82 period has been lost/misplaced after having been registered with Madras Customs Authority and Utilised partly.

I am satisfied that the original Customs purposes copy of the said licence has been lost/misplaced and direct that the duplicate Custom Purpose copy of the above licence should be issued to cover the balance of Rs. 27,403/51 to the applicant.

The Original Customs Purpose copy of licence No. PS. 1940994/C/XX/83/X/81 dated 5-4-1982 is hereby cancelled.

Sub : Issue of duplicate copy of licence No. D/2469718 dated 19-8-1983 in lieu of Original licence No. PS. 1940994 dated 5-4-1982

This is to inform you that the duplicate customs purposes copy of licence No. P/S/1940994 /C/XX/83/X/81 dated 5-4-1982 has been issued to M/s. Asian Trading and Manufacturing Company Bangalore-560 010. It is requested that the Customs Purposes copy (Particulars given below) should not be treated as valid if produced and that information should be sent to this Office immediately if the Original copy of the above said licence has already been presented/utilised.

Licence No. and date	Issued by	Item	Period
P/S/1940994 dt. 5-4-1982	J.C.C.I. & E Bangalore-9	Galvanised (GI Wires)	April-March '82
Valid for	Area	Value utilised	Value Balance
12 Months	G.C.A.	Rs. 38,596.49	Rs. 27,403.52

[F. No. ITC/SSI/105/Supply/AM. 82/Bang.]

आदेश

बंगलौर, 16 सितम्बर, 1983

विषय :—आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खण्ड 9 के अंतर्गत

का० आ० 268.—सर्वश्री वसंत केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर 68 को अप्रैल-मार्च, 84 की नीति पुस्तक की कंडिका-73(2) के अन्तर्गत कच्चे माल जैसे रैंथाइड्राक्सी मिथाइल एन एन डाइमिथिलेमाइन नेप्थामेडियन-कार्बोक्सामाइड-कार्बामाइड-कम्पाउण्ड के पूर्व उपभोग के आधार पर 24,18,750 रु०/- का एक वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस सं०-1941572 दिनांक 27-7-83 जारी किया गया था।

बाद में यह पता लगा कि आयात के लिए अनुमित उक्त मद लाइसेन्स में गल्ती से जारी की गई थी क्योंकि विचाराधीन मद स्वयं ही अप्रैल-मार्च, 83 अवधि के दौरान सरणीबद्ध की गई थी और इसलिए अप्रैल-मार्च, 84 अवधि के दौरान सरणीबद्ध मद के लिए लाइसेंस जारी करना अप्रैल-मार्च 84 की नीति पुस्तक की कंडिका-73(2) के प्रावधानों के अनुसार नहीं था इसलिए, कोई भी सुपुर्दगी किए बिना लाइसेंस वापस लिया गया। देखिए इस कार्यालय का पत्र सं० एस० एस० आई०/अन्ध/18/अप्रैल-मार्च, 84/बंग/670 दिनांक 1-8-1983। चूंकि फर्म ने इस कार्यालय को लाइसेंस वापस नहीं किया था जैसा कि मांगा गया था, अतः 8-8-1983 को एक आदेश जारी किया गया था कि लाइसेंस का परिचालन बन्द कर दिया जाए।

तत्पश्चात्, यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड-9(1)(क) के अन्तर्गत एक कारण बताओ सूचना दिनांक 27-8-1983 जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि लाइसेंस गलती से जारी किया गया था और यह मद अप्रैल-मार्च, 83 की अवधि के दौरान स्वयं सरणीबद्ध थी, इसलिए, अप्रैल-मार्च, 84 की नीति अवधि की कंडिका 73(2) के अनुसार लाइसेंस जारी करना सही नहीं था। एस सी एन के प्रत्युत्तर में पार्टी ने स्पष्टीकरण भेजा और 12-9-83 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी आई थी।

एस सी एन के उत्तर में पार्टी ने कहा कि मद मथाडाइड्राक्सी मिथाइल एन-एन-डाइमिथिलेमाइन नेप्थामेडियन-कार्बोक्सामाइड-कार्बोमाइड-कम्पाउण्ड अप्रैल-मार्च, 83 अवधि के दौरान सरणीबद्ध नहीं थी और अप्रैल-मार्च, 84 अवधि के दौरान यह पहली बार सरणीबद्ध थी। इस विवरण के समर्थन में उन्होंने दो बातें उठाई हैं :

1. बम्बई के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने अप्रैल-मार्च, 83 की अवधि के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मद की निकासी की।

2. आयात तथा निर्यात नीति, 83-84 की कंडिका 241(4) के अनुसार परिशिष्ट-3, 4, 5 और 9 में दर्शाई गई औषधियां उसी औषधि के आकार की थीं और 1982-83 के दौरान उपर्युक्त परिशिष्टों में दर्शाई गई औषधियों में उसी औषधि के नमक और इस्टर्स शामिल थे। व्यक्तिगत सुनवाई के समय लाइसेंसधारी ने यही बातें दुहराईं।

मैंने पार्टी के उत्तर पर विचार किया है और पार्टी के विचार को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

1. बात यह है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत माल की निकासी से यह सिद्ध नहीं हो पाता कि मद 82-83 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत और यह शायद अप्रैल-मार्च, 82 की नीति के अनुसार की गई सुपुर्दगी के मुद्दे हुई होगी जब मद खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत थी। यहां तक कि अन्यथा रूप से अधोहस्ताक्षरी को वे परिस्थितियां ज्ञात नहीं हैं जिसके अधीन सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने 1982-83 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मद की निकासी की अनुमति दी थी। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की ओर से कोई भी गलती या अन्य किसी कारण से लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए बाध्यकर नहीं है।

2. जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, समानता केवल वर्तमान नीति में शामिल है यह बताया जाए कि पार्टी द्वारा बताई गई आयात नीति की कंडिका-241(4) आयात नीति का केवल स्पष्टीकरण प्रावधान मात्र है और उससे आयात नीति में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं होता यदि नीति में कोई परिवर्तन होता है तो यह समुचित परिशिष्टों में दृष्टिगत होता है। जहां तक टेट्रासाइक्लीन बेस/एच सी एल का सम्बन्ध है, अप्रैल-मार्च, 82 और अप्रैल-मार्च, 83 दोनों ही नीतियों के परिशिष्ट-9 की मद के ब्यौरों में कोई परिवर्तन नहीं है। व्याख्या के सामान्य नियम के अनुसार स्पष्टीकरण मूल प्रावधान की तिथि से होता है और पूर्व प्रभावी है।

पार्टी का यह कथन कि चूंकि यह स्पष्टीकरण केवल 83-84 की नीति में दर्शाया गया है '82'-83 की नीति में नहीं, यह स्पष्टीकरण केवल '83'-84 से लागू होगा, उपर्युक्त कारणों से सही नहीं है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल-मार्च, 84 की नीति की कंडिका 73(2) के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करना स्पष्ट रूप से गलत था इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड 9(1)(क) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रैल-मार्च, 84 की नीति पुस्तक की कंडिका-73(2) के अनुसार मेथाड्राइड्राक्सी मिथाइल एन-एन-डाइमिथिलेमाइन मेथाक्लोडियन-कार्बोक्सीमाइड-कार्बामाइड-कम्पाउण्ड के आयात के लिए जारी किया गया लाइसेंस सं० 1941572 दिनांक 27-7-1983 एतद्द्वारा रद्द करता है।

अतः यह कार्यालय आदेश दिनांक 8-8-1983 उपर्युक्त लाइसेंस के संचालन को स्थगित करके एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।

यदि सर्वश्री वर्सन केमिकल्स प्राइवेट लि०, बंगलौर उपर्युक्त निर्णय से दुखित हैं तो वे इस आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को अपील कर सकते हैं।

[आई टी सी/एस एस आई/अन्य/18/ए एम-84/बंग०]

ORDER

Bangalore, the 16th September, 1983

Sub:—Under Section 9 of Import Control Order, 1955

S.O. 268.—M/s. Varson Chemicals Private Limited, 9th Mile, Hosur Road, Singasandra P.O., Bangalore-560068 were granted an import licence No. P/S/1941572 dated 27-7-1983 for Rs. 24,18,750 for import of Tetracyline Urea Complex (Pentahydroxy Methyl—N-N-Dimethylamino Napthacendion-Carboxamine-Carbamide Compound) in terms of para 73(2) of Import-Export Policy for April-March 1984 subject to the Actual User condition. As the item is not a newly canalised lictnce during April-March 83-84 period, the issue was erroneous ;

Whereas proceedings of cancellation of licence have been initiated under sub clause 9(1) of the Imports (control) Order. In exercise of the powers conferred under Clause 9(3) of Imports (Control) order 1955, as amended I suspend operation of the licence No. P/S/1941572 dated 27-7-1983 for Rs. 24,18,750 issued for April-March 1984 period to the SSI Unit M/s. Varson Chemicals Private Limited, 9th Mile. Hosur Road, Singasandra P.O., Bangalore-560068.

[No. ITC/SSI/OTHERS/18/AM-84/Bang.]

बंगलौर, 17 सितम्बर, 1983

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

का०आ० 269.—सर्वश्री कर्नाटक स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 30, रेस कोर्स रोड, बंगलौर-560001 को 24 मास की वैधता अवधि के भीतर 1.2 नग वी०एच०एफ०एफ०एम० मोबाइल रेडियो टेलीफोन 2.2 नग वी०एच०एस०एफ०एम० ट्रांसपोर्टेबल रेडियो टेलिफोन 3.2 नग बी०ए०एफ०एम० बेस स्टेशन 4.1 नग वी०एच० एफ०हैंड पोर्टेबल रेडियो टेलीफोन के आयात के लिए 89125/ रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/सी/1451089/सी/ एक्सएक्स/85/एक्स/82 दिनांक 17-12-1982 प्रदान किया गया था।

आवेदक ने 1983-84 की आयात-निर्यात क्रियाविधि हैण्डबुक की कंडिका-352 के अंतर्गत यथाअपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल-मार्च, 83 की उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई/ अन्यानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रयोजन, दोनों ही प्रतियां खो गई/ अस्थास्थ हो गई हैं और निदेश देता हूं कि 89125 रु० के पूरे मूल्य के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी की जाए।

मूल लाइसेंस सं० पी/सी/1451089/सी/एक्स/85/एक्स/ 82 दिनांक 17-12-1982 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[मिसिल सं० आईटीसी/एयू/106/सीजे/एएम 83/बंग०]

ज० तुकाराम, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

Bangalore, the 17th September, 1983

CANCELLATION ORDER

S.O. 269.—M/s. Karnataka State Electronics Development Corporation Limited, 30, Race Course Road, Bangalore-560001 were granted an import licence No. P/C/1451089/C/XX/85/X/82 dated 17-12-1982 for Rs. 89125 for import of 1.2 Nos. VHF FM Mobile Radio Telephone 2.2 Nos V.H.S. FM transportable Radio Telephone 3. 2 Nos. VHF FM Base station 4.1 No. VHF Head Portable Radio Telephone with a validity period of 24 months.

The applicant has filed an affidavit as required under para 352 of Hand Book of Import and Export Procedure 1983-84, wherein they have stated that the customs purposes and Exchange Control Purposes copy of the said licence for April—March 83 period have been lost/misplaced without having been registered with any customs authority.

I am satisfied that both the Exchange Control any Customs purposes copy of the licence in Original have been lost/misplaced and direct that the duplicate copy of the above said licence should be issued for the full value of Rs. 89125.

The Original licence No. P/C/1451089/C/XX/85/X/82 dated 17-12-1982 is hereby cancelled.

[F. No. ITC/AU/106/CG/AM.83/Bang]

R. THUKKARAM, Dy. Chief Controller of Imports & Exports for Jt. Chief Controller of Imports and Exports.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1984

का० आ० 270.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन-चिह्न) नियमों तथा विनियमों 1955 के नियम 3 के उप-नियम (2) और विनियम (3) के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक विशिष्टि संख्या IS: 10633-1983 वनस्पति की विशिष्टि 1983-12-31 से निर्धारित हो गई है।

[सं० सी एम डी/13:2]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 6th January, 1984

S.O. 270.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Indian Standards Specification number IS : 10633-1983 Specification for vanaspati has been established with effect from 1983-12-31.

[No. CMD/13 : 2]

का० आ० 271.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियमों तथा विनियमों 1955 के नियम 3 के उप-नियम (2) और विनियम (3) के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक विशिष्टि संख्या IS : 10748-1984 वेल्डकृत ट्यूब और पाइपों की गर्म वेल्लित इस्पात के स्केल्प/पत्तियों की विशष्टि 1984-01-31 से निर्धारित हो गई है। [सं० सी० एम० डी 13:2]

ए० एस० चीमा, अपर महानिदेशक

S.O. 271.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of Regulations 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Indian Standard Specification number IS : 10748-1984 Specification for hot rolled steel skelp/strip for welded tubes and pipes has been established with effect from 1984-01-31.

[No. CMD/13 : 2]

A. S. CHEEMA, Addl. Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1984

का०आ० 272.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 575 तारीख 19-5-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है,

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बम्बई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

एल०ए० केस नम्बर 24/83

अनुसूची

पाईप लाईन माहुल गांव से, तालुका—कुर्ला, जिला :—बम्बई उपनगर में महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हेक्टर	ऐयर
माहुल	का भाग	—	00	—
,,	17	—	00	16
,,	164	—	00	64
,,	165	—	00	22

[क्रमांक 12016/12/83-प्रोड०]

S.O. 272.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1575 (No. 12016/12/83/Prod) dated 19-3-83 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Bombay free from all encumbrances.

L.A. CASE NO. 24/83.

SCHEDULE

Pipeline Passing through Village Mahul, Taluk : Kurla, Dist. : Bombay Suburban, Maharashtra.

Village	Survey No./Gut No.	Hissa No.	Area H—R
Mahul	17 Part	—	00—16
	164 ,,	—	00—64
	165 ,,	—	00—22

[No. 12016/12/83-Prod.]

का० आ० 273.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2573 तारीख 16-6-83 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बंबई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एल०ए० केस नम्बर 29/83 :

अनुसूची

पाइपलाइन लोहोगांव से तालुका : हवेली जिला : पुणे, महाराष्ट्र तक

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर	क्षेत्रफल एयर
1	2	3	4	
लोहोगांव	16 का भाग	—	00	42
,,	66 ,,	—	00	15
,,	67 ,,	—	00	69
,,	74 ,,	—	00	18
,,	75 ,,	—	00	45
,,	76 ,,	—	00	54
,,	97 ,,	—	00	27
,,	102 ,,	—	00	11
,,	103 ,,	—	00	25
,,	104 ,,	—	00	01
,,	105 ,,	—	00	49
,,	107 ,,	—	00	81
,,	115 ,,	—	00	08
,,	117 ,,	—	00	67
,,	118 ,,	—	00	31
,,	119 ,,	—	00	38
,,	120 ,,	—	00	56
,,	123 ,,	—	00	27
,,	124 ,,	—	00	33
,,	299 ,,	—	00	09
,,	300 ,,	—	00	43
,,	301 ,,	—	00	40
,,	302 ,,	—	00	79
,,	303 ,,	—	00	18
,,	305 ,,	—	00	18
,,	307 ,,	—	00	27
,,	308 ,,	—	00	40
,,	309 ,,	—	00	49
,,	314 ,,	—	00	02

1	2		3	4	
लोहगांव	316	का भाग	—	00	06
(जारी)	317	"	—	00	25
		"	—	00	18

[सं० 12016/56/83-प्रोड]

S.O. 273.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 2573 (12016/56/83-Prod) dated 16-6-83 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government,

And furher the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in he schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

L.A. CASE No. 29/83

SCHEDULE

Pipeline from Village Lohgaon, Taluka : Haveli, Distt. : Pune, Maharashtra.

Village	Survey No./Gut No.	Hissa No.	Area H—R	
1	2		3	4
Lohgaon	16	Part	—	00—42
	66	,,	—	00—15
	67	,,	—	00—69
	74	,,	—	00—18
	75	,,	—	00—45
	76	,,	—	00—54
	97	,,	—	00—27
	102	,,	—	00—11
	103	,,	—	00—25
	104	,,	—	00—01
	105	,,	—	00—49
	107	,,	—	00—81
	115	,,	—	00—08
	117	,,	—	00—67
	118	,,	—	00—31
	119	,,	—	00—33
	120	,,	—	00—36
	123	,,	—	00—27
	124	,,	—	00—33
	299	,,	—	00—09
	300	,,	—	00—43
	301	,,	—	00—40
	302	,,	—	00—79
	303	,,	—	00—18
	305	,,	—	00—18
Lohgaon (Contd.)	307	Part	—	00—27
	308	,,	—	00—40
	309	,,	—	00—49
	314	,,	—	00—02
	316	,,	—	00—06
	317	,,	—	00—25
			—	00—18

[No 12016/56/83-Prod.]

का० आ० 274.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2572, तारीख, 16-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एल०ए० केस नम्बर 31/83 :

अनुसूची

पाइपलाइन गोजरी खुर्द गांव से, तालुका : हवेली जिला : पुणे, महाराष्ट्र तक

गांव	सर्वेक्षण नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर	एयर
1	2	3	4	
गोजरी खुर्द	186 का भाग	—	00	05
,,	193 ,,	—	00	03

1	2		3	4	
मोजरी खुर्द (जारी)	202	भाग	—	00	29
	203	"	—	00	05
	204	"	—	00	01
	205	"	—	00	09
	206	"	—	00	05
	207	"	—	00	08
	209	"	—	00	08
	210	"	—	00	09
	214	"	—	00	09
	218	"	—	00	01
	219	"	—	00	14
	220	"	—	00	06
	221	"	—	00	05
	222	"	—	00	23
	227	"	—	00	07
	284	"	—	00	05
	286	"	—	00	06
	287	"	—	00	06
	289	"	—	00	02
	288	"	—	00	06
	290	"	—	00	04
	297	"	—	00	05
	304	"	—	00	18
	305	"	—	00	15
	309	"	—	00	05
	310	"	—	00	04
	311	"	—	00	04
	312	"	—	00	04
	315	"	—	00	05
	316	"	—	00	36
	317	"	—	00	05
	326	"	—	00	05
	328	"	—	00	11
	330	"	—	00	03
	614	"	—	00	04
	622	"	—	00	18
	623	"	—	00	24
	624	"	—	00	07
	625	"	—	00	07
	660	"	—	00	05
	671	"	—	00	12
	666	"	—	00	05
	662	"	—	00	05
	679	"	—	00	08
	678	"	—	00	09
	680	"	—	00	05
	681	"	—	00	05
	682	का भाग	—	00	03
	780	"	—	00	33
	765	"	—	00	23
	766	"	—	00	11
	767	"	—	00	02
	768	"	—	00	15
	758	"	—	00	96
	759	"	—	00	04
	798	"	—	00	10
	799	"	—	00	05
	800	"	—	00	02
	801	"	—	00	08
	802	"	—	00	05
	803	"	—	00	08
	804	"	—	00	02
	805	"	—	00	05
	812	"	—	00	07
	813	"	—	00	05
	816	"	—	00	04
	814	"	—	00	07
	817	"	—	00	04
	818	"	—	00	05
	824	"	—	00	22

[सं० 12016/58/83-प्रोड]

S.O. 274.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 2572 (12016|58|83-Prod) dated 16-6-83 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

L. A. CASE No. 31/83

SCHEDULE

Pipeline from Village Manjri Khurd Taluka: Haveli Dist. Pune, Maharashtra.

Village	Survey No./Gat No.	Hissa No.	Area H=R
1	2	3	4
Manjri Khurd	136 Part	—	00=05
	193 „	—	00=03
	202 „	—	00=19
	203 „	—	00=05
	204 „	—	00=01
	205 „	—	00=09
	206 „	—	00=05
	207 „	—	00=05
	209 „	—	00=08
	210 „	—	00=10
	211 „	—	00=09
	218 „	—	00=01
	219 „	—	00=14
	220 „	—	00=05
	221 „	—	00=05
	222 „	—	00=13
	227 „	—	00=07
	284 „	—	00=05
	286 „	—	00=05
	287 „	—	00=05
	289 „	—	00=01
	288 „	—	00=06
	290 „	—	00=01
	297 „	—	00=17
	304 „	—	00=18
	305 „	—	00=15
	309 „	—	00=05
	310 „	—	00=04
	311 „	—	00=04
	312 „	—	00=04
	315 „	—	00=05
	316 „	—	00=16
	317 „	—	00=05
	326 „	—	00=05
	328 „	—	00=11
	330 „	—	00=03
	614 „	—	00=01
	612 „	—	00=18
	613 „	—	00=14
	624 „	—	00=07
	625 „	—	00=07
	660 „	—	00=07
	671 „	—	00=05
	665 „	—	00=1[illegible]
	662 „	—	00=05
	678 „	—	00=13
	679 „	—	00=13
	680 „	—	00=05
	681 „	—	00=05
	682 „	—	00=03
	760 „	—	00=33
	765 „	—	00=13
	766 „	—	00=11
	767 „	—	00=07
	768 „	—	00=15
	758 „	—	00=06
	759 „	—	00=04
	798 „	—	00=19
	799 „	—	00=05
	800 „	—	00=03
	801 „	—	00=08

1	2	3	4
Manjri Khurd (contd.)	802 Part	—	00=05
	803 „	—	00=08
	804 „	—	00=02
	805 „	—	00=05
	810 „	—	00=07
	812 „	—	00=05
	816 „	—	00=04
	814 „	—	00=07
	817 „	—	00=04
	819 „	—	00=05
	824 „	—	00=22

[No. O-11016/53/83-Prod.]

का० आ० 275.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद-10 से अहमदाबाद-13 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

अहमदाबाद-10 से अहमदाबाद-13 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात	जिला—अहमदाबाद		तालुका—दसक्रोई	
गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
बांध	295	0	10	80
	296	0	07	20
	291	0	10	00
	286	0	07	05

1	2	3	4	5
	287	0	08	26
	284	0	11	55
	282	0	14	80
	278	0	04	50

[सं० O-12016/148/83-प्रोड]

S.O. 275.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ahmedabad-10 to Ahmedabad-13 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission :

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specificalflly whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ahmedabad—10 to Ahmedabad-13.
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Wanch	295	0	10	80
	296	0	07	20
	291	0	10	00
	286	0	07	05
	287	0	08	26
	284	0	11	55
	282	0	14	80
	278	0	04	50

[No. O-12016/148/83-Prod.]

का० आ० 276.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन० के० डी० एक्स से पाईपलाइन-65 सी०टी० एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध, अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन० के० डी० एक्स से पाइप लाइन-65 से सी० टी० एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य–गुजरात जिला और तालुका–मेहसाणा

गांव	सं० नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
मेमहपुरा	80/1	0	04	80
	81/2	0	08	05
	32	0	09	10

[सं० O-12016/150/83-प्रोड]

S.O. 276.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKDX to Pipeline-65 to CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKDX to Pipeline 65 to CTF
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana.

Village	Survey No.	Hec-tare	Area	Cen-tiare
Memadpura	80/1	0	04	80
	81/2	0	08	05
	32	0	09	10

[No.O-12016/150/83—Prod.]

का० आ० 277.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूआ संख्या के 230 से जी० जी० एस० VIII तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० बे-230 से जी०जी० एस० –III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य गुजरात जिला–महेसाना तालुका–कलोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कलोल	869	0	04	05
	793/1	0	04	50
	792	0	04	95
	789/पी	0	04	65

[सं० ओ-12016/51/83 प्रोड]

S.O. 277.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from WELL No. K-230 to GGS VIII in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission :

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pifeline from Well No. K-230 to GGS VIII

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kalol	869	0	04	05
	793/1	0	04	50
	792	0	04	95
	789/P	0	09	65

[No. O-12016/51/83-Prod.]

का० आ० 278.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद-13 से अहमदाबाद 18 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

अहमदाबाद-13 से अहमदाबाद-18 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य–गुजरात जिला–अहमदाबाद तालुका–दसक्रोइ

गांव	सर्वे०नं०	हे०	आर	सें०
वौंच	108	0	09	00
	110	0	12	83

1	2	3	4	5
	111	0	10	95
	112	0	01	65
	100	0	09	50
	99	0	03	75
	98	0	05	62
	95	0	12	60
	83	0	15	60
	176	0	13	05
	175	0	14	50
	174	0	00	50
	177	0	12	55
	203/1	0	05	85
	202	0	08	31
	201.	0	08	36
	211	0	01	62
	231	0	03	00
	230	0	07	88
	238	0	05	70
	237	0	06	00
	242	0	05	91
	241	0	03	37
	243	0	05	55
	260	0	12	60
	259	0	29	26
	265	0	08	25
	279	0	12	53
	281	0	13	05
	278	0	15	60
	339	0	01	00
	358	0	14	93
	357	0	09	00
	360	0	13	30

[सं० O-12016/153/83-प्रोड]

S.O. 278.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ahmedabad-13 to Ahmedabad-18 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission :

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ahmedabad—13 to Ahmedabad—18

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Daseroi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Wanch	108	0	09	00
	110	0	12	83
	111	0	10	95
	112	0	01	65
	100	0	09	50
	99	0	03	75
	98	0	05	62
	95	0	12	60
	83	0	15	60
	176	0	13	05
	175	0	14	50
	174	0	00	50
	177	0	12	55
	203/1	0	05	85
	202	0	08	31
	201	0	08	36
	211	0	01	62
	231	0	03	00
	230	0	07	88
	238	0	05	70
	237	0	06	00
	242	0	05	91
	241	0	03	37
	243	0	05	55
	260	0	12	60
	259	0	29	26
	265	0	08	25
	279	0	12	53
	281	0	13	05
	278	0	15	60
	339	0	01	00
	358	0	14	93
	357	0	09	00
	360	0	13	30

[No. O-12016/153/83-Prod.]

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1984

का० आ० 279.—पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (2), खण्ड (क) के अनुसरण में और भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय की दिनांक 16 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1737 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में दिये हुए प्राधिकारी के कथित अधिनियम के अधीन अनुसूची के कालम (2) में प्रविष्टि के अनुरूप लिखित क्षेत्रों के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

प्राधिकारी और पता	क्षेत्राधिकार
1	2
श्री डी० चक्रवर्ती, सीनियर पाईपलाईन इंजीनियर	पश्चिम बंगाल

प्राधिकारी और पता	क्षेत्राधिकारी
1	2
द्वारा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, (रिफाईनरीज तथा पाईपलाईनस प्रभाग), हल्दिया मौरीग्राम राजबंद बरौनी पाईपलाईन, 14, ली रोड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	

[एफ० सं० 12017/1/83-प्रोड]

विनय बंसल, निदेशक

New Delhi, the 11th January, 1984.

S.O. 279.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy S.O. No. 1737dated the 16th March, 1983, the Central Government hereby authorises the authority mentioned in Column 1 of the Schedule below to perform the functions of Competent Authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in Column 2 of the said schedule.

SCHEDULE

Authority & Address	Areas
Shri D. Chakraborty, Sr. Pipeline Engineer. C/O Indian Oil Corporation Ltd., (Refineries & Plpelines Divn.) Haldia-Mourigram-Rajbandh-Barauni Pipe 14-Lee Road. Calcutta, West Bengal.	State of West Bexn

[F. No. 12017/1/83-Prod].
Vinay Bansal, Director.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1984

का०आ० 280.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग की अधिसूचना सं० का०आ० 2086, दिनांक 16 जूलाई, 1981 द्वारा जिसे भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2), तारीख 1 अगस्त, 1981 में प्रकाशित किया गया था, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 722.023 हैक्टर (लगभग) या 1784.16 एकड़ (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा-मंत्रालय, (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० 3279, तारीख 9 अगस्त, 1983 द्वारा 1 अगस्त, 1983 से आरम्भ होने वाली छह मास की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि का या ऐसी भूमि में या उस के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है; और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 609.64 हैक्टर (लगभग) या 1506.48 एकड़ (लगभग) भूमि का, सभी अधिकारों सहित जैसा कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्जित है, अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

टिप्पण-1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं० सी-1 (ई)/(1) जे०आर० 259-583 दिनांक 12-5-1983 का निरीक्षण कलक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (राजस्व अनुभाग) कोल एस्टेट सिविल लाईंस, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण-2 पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है :—

अर्जन के प्रति आपत्ति

"8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो आवश्यक समझता है वह या जो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसा भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशें और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पण—3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, कार्डिंगल स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची "क"

पदमपुर ब्लाक

वर्धा वैली कोलफील्ड

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार (राजस्व भूमि)

क्र० सं०	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं०	तहसील और जिला	हैक्टरों में क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	किताडी	11	चन्द्रपुर	42.23	भाग
2.	पदमपुर	11	,,	204.06	,,
3.	मिनगांव	11	,,	105.46	,,
4.	सिनहाला	11	,,	3.02	,,
5.	चन्दाला सुर्ला (खैरगांव)	10	,,	12.24	,,
6.	कान्धी मालगुजारी	10	,,	90.77	,,
7.	दुर्गापुर	10	,,	121.61	,,
8.	चैक कोन्धी	10	,,	0.15	,,
	कुल राजस्व भूमि			579.54 हैक्टर (लगभग) या 1432.10 एकड़ (लगभग)	

अनुसूची "क 1"

सभी अधिकार (वन भूमि)

क्र०सं०	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं०	तहसील और जिला	खसरा सं०	हैं०में० क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	किताडी	11	चन्द्रपुर	86	12.91	भाग
2.	पदमपुर	11	,,	71	17.19	भाग
	कुल क्षेत्र				30.10 हैक्टर (लगभग) 74.38 एकड़ (लगभग)	
	कुल योग				609.64 हैक्टर (लगभग) या 1506.48 एकड़ (लगभग)	

ग्राम किताडी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 2 (भाग), 3 से 5, 6/1, 6/2, 7 से 12, 13 (भाग) 86 (भाग), नाला और सड़क (भाग)

ग्राम पदमपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 1 से 19, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21 से 40, 40/1, 41/2, 42 से 52, 53/1, 53/2, 54 से 70, 71/3 (भाग), 126 (भाग); 134 (भाग), 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 137 से 139, 140/1 140/2, 141, 142 (भाग), 143/1 (भाग), 1432, 143/3 (भाग), 144 (भाग), 158 (भाग), 159 (भाग), सड़क (भाग), नाला (भाग) और आबादी।

ग्राम मिनगांव में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 1 से 28. 29/1, 29/2, 30 से 38, 39 (भाग), 40 (भाग), 41 (भाग), 42 (भाग), 43 से 49, 50/1, 50/2, 51 से 54, 55/1, 55/2, 56 से 61, आबादी और सड़क।

ग्राम सिनहाला में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 73 (भाग), 74 (भाग), 75 (भाग), 76 (भाग), और नाला (भाग),।

ग्राम चन्दाला सुर्ली (खैरगांव) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 118 (भाग), 119, 120, 121, 122 (भाग), 123, 124 (भाग), और 125 (भाग),

ग्राम कोन्धी माल गुजारी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 36 (भाग), 38 (भाग), 131 (भाग), 134 (भाग), 135, 136, 137 (भाग), 138 (भाग), 139 भाग, 140, 141, 142 (भाग), 143, 163 और 164 (भाग) और सड़क (भाग) ।

ग्राम दुर्गापुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 1 से 14, 15 (भाग), 16 (भाग), 17 (भाग), 18, 19 (भाग), 31 (भाग), 32, 33, 34 (भाग), 35 (भाग), 36 (भाग), 38 (भाग), 39 (भाग), 40 (भाग), 41 (भाग), 42 (भाग), 43 (भाग), 44, 45 (भाग), 46 (भाग), 47 (भाग), 48 (भाग), 56 (भाग), 57 (भाग), 58 (भाग), 67 (भाग), 68 (भाग), 69 (भाग), 70 (भाग), 72 (भाग), 73, 74 (भाग), 75 (भाग), 76 (भाग), 77 (भाग), 82 (भाग) 83 (भाग), 102 (भाग), 103 (भाग), 104 (भाग), 105, 106 (भाग), 107, 108 (भाग), 155 (भाग), 156 (भाग), 207 (भाग), 208 (भाग), 209 (भाग) 210, 211, 212 (भाग), 313 (भाग) ।

ग्राम चेक कोन्धी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं० 32

सीमा वर्णन

क-ख-ग रेखा इरइ नदी के पूर्वी किनारे की बिंदु "क" से प्रारम्भ होती है और भागतः प्लाट सं० 2 के साथ-साथ और भागतः उससे होकर, प्लाट सं० 13 से होकर किताडी ग्राम में जाती है, सड़क पार करती है और तब प्लाट सं० 86 से होकर जाती है और प्लाट सं० 86 की पूर्वी सीमा पर बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा किताडी ग्राम में, प्लाट सं० 86 के साथ-साथ जाती है और तब पदमपुर ग्राम में जाती है और भागतः 71/3 से होकर और भागतः उसके साथ-साथ सड़क पार करती है और उसी प्लाट की दक्षिणी सीमा पर बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ-घ 1 रेखा पदमपुर में, प्लाट सं० 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70,3 आबादी के साथ-साथ जाती है, लोक निर्माण विभाग की सड़क को पार करती है और सड़क की पूर्वी सीमा पर बिन्दु "घ1" पर मिलती है ।

घ1-ङ रेखा पदमपुर ग्राम में, लोक निर्माण विभाग की सड़क की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-च रेखा पदमपुर ग्राम में, प्लाट सं० 142, 143/1, 144, 143/3, 134, 158 मोटा घाट नाला, प्लाट सं० 159, 126 से होकर जाती है और पदमपुर तथा सिनहाला ग्राम की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ रेखा सिनहाला ग्राम में, प्लाट सं० 76, 75, 74, 73 नाला से होकर जाती है और तब दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 45, 46, 70 72, 74, 75, 76 से होकर जाती है और दुर्गापुर तथा सिनहाला ग्रामों की सम्मिलित सीमा बिन्दु "छ" पर मिलती है ।

छ-ज रेखा दुर्गापुर और सिनहाला ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज-झ रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 77, 82, 83, 69, 68, 67, 46, 47, 48, 45, 43 और 42 से होकर जाती है जो का०आ० सं० 450 (अ) तारीख 4-8-79 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित किए गए दुर्गापुर खंड की उत्तरी सीमा भी है और दुर्गापुर तथा पदमपुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "झ" पर मिलती है ।

झ-ञ रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 42, 41, 40, 39, 38, 36, 35, 34 से होकर जाती है और तब कोन्धी मालगुजारी ग्राम में प्लाट सं० 164 से होकर जाती है जो का०आ० सं० 450 (अ) तारीख 4-8-79 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित किए गए दुर्गापुर खंड की उत्तरी सीमा भी है और कोन्धी मालगुजारी ग्राम के प्लाट सं० 164 और 163 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ञ" पर मिलती है ।

ट-ठ रेखा कोन्धी मालगुजारी ग्राम में प्लाट सं० 164 से होकर जाती है और तब दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 34, 35, 56, 58, 57, 102, 103, 104, 106, 108, 155, 156, 208, 207, 209, 212, 213 से होकर जाती है जो का०आ०सं० 150 (अ) तारीख 4-8-79 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित किए गए दुर्गापुर खंड की पूर्वी सीमा भी है और दुर्गापुर ग्राम के प्लाट सं० 213 में बिन्दु "ठ" पर मिलती है ।

ठ-ड रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 213 के साथ-साथ जाती है और दुर्गापुर तथा चेक कोन्धी ग्राम की सम्मिलित सीमा पर बिंदु "ड" पर मिलती है ।

ड-ढ रेखा चेक कोन्धी और दुर्गापुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और चेक कोन्धी ग्राम में प्लाट सं० 32 के साथ-साथ जाती है और तब दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 208, 156, 155, 108, 107 के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ढ" पर मिलती है ।

ढ-ण रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 19 के साथ-साथ प्लाट सं० 31 से होकर लोक निर्माण विभाग की सड़क पार करके जाती है और तब प्लाट सं० 19, 17, 16, 15 से होकर जाती है और दुर्गापुर तथा तथा कोन्धी मालगुजारी ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ण" पर मिलती है ।

ण-त रेखा कोन्धी मालगुजारी ग्राम में प्लाट सं० 164, 131, 133, 134, 137, 139, 138, 142, 38, 36 से होकर जाती है और तब प्लाट सं० 39, 40, 41, 42 से होकर मिनगांव ग्राम में जाती है और तब प्लाट सं० 124 125, 122, 118 से होकर चन्दाला, सुर्ला ग्राम में जाती है तथा उसी ग्राम में इरई नदी के पूर्वी किनारे पर बिन्दु "त" पर मिलती है ।

त-क रेखा चन्दाला सुर्ला मिनगांव, किताडी ग्रामों में इरई नदी के पूर्वी किनारे के साथ-साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19/61/83-सी० पुल०]
समय सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 17th January, 1984

S.O. 280.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal S.O. No. 2086 dated the 16th July, 1981 under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) published in the Gazette of India in Part II Section 3,Sub-section (ii) dated the 1st August, 1981, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 722.023 hectares (approximately) or 1784.16 acres (approximately) of the lands in locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal) No.S.O. 3279 dated the 9th August, 1983 under sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government specified a further period of six months commencing from the 1st August, 1983 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 609.64 hectares (approximately) or 1506.48 acres (approximately) in All Rights as described in the Schedule appended hereto;

Note—: The plan bearing No.C-1 (E)/III/JR/259-583 dated 12-5-83 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited person.

(Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra).

Note—2: Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the aforesaid Act, which provide as follows :

OBJECTIONS TO ACQUISITION :

"8 (1)—Any person interested in any land in respect of which a notification under Section 7 has been issued may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights or in or over such land.

Explanation: It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Competent Authority in writing and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note-3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

PADMAPUR BLOCK

WARDHA VALLEY COALFIELD

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

ALL RIGHTS (REVENUE LAND)

Sl. No.	Name of village	P.C. No.	Tahsil & District	Area in hectares	Remarks
1.	Kitadi	11	Chandrapur	42.23	Part
2.	Padmapur	11	,,	204.06	,,
3.	Mingaon	11	,,	105.46	,,
4.	Sinhala	11	,,	3.02	,,
5.	Chandala Surla (Khairgaon)	10	,,	12.24	,,
6.	Kondhi Malgujari	10	,,	90.77	,,
7.	Durgapur	10	,,	121.61	,,
8.	Check Kondhi	10	,,	0.15	,,
Total Revenue Land :				579.54 hectares (approximately) OR 1432.10 acres (approximately)	

SCHEDULE 'A1'

ALL RIGHTS (FOREST LAND)

Sl. No.	Name of village	P.C.No.	Tahsil & district	Kh. No.	Area in hectares		Remarks
1.	Kitadi	11	Chandrapur	86	12.91		Part
2.	Padmapur	11	,,	71	17.19		Part
				3			
Total Area :					30.10 hectares (approximately) OR 74.38 acres (approximately)		

Grand Total : 609.64 hectares (approximately)
OR 1506.48 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Kitadi : 2P, 3 to 5 6/1, 6/2, 7 to 12, 13P, 86P, Nallah P and Road P.

Plot numbers to be acquired in village Padmapur : 1 to 19, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21 to 40, 41/1, 41/2, 42 to 52, 53/1, 53/2, 54 to 70, 71/3P, 126P, 134P, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 137 to 139, 140/1, 140/2, 141, 142P, 143/1P, 143/2, 143/3P, 144P, 158P, 159P, Road P, Nallah P and Abadi.

Plot numbers to be acquired in village Mingaon : 1 to 28, 29/1, 29/2, 30 to 38, 39P, 40P, 41P, 42P, 43 to 49, 50/1, 50/2, 51 to 54, 55/1, 55/2, 56 to 61. Abadi and Road.

Plot numbers to be acquired in village Sinhala : 73P, 74P, 75P, 76P, and Nallah P.

Plot numbers to be acquired in village Chandala Surla (Khairgaon) : 118P, 119, 120, 121, 122P, 123, 124P, and 125P.

Plot numbers to be acquired in village Kondhi Malgujari : 36P, 38P, 131P, 133P, 134P, 35, 136, 137P, 138P, 139P, 140, 141, 142P, 143 to 163, 164P and Road P.

Plot numbers to be acquired in village Durgapur : 1 to 14, 15P, 16P, 17P, 18, 19P, 31P, 32, 33, 34P, 35P, 36P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44, 45P, 46P, 47P, 48P, 56P, 57P, 58P, 67P, 68P, 69P, 70P, 72P, 73, 74P, 75P, 76P, 77P, 82P, 83P, 102P, 103P, 104P, 105, 106P, 107, 108P, 155P, 156P, 207P, 208P, 209P, 210, 211, 212P, 213P.

Plot number to be acquired in village Check Kondhi : 32.

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B-C Line starts from point 'A' of the eastern bank of the River Erai and passes in village Kitadi through plot No. 13, partly along and partly through plot No. 2 crosses the Road then passes through plot No. 86 and meets on the eastern boundary of plot No. 86 at point 'C'.

C-D Line passes in village Kitadi along plot No. 86, then proceeds in village Padmapur acrosses the Road, partly through the partly along 71/3 and meets on the southern boundary of the same plot at point 'D'.

D-D1	Line passes in village Padmapur along plot Nos. 61, 65, 66, 67, 68, 69,70, 3, Abadi, crosses P.W.D. Road and meets on the eastern boundary of the Road at 'point D1'.
D1-E	Line passes in village Padmapur along the eastern boundary of the P.W.D. Road and meets at point 'E'.
E-F	Line passes in village Padmapur through plot Nos. 142, 143/1, 144, 143/3, 134, 158, Motaghat Nallah, plot Nos. 159, 126 and meets on the common boundary of villages Padampur and Sinhala at point 'F'
F-G	Line passes in village Sinhala through plot Nos. 76, 75, 74, 73, Nallah and then in village Durgapur through plot Nos. 45, 46, 70, 72,74, 75, 76 and meets on the common boundary of Villages Durgapur and Sinhala at point 'G'.
G-H	Line passes along the common boundary of village Durgapur and Sinahala and meets at point 'H'.
H-I	Line passes in village Durgapur through plot Nos. 77, 82, 83, 69, 68, 67, 46, 47, 48, 45, 43 and 42 which is also the northern boundary of Durgapur Bloch acquired under Section 9(1) of the CBA Act vide S.O. No. 450(E) dated 4-8-79 and meets on the common boundary of villages Durgapur and Padmapur at point 'I'.
I-J	Line passes in village Durgapur through plot Nos. 42, 41, 40, 39, 38, 36, 35, 34 and then in village Kondhi Malguzari through plot No. 164 which is also the northern boundary of Durgapur Block acquired under Section 9(1) of the CBA Act vide S.O. No. 450(E) dated 4-8-79 and meets on the common boundary of plot Nos. 164 and 163 of village Kondhi Malguzari at point 'J'.
J-K-L	Line passes in village Kondhi Malguzari through plot No. 164 and then in village Durgapur through plot Nos. 34, 35, 56, 58, 57, 102, 103, 104, 106, 108, 155, 156, 208, 207, 209, 212, 213 which is also the eastern boundary of the Durgapur Block acquired under Section 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 450(E) dated 4-8-79 and meets in plot No. 213 of village Durgapur at point 'L'.
L-M	Line passes in village Durgapur along plot No. 213 and meets on the common boundary of villages Durgapur and Check-Kondhi at point 'M'.
M-N	Line passes along the common boundary of villages Check-Kondhi and Durgapur and proceeds in village Check-Kondhi along plot No. 32, then proceeds in village Durgapur along plot Nos. 208, 156, 155, 108, 107 and meets at point 'N'.
N-O	Line passes in village Durgapur crossing P.W.D. Road through plot No. 31, along plot No. 19 and then through plot Nos. 19, 17, 16, 15 and meets on the common boundary of villages Durgapur and Kondhi Malguzari at point 'O'.
O-P	Line passes in village Kondhi Malguzari through plot Nos. 164, 131, 133, 134, 137, 139, 138, 142, 38, 36 and then in village Mingaon through plot Nos. 39, 40, 41, 42 and then in village Chandala Surla through plot Nos. 124, 125, 122, 118 and meets in the same village on the eastern bank of Erai River at point 'P'.
P-A	Line passes in villages Chandala Surla, Mingaon, Kitadi along the eastern bank of the Erai River and meets at the starting point 'A'.

[No. 19/61/83-CI.]

SAMAY SINGH, Under Secy.

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1984

शुद्धि पत्र

का०आ० 281 :—पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12016/8/82-उत्पा० दिनांक 16-2-1983 के अनु०आ०सं० 126(अ) के अधीन भारत सरकार के दिनांक 19-2-1983 के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ संख्या 1 से 3 पर प्रकाशित परिच्छेद 4 जो कि महाराष्ट्र राज्य के जिला रायगढ़, तालुका उरण के गांव नागांव, कालाधोंडा और चाकेडवीरा के लिये है।

	पढ़ें			के स्थान पर		
परिच्छेद 4	धारा 6 की उपधारा (1)			धारा 7 की उपधारा (1)		
गांव	सर्वेक्षण संख्या		क्षेत्र हे०आर०से०	सर्वेक्षण संख्या		क्षेत्र हे०आर०से०
नागांव	47	1	0–10–0	47	1	0–01–0
कालाधोंडा	23	1	0–06–0	23	1	0–06–5
चोकडविरा	112	3 33	0–06–8	112	3/33	0–06–3

[सं० 12016/8/82–उत्पादन]

विनय बंसल, निदेशक

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 13th January, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 281.—In the schedule appended to the notification of Govt. of India Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum)'s No. 12016/8/82-Prod. issued under section 6(1) of the Petroleum and Mineral Pipeline (ARUL) Act 1962 (50 of 1962) published under S.O. No. 176(E), dated 16-2-1983 at page Nos. 3 to 4 of the Govt. of India's Extraordinary Gazette dated 19-2-1983 part II section 3 sub-section (ii) for villages Nagaon and Bokadvira Taluka Uran, District Raigad, Maharashtra State.

Village	Read			For		
	S.No.	H.No.	H-Are-Centare	S.No.	H No.	H. Are-Centare
Nagaon	47	1	0—10.0	47	1	0—01.0
Bokadvira	112	1/23	0—26 0	112	1/23	0—06.0

[No. 12016/8/82-Prod.]
VINAY BANSAL, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1984

का० आ० 282.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नियम, 1957 के नियम 2 के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद के रजिस्ट्रार डा० विश्वनाथ शर्मा को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3, उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के एक सदस्य के निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या वी० 11013/27/83-एम० ई० (पी)]

प्रकाश चन्द्र जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 13th January, 1984

S.O. 282.—In pursuance of clause (d) of rule 2 of the Indian Medical Council Rules, 1957, the Central Government hereby appoints Dr. Vishwa Nath Sharma, Registrar, Rajasthan Medical Council as Returning Officer for the conduct of election of a member to the Medical Council of India under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) in the State of Rajasthan.

[No. V. 11013/27/83-M.E. (P)]
P. C. JAIN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1984

का० आ० 283.—केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारियों के पद पर नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और तदनुसार कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
1. मंडलीय वन अधिकारी विम्बरली गंज, दक्षिणी अंडमान वन प्रभाग	दक्षिणी अंदमान वन मण्डल के अधिसूचित इलाके की वन भूमि
2. मंडलीय वन अधिकारी, विम्बरली गंज, बारातंग वन मंडल	बारातंग वन मंडल के अधिसूचित इलाके की वन भूमि
3. मंडलीय वन अधिकारी लोंग आयलैण्ड मध्य अंदमान	मध्य अंदमान वन मण्डल के अधिसूचित इलाके की वन भूमि
4. मण्डलीय वन अधिकारी भाया-बन्दर, उत्तरी अंडमान	उत्तरी अंदमान वन मण्डल के अधिसूचित इलाके की वन भूमि
5. मण्डलीय वन अधिकारी कैम्पबैल खाड़ी निकोबार प्रभाग	निकोबार वन मण्डल के अधिसूचित इलाके की वन भूमि

[सं० 3-42/79 वन० स्था० 2(खण्ड 2)]

आर० एस० विष्ठ, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 6th January, 1984.

S.O. 283.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the table below, being gazetted officers of the Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of public premises specified in the corresponding entries in column 2 of the said table.

THE TABLE

Designation of Officer.	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1. Divisional Forest Officer. Wimberlygunj South Andaman Forest Division.	Forest land of notified area of South Andaman Forest Division.
2. Divisional Forest Officer. Wimberlygunj Baratang Forest Division.	Forest land of notified area of Baratang Forest Division.
3. Divisional Forest Officer., Long Island Middle Andaman.	Forest land of notified area of Middle Andaman Forest Division.
4. Divisional Forest Officer Mayabunder, North Andaman	Forest land of notified area of North Andaman Forest Division.
5. Divisional Forest Officer. Campbell Bay, Nicobar Division.	Forest land of notified area of Nicobar Forest Division.

[No. 3-42/79-FE. II (Vol.II)]
R.S. BHIST, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1984

का० आ० 284.—केन्द्रीय सरकार, वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसरण में प्रिंसिपल राजस्थान राज्य फलाईंग स्कूल जयपुर को उक्त नियमों के नियम 38 के खण्ड (क) में और उसकी अनुसूची 2 के अनुभाग ख में निर्दिष्ट छात्र पाइलेट अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत करती है और भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 11 सितम्बर, 1982 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3209 तारीख 17 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :

"4 प्रिंसिपल, राजस्थान राज्य फलाईंग स्कूल जयपुर।"

[फा० सं० ए० वी०-11012/9/80-ए]
नसीब सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 4th January, 1984

S.O. 284.—In pursuance of sub-rule (2) of rule of the Aircraft Rules 1937, the Central Government hereby authorises the **Principal,** Rajasthan State Flying School, Jaipur to grant or renew student pilot's licence referred to in clause (a) of rule 38 and in section B of Schedule II to the said rules, and make the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 3209 dated 17th August, 1982 published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 11th September 1982, namely :—

In the said notification, for serial No. 4 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely .—

"4. The Principal, Rajasthan State Flying School, Jaipur".

[F. No. AV.-11012/9/80-A]
NASIB SINGH, Under Secy.

संचार मंत्रालय

डाक तार बोर्ड

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1984

का० आ० 285.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने सुल्तानपुर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-2-84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-5/83/पीएचबी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T BOARD)

New Delhi, the 12th January, 1984

S.O. 285.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-2-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sultanpur Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-5/83-PHB]

का० आ० 286.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने संगारेड्डी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 28-1-84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-8/83 पीएचबी]

S.O. 286.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 28-1-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sangareddy Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-8/83-PHB]

नई दिल्ली, 13, जनवरी, 1984

का० आ० 287.—स्थायी [illegible] 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड (III) के पैरा (क)

के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने वलवनूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-2-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/84-पी० एच० बी०]

वेद प्रकाश भारद्वाज, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

New Delhi, the 13th January, 1984

S.O. 287.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1st February, 1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Valavanur/Minjur Telephone Exchanges Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/84-PHB]

V. P. BHARDWAJ, Asstt. Director Genl. (PHB)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1983

का० आ० 288.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षु और संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के निम्नलिखित अधिकारियों का जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित हैं, केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए स्तम्भ 3 में वर्णित पदाभिधानों के साथ उप शिक्षुता सलाहकार नियुक्त करती है, अर्थात्—

अनुसूची

क्रम सं०	धारित पद	पदाभिधान
1	2	3
1.	प्रशिक्षण उपनिदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर	उप क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
2.	प्रशिक्षण, उपनिदेशक शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता	उप क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
3.	प्रशिक्षण उप निदेशक शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास	उप क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
4.	प्रशिक्षण उप निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (पश्चिमी क्षेत्र) मुम्बई	उप क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार

[संख्या डी० जी० ई टी-1(6)/83 ए पी]

शशि भूषण, अवर सचिव,

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Directorate General of Employment and Training)

ORDER

New Delhi, the 29th December, 1983.

S.O. 288—In exercise of the powers conferred by Sub-tion (i) of section 27 of the Apprentices, Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby appoints the following officers of the Boards of Apprenticeship Training sponsored by the Ministry of Education and Culture, Department of Education mentioned in column 2 of the Schedule annexed hereto as Deputy Apprenticeship Advisers with the designations as shown in column 3 thereof to assist the Central Apprenticeship Adviser in the performance of his functions, namely —

SCHEDULE

Sl No	Post held	Designated
1	2	3
1	Deputy Director of Training Board of Apprehticeship Training, (Northern region) Kanpur	Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser
2	Deputy Director of Training Board of Apprenticeship Training, (Eastern region, Calcutta.)	Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser
3	Deputy Director of Training Board of Apprenticeship Training, (Southern region), Madras.	Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser.
4.	Deputy Director of Training, Board of Apprenticeship Training, (Western region) Bombay.	Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser.

[No. DGET-1(6/83-AP)

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

का० आ० 289.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2981 दिनांक 8 जुलाई, 1983 द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जुलाई, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि को छ : मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जनवरी, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस-11017/11/81-डी-1 (ए)]

एस० एच० एस० आयंगर, अवर सचिव

New Delhi, the 7th January, 1984

S.O. 289.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2981 dated the 8th July, 1983, the Bank Note Press, Dewas (MP) to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 15th July, 1983;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 15th January, 1984.

[No. S-11017/11/81-D. I(A)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984

आदेश

का०आ० 290.—मैसर्स दि स्टेट्समैन लिमिटेड, स्टेटसमैन हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व स्टेट्समैन कर्मचारी युनियन, स्टेट्समैन हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ने किया, दिल्ली प्रशासन के सुलह अधिकारी, श्री एस०पी० जोशी के समक्ष 8 जनवरी, 1971 को एक समझौता किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इन बातों की व्यवस्था है :—(i) तारीख 3 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित राष्ट्रीय अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को लागू करना, (ii) वर्ष 1970, 1971 और 1972 के लिए बोनस का भुगतान करना और (iii) कर्मकारों के ऐसे वर्गों के लिए वेतनमान आरंभ करना, जिन्हें राष्ट्रीय अधिकरण के पूर्वोक्त पंचाट में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है ।

और अब कर्मकारों के कतिपय वर्गों के समुचित स्थानन और सहवर्ती मंहगाई भत्ते की अदायगी के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया है और प्रबन्धतंत्र का दावा है कि ये कर्मकार समुचित समूहों / श्रेणियों में रखे गए हैं, जिनके वे हकदार हैं, जैसा कि उपाबन्ध "क" के स्तंभ 2 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, जबकि युनियन का यह तर्क है कि ये कर्मकार उपाबन्ध 'क' के स्तंभ 1 में उन कर्मकारों के सामने उल्लिखित समूहों/श्रेणियों में रखे जाने और उसमें यथावर्णित सहवर्ती मंहगाई भत्ते की अदायगी के हकदार हैं;

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवादों को राष्ट्रीय अधिकरण को भेजा गया था जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री आर० एन० भट्टाचार्य जिनका मुख्यालय कलकत्ता में था ।

और पूर्वोक्त न्यायमूर्ति श्री आर० एन० भट्टाचार्य की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 ख, धारा 33 ख की उपधारा (1) और धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री एम०पी० सिंह होंगे, जिनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और उक्त विवाद से संबंध कार्यवाही को न्यायमूर्ति श्री आर०एन० भट्टाचार्य, पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता से वापस लेती है और उसे न्याय-निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को स्थानांतरित करती है, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम०पी० सिंह होंगे ।

अनुसूची

(1) क्या मैसर्स दि स्टेट्समैन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र और स्टेट्समैन कर्मचारी युनियन द्वारा उठाए गए उपाबंध "क" में उल्लिखित तर्क को ध्यान में रखते हुए, उसमें निर्दिष्ट कर्मकार ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट और सुलह अधिकारी श्री एस० पी० जोशी के समक्ष 8 जनवरी, 1971 को हुए समझौते के अनुसार समुचित समूहों /श्रेणियों में रखे गए हैं, और यदि नहीं, तो ये कर्मकार किन समूहों/श्रेणियों में रखे जाने चाहिए और किस तारीख से ?

(2) क्या सहवर्ती मंहगाई भत्ता, जो वर्तमान में दिया जा रहा है, ऊपर निर्दिष्ट पंचाट और समझौते के अनुसार है, और यदि नहीं, तो क्या किसी उपान्तरण की आवश्यकता है ?

उपाबन्ध 'क'

स्टेटसमैन कर्मचारी युनियन का तर्क	स्टेटसमैन के नियोजकों का तर्क
1	2
1. (क) दोषपूर्ण रूप से फिट करना तीन यांत्रिक सर्वश्री भगवानदास नानक चंद और किशन को 190-8-238-15-328-द०रो०-20-388-रु० समूह-III (कारखाना) के वेतन मान के स्थान पर 175-7-217-12-301-द०रो०-20- 341 रु० के वेतन-मान में गलत ढंग से फिट किया गया। 1-1-1971 से गलत फिट किए जाने की बात को सुधारा गया और उन्हें समूह II (कारखाना) 210-8-258-15-348-द०रो०-20-408 रु० में रखा गया। 1-7-67 से 30-12-70 तक कर्मकारों को समूह III (कारखाना) में फिट किया जाना चाहिए और तदनुसार बकाया संदत्त की जानी चाहिए	ये मशीनमैन नौकरी विभाग में थ्रोटल यंत्र का प्रचालन कर रहे थे । ये यंत्र पंचाट के अधीन समूह-4 (कारखाना) में समूहबद्ध किए गए हैं।

1	2
(ii) ज्येष्ठतम होने पर भी श्री नेकराम, मशीनमैन चालक को समूह II (कारखाना) में श्रेणी पदोन्नत नहीं किया गया ।	श्री नेकराम को प्रोसेस विभाग में नियोजित किया गया है, न कि वाणिज्यिक मुद्रण विभाग में मशीनमैन के रूप में फिट किए जाने के समय उसके वास्तविक कार्य को ध्यान में रखा गया था ।
(ख) आठ कर्मकार सर्वश्री ई० दत्त, एन० आर० बरुआ, एन० के० बरुआ बानूखान, एस० पी० बरुआ, के० ए० थाकर, पी० के० बरुआ और बी०सी० डे को जिन्होंने 1-2-1967 से कास्टर के कृत्यों का निर्वहन किया और जो समूह II (कारखाना) 210-8-258-15-348-द० रो०20-408 रु० के वेतनमान में फिट किए जाने के हकदार है, दोषपूर्ण रूप से समूह III (कारखाना) में 190-388 रु० के वेतनमान में फिट किया गया है ।	इन आठ कर्मकारों का पदाभिधान पंचाट के अधीन समूह III (कारखाना) के अंतर्गत आता है। काम की प्रकृति स्टीरियो ब्लाक मैन की है, स्टीरियो कास्टर का कार्य अनुभाग का हैंडमैन करता है।
प्रोसेस विभाग	
(ग) श्री पी० एन० खन्ना उत्कीर्णक हाफटोन निक्षारक को 210-408 रु० समूह II (कारखाना) के स्थान पर 110-160 रु० समूह IV (कारखाना) वेतनमान दिया गया है। उन्हें 1-7-1967 से यह वेतनमान मिलना चाहिए।	श्री खन्ना का प्रोसेस विभाग में पदनाम मददगार के रूप में पदाभिहित है। रजिस्टर पर 9 हाफटोन निक्षारकों के नाम दर्ज है। वह केवल मात्र उनकी सहायता करता है।
(घ) प्रोसेस विभाग के श्री सतपाल को जो दोषपूर्ण रूप से समूह II (कारखाना) में फिट किए गए हैं समूह I (कारखाना) में 250-670 रु० के वेतनमान में 1-7-67 से फिट किया जाना चाहिए।	श्री सतपाल को केमरा प्रचालक के रूप में नियोजित किया गया है, और उन्हें समूह II (कारखाना) के अधीन ठीक ही फिट किया गया है। फोटो ट्रांसपैरसी का काम नगण्य है और उसके लिए पूर्णकालिक आदमी रखने की आवश्यकता नहीं है।
(ङ) श्री दयाचंद जैन और श्री पी० एन० खन्ना दोनों क श्रेणी के टंकक हैं। क श्रेणी के लिपिक और क श्रेणी के टंकक को समूह IV (प्रशासन) वेतनमान 190-374 रु० के स्थान पर 1-7-67 से समूह V (प्रशासन) में जिसका वेतनमान 250-660 रु० है, फिट किया जाना चाहिए। उन्हें ठीक जगह फिट किया जाना चाहिए और सही वेतन दिया जाना चाहिए ।	श्री दयाचंद और श्री पी० एन० खन्ना समूह VI (क) में टंकक के रूप में ठीक ही फिट किए गए है। उनका कार्य मात्र टंकण है और उसमें किसी भी प्रकार का आशुलिपिकीय कार्य शामिल नहीं है । समझौते के साथ प्राप्त पंचाट अधीन उचित वर्गीकरण किया गया है।
(च) श्री राम फल और श्री एमेनूयल सुखलाल जिल्दसाजों को समूह VII (प्रशासन) के स्थान पर जिल्दसाजी के समूह V (कारखाना) में 150-297-के वेतनमान में 1-7-67 से फिट किया जाना चाहिए और बकायों का संदाय किया जाना चाहिए।	श्री रामफल और श्री इमेनूयल सुखलाल दफतरी के रूप में नियोजित है और उसी रूप में पदाभिहित हैं। अनुभाग में कागज-पत्र या प्रलेखों की समुचित जिल्दसाजी की कोई व्यवस्था नहीं हैं।
(छ) श्री राम समुज सिंह को समूह VI (क) (190-374) की उनकी सही श्रेणी के स्थान पर समूह VIII (क) (110-160 रु०) में दोषपूर्ण रूप से फिट किया गया है ।	श्री राम समुज सिंह प्रेषण लिपिक के साथ लगा चपरासी है फ्रंकिंग यंत्र इसलिए लगाया गया है कि प्रेषण लिपिक डाक का द्रुत गति से निपटान कर सके। वह यंत्र का प्रचालन नहीं करता है। उसका प्रचालक तो लिपिक ही है।
(ज) सभी लेखा—लिपिकों को 190-374 रु० समूह VII (क) के स्थान पर 1967 से भूतलक्षी प्रभाव से 250-660 रु० समूह (क) का वेतनमान दिया जाना चाहिए।	लेखा-लिपिकों को कम्पनी के वेतनमानों के अधीन तीन समूहों (क) (ख) और (ग) में विभाजित किया गया था। ख और ग समूहों के लिपिकों को कनिष्ट लिपिक माना गया और उन्हें समूह VI (क) के अधीन फिट किया गया और क समूह के लिपिकों को कुशल माना गया और उन्हें समूह (क) के अधीन रखा गया।
(झ) दिल्ली के समाचार/विज्ञापन अनुभागों के प्रूफ शोधक पंचाट के गलत क्रियान्वयन से पीड़ित हो गए दिल्ली में जाब अनुभाग के प्रूफ शोधक और कलकत्ता के जाब और विज्ञापन रीडर आरंभ में 1-7-67 को समूह (III) कारखाना में फिट किए गए थे और 1-1-71 समझौते के अनुसार पुन: ठीक ढंग से रख दिए गए थे। किन्तु दिल्ली के समाचार/विज्ञापन अनुभाग के प्रूफ शोधकों को फायदे से इन्कार कर दिया गया इस प्रकार उन्हें मजदूरी में हानि हुई ।	प्रूफ शोधक समझौते के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध ख खण्ड (2) के अधीन आ गए और यह सहमति हुई थी कि उन्हें पंचाट के समूह V (कारखाना) में रखा जाएगा। पूर्ववर्ती फिटमैन पर न तो विचार विमर्श किया गया था और न ही समझौते के अधीन यह आता हैं।
II सेवा वेतन वृद्धि	
कुछ कर्मकार/प्रोसेस कर्मचारिवृन्द और लिपिकों को अब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर वे एक सेवा वेतन-वृद्धि के हकदार है और 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर दो वेतन वृद्धियों के हकदार हैं।	सेवा वेतनवृद्धि के लिए लेखे में ली जाने वाली सेवा अवधि उसी प्रवर्ग में, जिसमें कर्मकार फिट किए जाते समय नियोजित किया था, कार्य पर आधारित है ।
(क) लिपिक-जो वर्षों से समस्त कार्य करते रहे हैं, उन्हें क, ख और ग श्रेणी लिपिकों के रूप में कम्पनी की कृत्रिम नाम पद्धति में उनकी सेवा के अमान्य आधार पर वेतनवृद्धियां नहीं दी गईं । लिपिकों की सेवा को सेवा वेतनवृद्धियां देने के लिए विचार-गत किया जाना चाहिए, न कि कम्पनी की नाम पद्धति क, ख	प्रत्येक कर्मचारी को सभी सेवा वेतन मान वृद्धियां दी गई हैं।

1	2
और ग में उनकी सेवाओं को।	
(ख) प्रोसेस कर्मचारिवृन्द	
इसी प्रकार, प्रोसेस विभाग के कई कर्मकारों को सेवा वेतनवृद्धियां देने से इंकार किया गया है। लाइन निक्षारक और हाफ टोन निक्षारक के रूप में उनके काम की प्रकृति ट्रेड समान होते हुए भी, कम्पनी ने क श्रेणी कर्मकार के ख श्रेणी कर्मकार और ग श्रेणी कर्मकार के रूप में नाम पद्धति संलग्न कर दी है।	
(ग) श्री रतन लाल और श्री पुरी से प्रबन्धक वर्ग ने ए० पी० आई० प्रचालक और कनिष्ठ/करेक्टर दोनों के कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा की थी चूंकि उनकी सेवा केवल ए० पी० आई० प्रचालक के रूप में ही हिसाब से ली गई, अत: उन्हें सेवा वेतनवृद्धियां देने से इंकार किया गया है। उनकी कुल सेवा को हिसाब में लिया जाए।	
(घ) श्री शिव चरन मिसिर को इसलिए सेवा वेतनवृद्धि से इंकार किया गया है क्योंकि उसे हैडमैन के रूप में पदाविहित किया गया है, यद्यपि उसे समूह III (कारखाना) में फिट किया गया है।	
इसी प्रकार श्री स्वरूपा का पदनाम हैडस्वीपर रखा गया जिसका वेतन उसके अधीन काम कर रहे स्वीपरों से कम है।	
ख—दक्षता रोध—समझौते के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में दक्षता रोध लागू नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली कार्यालय में दो कर्मकार श्री एन्थोनी जैकब, मेकअप मैन पर्यवेक्षक और प्रोसेस विभाग के श्री भरतराम को 1971 में दक्षता रोध के आधार पर, दण्डात्मक रूप से वेतनवृद्धियां देने से इंकार कर दिया गया है। दक्षता रोध अधिरोपित करने के लिए प्रबंधक वर्ग को, पंचाट के अनुसार, प्रक्रिया अपनानी चाहिए, किन्तु इसमें उसका अनुसरण नहीं किया गया है।	श्री जैकब और श्री भरत राम को वेतनवृद्धियां देने पर विचार किया गया था। विभागीय रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि वे उच्चतर वेतनमान में दक्षकर्तव्यों पर लिए जाने के योग्य नहीं समझे गए। यदि यह मान भी लिया जाए कि दक्षता रोध की प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना लागू किया गया है तो भी समझौते या पंचाट के किसी उल्लंघन का अभिकथन नहीं किया जा सकता।
III. सहवर्ती मंहगाई भत्ता	
मंहगाई भत्ते पर प्रतिवर्ष पुनरीक्षा होनी चाहिए। 1 जनवरी, 1971 में प्रबंधक वर्ग ने 10 प्वाइंट का मंहगाई भत्ता संदत्त किया जब कि अंतर 15 प्वाइंट का था और कर्मकारों को शेष 5 प्वाइंट के लाभ से वंचित रखा गया।	मंहगाई भत्ते को पूर्ववर्ती 12 मास के औसत के आधार पर प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन पर आधारित, श्रमिक वर्ग के वर्ष 1965 उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अखिल भारतीय औसत के साथ संलग्न किया जाना होता है, यदि किसी विशिष्ट वर्ष के औसत में पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्वाइंट या अधिक की उपरिमुखी या अधोमुखी भिन्नता होती है :— निम्नलिखित वर्षों के लिए औसत: 1965 166 1966 184 1967 209 1968 215 1969 213 1970 224 प्रथम पुनरीक्षण 1968 में हुआ था। 1969 में सूचकांक 1967 की तुलना में 6 प्वाइंट बढ़ा, इसलिए पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता न थी : 1971 में पुनरीक्षण किया गया।

[संख्या एल-51011/33/74 आई०एण्ड ई०आई]

वॉ० एस० एलाघाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 9th January, 1984

ORDER

S.O. 290.—Whereas the management of Messrs. The Statesman Limited, Statesman House Connaught Circus, New Delhi, and its workmen represented by the Statesman Employees' Union, Statesman House, Connaught Circus, New Delhi had entered into a settlement before the Conciliation Officer, Delhi Administration, Shri S. P. Joshi, on 8th January, 1971 which inter-alia provided for: (i) implementation of the award of the National Tribunal, Calcutta published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd August, 1970. (ii) Payment of bonus for the year 1970, 1971 and 1972 and (iii) introduction of scales of pay for such categories of workmen which do not find place in the aforesaid award of the National Tribunal.

And whereas a doubt has now arisen with regard to the proper placement of certain categories of workmen and payment of linkage Dearness Allowance, the management maintaining that these workmen have been placed in proper groups/grades mentioned against these workmen in column each in column 2 of Annexure 'A', the union, however, contending that these workmen are entitled to be placed in groups/grades mentioned against these workmen in column 1 of Annexure 'A' and paid linkage Dearness Allowance as shown therein·

Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed were referred to the National Industrial Tribunal of which Justice Shri R. N. Bhattacharya was the Presiding Officer with headquarters at Calcutta.

And whereas the services of said Justice R. N. Bhattacharya are no longer available.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7B, Sub-section (i) of Section 33B and Section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a National Industrial Tribunal of which Justice Shri M P. Singh shall be the Presiding Officer with headquarters at Calcutta and withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Justice R. N. Bhattacharya, Presiding Officer, National Industrial Tribunal, Calcutta, and transfer the same for adjudication to the National Industrial Tribunal Calcutta, presided over by Justice Shri M. P. Singh.

SCHEDULE

(i) Whether in view of the contention raised by the management of Messrs The Statesman Limited and the Statesman Employees' Union as stated in Annexure 'A', the workmen detailed therein have been placed in proper groups/grades in pursuance of the award of the National Industrial Tribunal, referred to in para 1 above and settlement dated 8th January, 1971, before the Conciliation officer, Shri S. P. Joshi, and if not, in which groups/grades these workmen should be placed and from which date ?

(ii) whether the linkage Dearness Allowance which is being paid at present is in accordance with the award and settlement referred to above, and if not whether any modification is required?

ANNEXURE 'A'

Statesman Employees Union's Contention	Statesman Employers' Contention
1(A) Wrongful fitment	
Three mechanics Sarvashri Bhagwan Das, Nanak Chand and Kishan were wrongly fitted in the pay scale of Rs. 175-7-217-12-301-EB-20-341 awarded for group IV (factory) instead of pay scale of Rs. 190-8-238-15-328-EB-20-388 group III (Factory). From 1-1-1971 misfitment was rectified and they were placed in group II (Factory) Rs. 210-8-258-15-348-EB-20-408. From 1-7-67 to 30-12-70 the workmen should be fitted in group III (Factory) and paid arrears accordingly.	These Machinemen were operating Threadle Machines in Job Department. These mechanics are grouped in IV (Factory) under the award.
(ii) Shri Nek Ram, Machineman has not been upgraded to group II (Factory) being senior most.	Shri Nek Ram is employed in the Process Department and not as a Machineman in the Commercial Printing Department. At the time of fitment, his actual work was taken into account.
(B) Eight workmen Sarvashri E. Dott, N.R. Barua, N.K. Barua, Babu Khan, S.B. Barua, K.A. Walker, B.K. Barua & B.C. Dey who discharged functions of Stereo Caster and are entitled to be fitted in group II (Factory) in the pay scale of Rs. 210-8-258-15-348-EB-20-408- w.e.f. 1-7-67 have been wrongly fitted in Group III (Factory) in the pay scale of Rs. 190-388.	The designation of these eight workmen fall within Group III (Factory) unde the Award. Nature of work is that of Stereo Blockmen; work of Stereo Caster is performed by Headman in the Section.

1	2
Process Department	
(C) Shri P.N. Khanna engraver/half tone etcher has been given pay scale of Rs. 110-160 (Group IV Factory) instead of Rs. 210-408 (Group II Factory) should be given scale w.e.f. 1-7-1967.	Mr. Khanna is designated as helper in the Process Department. 9 half Tone Etchers are on roll. He only helps them.
(D) Shri Satpal of the Process Department should be fitted in Group I (Factory) in the scale of Rs. 250-670 w.e.f. 1-7-67 who is wrongly fitted in Group II (Factory).	Shri Sat Pal is employed as a Camera Operator, who is given Correct fitment under group II (Factory) Work of Photo transperency is of negligible order and a wholetime man is not required.
(E) Shri Daya Chand Jain and Shri P.N. Khanna both are 'A' grade typist. 'A' grade clerk and 'A' grade typist should be fitted in group V (Admn.) carrying pay scale of Rs. 250-660 instead of group VI (Admn.) (Pay scale of Rs. 190-374) w.e.f. 1-7-67. They should be correctly fitted and paid.	Shri Daya Chand & Shri P.N. Khanna have been correctly fitted as typist in group VI (A). Their work is of typing only and does not involve any element of stenography. Proper classification has been made under the Award received with settlement.
(F) Shri Ram Phael and Shri Emanuel Sukhlal Binders should be fitted in Binders Grade Factory V in Pay Scale Rs. 150-297 instead of Group VII (Admn.) w.e.f. 1-7-67 and paid arrears.	Shri Ram Phael and Shri Emanuel Sukhlal are employed as Daftries and designated as such. There is no arrangement for proper binding of papers or documents set up in the section.
(G) Shri Ram Samuj Singh wrongly fitted in Group VIII (A) (Rs. 110-5-160) instead of his rightful grade of group VI VI(A) (Rs. 190-374).	Shri Ram Samuj Singh is a peon attached to the despatch clerk. The franking machine has been placed to help the Despatch Clerk for quick disposal of dak. He is not operating the machine. The clerk is operator of its.
(H) All accounts clerks should be given the pay scale of Rs. 250-660 Group V(A) instead of Rs. 190-374 Group VII(i) with retrospective effect from 1967.	Accounts clerks were divided into three groups under the Company's pay scales (A, B & C). Clerks of B&C groups were considered junior clerks and were given fitment under the Group VI(A) and clerks of A scale were considered skilled and placed under group V(A).
(I) Proof Readers of the News/Advt. Section of Delhi are victims of mis-implementation of Award. Job Section Proof Readers in Delhi and Job and advertisement readers in Calcutta were initially fitted in group (III) Factory on 1-7-67 and re-fitted accordingly to settlement on 1-1-71 but Proof Readers of News/	Proof Readers were covered in the settlement specifically under Annexure 'B' clause (2) and it was agreed that they would be placed in Group V (Factory) of the Award. Prior fitment was neither discussed nor covered under the settlement.

1	2
Advt. Section of Delhi have been denied the benefit and thus have suffered loss in wages.	
II. Service Increment	
Some workers/Process Staff and clerks have not been granted their annual increment so far. They are entitled to one service increment for 5 years completed service and two increments for 10 years of service and above.	The service period to be taken into account for service increment is based upon the work in the same category in which the workman was employed at the time of fitment.
(a) Clerks– Have been performing similar duties for years have been denied increments on the untenable ground of their service in the Company's artificial nomenclatures as 'A', 'B' and 'C' grade clerks. The service of the clerks should be taken for giving service increments and not their services in company's nomenclature 'A', 'B' and 'C'.	Correct service increment have been given to each of the employees.
(b) Process Staff : Similarly several workmen of the Process Department have been denied service increments. Their nature of duties/trade such as Line Etcher and Half tone Etcher being the same company had appended its nomenclature such as 'A' grade worker 'B' grade worker and 'C' grade worker.	
(c) Shri Ratten Lal and Shri Puri were required by the management to perform the duties of both A.P.I. Operator and Junior/Corrector. They have been denied service Increments since their service as A.P.I. Operator only was taken into account. Their total service should be taken into account.	
(d) Shri Shiv Baarn Missir has been denied his service increment because he has been designated Headman though fitted in Group III (Factory). Similarly Shri Swarooopa has been desgignated as Head Sweeper who draws less than sweeper under him.	
(B) Ffficiency Bar	
E.B. should not be applied in the first year of the implementation of the agreement. In Delhi Office the Two workmen, Mr. Anthony Jacob, Make up man Supervisor and Shri Bharat Ram of the process Department have been vindictively singled out for the denial of increments in 1971 on grounds of T.B.	Mr. Jacob & Bharat Ram were considered for increment. Departmental reports showed they were not considered fit for taki on efficient duties in the higher scale. Even if it is held that the E.B. has been applied without observing the procedure no violation of the Agreement or the award can be alleged.
The procedure should be adopted by the management for imposition of E.B. according to award, but the same has not been followed.	
III. Linkage D.A.	
The D.A. should be revised every year. In January, 1971 management paid dearness allowance of 10 points when the difference was 15 points and deprived workers benefit of rest 5 points.	D.A. is to be linked up with All India Average for Consumer Price Index Number for the working class for the year 1965 based on 1st of each year on the basis of previous 12 months average; if the average of any particular year differs by 10 Points or more upward or downward of the previous year. Average for 1965—166 1966—184 1967—209 1968—215 1969—213 1970—224 The first revision took place in 1968. In 1969 index number rose by 6 points compared to 1967, therefore, no revision was necessary; in 1971 revision was given effect.

[L-51011/33/74-I&E(I)]

V. S. AILAWADI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984

का०आ० 291.—उत्प्रवास 1983 (1983 का 31) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम०एस० टांगरी, अनुभाग अधिकारी, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग), को 7-1-1984 से श्री एन०आर० पुंज के स्थान पर, उत्प्रवासी संरक्षक, दिल्ली के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० टी०-11017/1/83 इमीग्रेशन-II]

आर० के०दास, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 1984

S.O. 291.—In exercise of the power conferred by subsection (1) of section 3 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri M. S. Tangry, Section Officer, Ministry of Labour and Rehabilitaton (Department of Labour), New Delhi to be Protector of Emigrants, Delhi w.e.f. 7-1-1984 vice Shri N. R. Puni.

[No. T-11017(1)/83-EMIG.II]

R. K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984

का०आ० 292.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० 2316, दिनांक 10 जुलाई, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल। — केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त।

सदस्य

2. श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर। — राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति।
3. उद्योग संचालक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

4. श्री जी०के०चैन, कार्मिक प्रबन्ध, भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, मध्य प्रदेश टैक्सटाईल्स मिल एसोसिएशन (इन्दौर) नागदा, मध्य प्रदेश।
5. श्री एस० मिश्रा, कार्मिक प्रबन्धक, यूनियन कार्बाइड, काली पेरेड, बैरसिया रोड (फेडरेशन आफ मध्य प्रदेश चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज) भोपाल।
6. श्री हरी इशरानी, सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, 8, नवीन बाजार, जी०ई० रोड, रायपुर। — राज्यों में नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि।

7. श्री मंगी लाल जोशी, महामंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्रम शिविर, देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर।
8. श्री द्वारका प्रसाद पाठक, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (मध्य प्रदेश) 452, कोतवाली रोड, जबलपुर।
9. श्री सुरेश शर्मा, महा मंत्री, भारतीय मजदूर संघ (मध्य प्रदेश) 44/26, दक्षिण टी०टी० नगर, भोपाल। — राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि

[संख्या वी-20012/7/78 पी०एफ-2]

ए० के० भट्टाचारी, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 1984

S.O. 292.—In pursuance of sub-paragraph (1) of the paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 2316 dated the 10th July, 1975 the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Madhya Pradesh, consisting of the following persons, namely :—

CHAIRMAN

1. Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Bhopal. — Appointed by the Central Government.

MEMBERS

2. Labour Commissioner, Government of Madhya Pradesh, Indore.
3. Director of Industries, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. — Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.

4. Shri V.K. Jain, Personnal Manager, Bharat Commerce and Industries, Madhya Pradesh Textiles Mill Association (Indore), Nagda, Madhya Pradesh.
5. Shri S. Mishra, Personnal Manager, Union Carbide, Kali Parade, Barsia Road, (Federation of Madhya Pradesh Chamber of Commerce and Industries), Bhopal.
6. Shri Hari Ishrani, Secretary, Chhatishgarh Chamber of Commerce and Industries, 8, Navin Bazar, G.E. Road, Raipur. — Three representatives of the employers appointed by Central Government in consultation with, Organisations of employers in the State.

7. Shri Mangi Lal Joshi, General Secretary, Rashtriya Mazdoor Congress (Madhya Pradesh), Shram Sivir, Devi Ahalia Marg, Indore.
8. Shri Dwarka Prasad Pathak, Rashtria Mazdoor Congress, (Madhya Pradesh), 452, Kotwali Road, Jabalpur.
9. Shri Suresh Sharma, General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, (Madhya Pradesh), 44/26, South T.T. Nagar, Bhopal. — Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employees in the State.

[No. V. 20012(7)/78-PF.II]

A. K. Bhattarai, Under Secy.

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1984

का० आ० 293.—केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राक फास्फेट खानों के नियो-

जन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय है, निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के अवसान के पश्चात विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्तावों की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल	
मजदूर (पुरुष और महिला) चौकीदार क्लीनर, खलासी भूकंतक, वाहक (प्रस्तर), वाहक, पैट्रोलमैन, सफेदीवालावाला, पानी वाला, पानी ले जाने वाला, सफाईवाला सरफेस, मक्कर, भूमि के नीचे काम करने वाले मक्कर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल प्रकृति के हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	
खनक, ब्रेकर, ड्रिलर, भिश्ती, परिचर, रसोइया, आया, प्रधान चौकीदार, मुकद्दम, आयलमैन, पम्प खलासी शाट-फायरर प्रधान मिस्त्री, क्वारी मैन, खदान प्रचालक, स्टोर मैन, सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ सफाई वाला, लैंप बॉय, माली चपरासी, वार्ड बॉय, स्टाकर, वॉगलर मैन, पैचर, थुम्बा मैन, टिंडल, ट्राली मैन, जमादार, बैरा मेकमसैन, हेल्पर (लोको, क्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हमैर, मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) स्टोन कटर और ड्रेसर, चिजल मैन अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल	
लोहार, बढ़ई, कंपाउंडर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वेल्डर, विस्फोटक कर्ता, मशीनिस्ट उप-पर्यवेक्षक (अर्नाहित), सर्वेक्षक, पम्प प्रचालक, प्रचालक, मिस्त्री, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित) अन्य, प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
लिपिकीय	
लेखाकार, लिपिक, मुन्शी, स्टोर लिपिक, स्टोर इशुअर, (सामग्री) देने वाला। स्टोर कीपर (ग्रेड I तथा II) डेली लिपिक, टाइम कीपर, टूल कीपर, संगणक, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, नकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी को न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता, सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक या मार्गदर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक-बुद्धि की आवश्यकता है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों के उच्च-

ाम है वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

6. रॉक फास्फेट खान में काम करने वाला श्रमिक जो उत्खनन और रॉक फास्फेट अयस्क हटाने तथा इससे संबद्ध कार्य में लगा है, को "खनक" माना जाएगा।

[संख्या एस-32019/2/83-डब्ल्यू-सीएम डब्ल्यू]

बिशम्भर नाथ, अवर सचिव

(Department of Labour)

New Delhi, the 10th January, 1984

S.O. 293.—The following proposals made by the Central Government in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for fixing the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employment in Rock Phosphate Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal shall be taken into consideration after the expiry of 2 months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled :	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earth-cutter, Carrier (stone), Carrier, Petrolman, White Washer, Waterman, Water carrier, Sweeper, Surface Mucar, Underground Mucar, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground). Rs. 11.75 (for work below ground).
Semi-Skilled/unskilled supervisory :—	
Underground Miner, Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook,. Creche, Ayah, Head Chowkidar, Muccadam, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarry man, Quarry Operator, Storeman, Security Guard, Senior Sweeper, Lab. boy, Mali, Peon, Ward Boy, Stocker Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (Loco, Crane, Truck), Timber man, Jack Hammer, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Stone cutter and dresser, Chisel man, other categories by whatever name called are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground).
Skilled :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Supervisor, Head Cook, Engineman, Welder Blaster, Machinist, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyor, Pump Operator, Operator, Manson, Mate (with competency certificate under Mettaliferous Mines Regulations, 1961), other categories by whatever name called which are of Skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground). Rs. 18.00 (for work below ground).
Clerical :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store issuer, Store keeper (grade I and II), Tally clerk, Time keeper, Tool keeper, Computor, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are Clerical.	Rs. 15.00

Explanation :—For the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by Contractors also.

(3) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6) A worker in a Rock Phosphate mine who is engaged in extraction and removal of rock phosphate ores as well as in other incidental jobs shall be desiganted as a "Miner".

[No. S-32019/2/83-W.C. (M.W.)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.

S.O. 284.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 6 & 7 Pits Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st December, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD.

Reference No. 1 of 1983

In the matter of an industrial dispute under S. 10 (1) (d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :—

Employers in relation to the management of 6 & 7 Pits Jamadoba colliery of M/s. TISCO Ltd., P.O. Jamadoba District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :—

On behalf of the employers : Shri S. N. Sinha, Group Personnel Officer.

On behalf of the workmen : Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sang, Dhanbad.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.
14th December 1983.

AWARD

This is a reference under S. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour), New-Delhi by its order No. L-20012(303)/82-D. IR(A) dated 6-1-1983 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

1. "Whether the demand of the workmen of 6 and 7 Pits Jamadoba colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Ltd. that the workmen working in the Longwall section of the said colliery should be given Longwall allowance is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. "Whether the action of the management 6/7 Pits, Jamadoba colliery of M/s Tata Iron & Steel Company Ltd. in not making permanent the services of casual stone cutters/temporary workers working in the said colliery is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?'

Soon after the receipt of the reference notices were duly sent to the parties for filing written statements.

After a few adjournments, the parties filed a memorandum of settlement on 3-8-1983 I find that the settlement is beneficial to both the parties and accordingly I accept the same, and pass an award in terms of the settlement. The settlement will form part of the award as an annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer,

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2,

DHANBAD.

Reference No. 1 of 1983

PARTIES :—

Empoyers in relation to the Management of 6 & 7 pits, Jamadoba colliery of M/s. Tisco. Ltd.

AND

Their workmen represented by the General Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

That it is submitted that the Central Government, Ministry of Labour & Rehabilitation, New Delhi referred the following disoute by their Order dated 1-1-1983 to this Honourable Tribunal for adjudication :—

SCHEDULE

1. "Whether the demand of the workmen of 6 & 7 pits colliery of M/s. Tata Iron & Steel Company Limited., that the workmen working in the long wall section of the said colliery should be given longwall allowance is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. "Whether the action of the management of 6 & 7 pits, Jamadoba colliery of M/s. Tata Iron & Steel Company Ltd., is not making permanent the services of casual Stone Cutters/Temporary workers working in the said colliery is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

That the parties above named beg to submit that after detailed discussion and scrutiny of the papers, the dispute as mentioned in the item one of the schedule of the reference has been settled amicably in terms of a bi-partite settlement reached on 21-1-1983 between the parties which resolves the dispute fully, pending before this Honourable Tribunal for adjudication. A copy of the said settlement is enclosed.

That with regard to item 2 of the schedule of the reference, it is submitted that the union above named had served a strike notice for making permanent all temporary workers of collieries/departments including 6 & 7 pits, Jamadoba colliery. After prolonged discussion before the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad, by the parties above named, a Conciliation Settlement was arrived at amicably on 5-5-1983 which resolves the dispute pending before this Honourable Tribunal in terms of the settlement thereof. A copy of the said conciliation settlement its enclosed.

That the settlements so arrived at between the parties are fair.

It is, therefore, humbly prayed that no dispute Award may please be passed by the Honourable Tribunal in respect of the item 1 and 2 of the schedule of the reference.

FOR THE WORKMEN

FOR EMPLOYER
Sd. (Illegible)
Group Personnel Officer, 3-8-1983

Sd. (Illegible)
Secy. RCMS 6 & 7 Pits Colliery, 3-8-1983

MEMORANDUM OF SETLEMENT

(Form- 'M')

Representing the Management

(1) Sri R. Chawla,
Director of Collieries (J)
The Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
Post Office Jamadoba, Dist. Dhanbad,

(2) Sri D. V. Pichamuthu,
Divisional Manager (J),
The Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
P.O. Jamadoba, Dist Dhanbad.

Representing the workmen.

(1) Sri S. Das Gupta,
Jt. General Secretary,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.
Rajendra Path,
Dhanbad.

(2) Sri Varis Khan, Secretary,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.
Secretary,
6 & 7 pits branch,
P. O. Bhaga, Dist. Dhanbad.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Whereas the Union, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, 6 & 7 pits branch has demanded the revision of wage structure in respect of the workers working in the Longwall sections of 6 & 7 pits colliery, which was fixed earlier vide settlement dated 24th June, 1981 for panel No. VI.

Whereas the matter was being discussed, an industrial dispute was raised through a strike notice.

Whereas the matter was before the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad, separate discussions were also held between the parties to resolve the dispute.

Whereas the dispute before the Asst. Labour Commissioner (C), Dhanbad has also been referred to Central Government Industrial Tribunal No. II, Dhanbad for adjudication.

Mutual discussions were held on different dates and a settlement has been arrived at on 21-1-1982 on the following terms.

TERMS OF SETTLEMENT

(1) That the management suggested that the present system of engagement in Longwall section is not suited to the method of mining and should be changed to the concept of "All-men-all-jobs". The Union agreed to consider the proposal when the management is ready to introduce the system of "All-men-all-jobs" in the Longwall Section. Both the parties agreed that in that event the persons working in the Longwall section at present would be given the option to work in the changed system and suitable training would be imparted to them. Those persons who would not be interested in the changed system will go back to their substantive posts from where they were drawn prior to their placement in the Longwall section.

(2) That it was agreed that till the present system is changed to "All-men-all-jobs" basis, the rate of payment of wages to piece-rated miners/loaders will be on the following basis :—

(i) The minimum work load will be 0.5 cycle per shift per day in the bottom, middle & top lifts of panel V. B.

(ii) The following will be their basic rates on achieving the cycles on daily basis :—

(a) Cycle	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.00
Rupees	22/-	26/-	30/-	34/-	38/-	44/-

For an advance of every 0.1 cycle beyond 1 cycle the additional payment would be at the rate of Rs. 5 (Basic).

(b) The minimum (fall back) basic wages for piece-rated miners/loaders would be Rs. 22/- provided they are not able to achieve the minimum work-load due to no fault of theirs.

(iii) It was agreed that while the calculations for payments would be made on the basis of shift measurement, a check measurement will jointly be made on weekly basis and proportionate adjustments made on shiftwise performance.

(iv) The miners/loaders shall continue to get the dressing allowance on the same terms as mentioned in the settlement dated 14th June, 1981.

(3) That it was agreed that all categories of workers employed in the Longwall Section other than miners and loaders, shall be paid Longwall Allowance at a flat rate of Rs. 1-50 per day, so long as they continue to work in Longwall Section.

(4) That it was agreed that the present practice of engagement of workers in the Longwall section in different shifts according to exigencies of work shall continue.

(5) That it was agreed that all other provisions of the earlier settlement dated 24th June, 1981, which are not altered by this settlement shall continue to be operative.

(6) That it was agreed that the time-rated workers, other than the miners and loaders shall be paid the same basic wages as agreed in the settlement dated 24th June, 1981.

(7) That it was also agreed that 1 cycle would mean the following advances of the face :

(a) Panel V B (Bottom lift)—advance of the face by 4.125 ft (Length of the link bar) along the whole length with a face height of not less than 5 feet 7 inches (average face length 315 feet ± 5 feet) i.e. corresponding to 315 tonnes per cycle.

(b) Panel V B (middle and top lifts)—advance of the face by 4.125 ft. length of the link bar) along the whole length, with a face height of not less than 7 ft. (average face length 300 feet ± 5 feet) i.e. corresponding to 100 tonnes per cycle.

(c) In case due to certain reasons, 4.125 feet length link bars are not in use, the face shall be advanced by link bars of length of 3.25 feet which will entail pro-rata adjustment in respect of number of miners and production per cycle.

(8) That it was agreed that there would be no change in the system of incentive payments as agreed upon in the earlier settlement dated 24th June, 1981 and 16th April, 1982.

(9) That it was also agreed that when at times due to certain reasons, the engagement of Miners would go beyond the number fixed, and weekly advance of 1.5 cycles achieved, incentive money will be payable on the basis of the number of Miners fixed and this will be equally distributed amongst the total miners actually engaged. For example, if instead of normal engagement of 34/33 miners, a total of 40 miners were engaged, calculation of incentive will be in respect of 34/33 miners and the same will be distributed amongst 40 Miners.

(10) That it was also agreed that the Union would not press the dispute regarding Longwall Allowance before the Industrial Tribunal (Central) referred as schedule (B) of Reference No. 1 of 1983 and both the parties would pray for a NO DISPUTE AWARD by the Honourable Tribunal in view of the amicable settlement arrived at.

(11) That it was agreed that this settlement would be effective from 30-9-1982, the first date on which discussions were held at conciliation level.

Management Representatives | Union Representative

Sd/-
(R. Chawla)
Director of Collieries (J)

Sd/-
(S. Das Guppta)
Joint General Secretary

Sd/-
(D.V. Pichmuthu)
Divisional Manager (J)

Sd/-
Secretary
(Varis Khan)

WITNESSES

Sd/-
(R.T. Luther)
Chief Personnel Manager (J)

Sd/-
(Bali Ram)
President, 6 & 7 pits Branch

Sd/-
(N.D. Trehan)
Agent, Jamadoba Group of Collys.

Sd/-
(Ashique Khan)

Copy to the Secretary, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

Copy to the Chief Labour Commissioner (C), Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

Copy to The Regional Labour Commissioner (C), Government of India, Ministry of Labour, Dhanbad.

Copy to The Asst. Labour Commissioner (C), Government of India, Ministry of Labour, Dhanbad

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

का० आ० 295.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में जय भारत ग्राइंडिंग वर्क्स के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोट होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या भारत ग्राइंडिंग वर्क्स के प्रबन्धतंत्र का अपने कर्मकारों की सेवाओं को समाप्त करना तथा उनसे संबंधित कार्यस्थलों की तालाबन्दी न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के तथा किस तारिख से हकदार हैं।

[संख्या एल-29024(1)/83-डी3बी/डी० 3(ए)]

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1984

S.O. 295.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jay Bharat Grinding Works and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

"Whether the management of Jay Bharat Grinding Works are justified in terminating the services of their workmen & locking out the work place in respect of them? If not, to what relief are the workmen concerned entitled and from what date?"

[No. L-29024(1)/83-D.IIIB/D. III-A]

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1984

का० आ० 296.—भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भोवरा एरिया संख्या-3, मुकाम और डाक घर भोवरा, (धनबाद) के प्रबंधक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व सेक्रेटरी राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 30 दिसम्बर, 1983 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :—	1. महा प्रबन्धक, भोवरा एरिया, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड।
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	1. सेक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक)

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एस० एन० सहाय, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद-5, हीरापुर कार्यालय, धनबाद, डाकघर-औरा, जिला-धनबाद के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय

क्या प्रबन्धतंत्र द्वारा भूलनबरारी कोलियरी की श्रीमती बरणी मांझिन और 35 अन्य उजेली दर ओ० बी० आर० को सक्षम-दर-काम पर नियोजित न करने और उन्हें बरारी कोलियरी में वेगन लोडरों के रूप में स्थानांतरित करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	सेक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक) माइकल जौन समृति, भवन राजेन्द्र पथ, पोस्ट बाक्स-22 धनबाद-826001
	बनाम
	महा प्रबंधक भोवरा एरिया (बी०सी० सी०एल०) डाकघर-भोवरा जिला-धनबाद।

3. कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त है या यदि कोई संघ प्रश्नागत कर्मकार/कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम	सेक्रेटरी राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक)
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	36 कर्मकार
5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	36 कर्मकार

मध्यस्थ अपना पंचाट दो मास की कालावधि (यहां पक्षों द्वारा स्वीकार की गई अवधि निर्दिष्ट की जाए) या इतने और समय के भीतर देगा जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०/ महाप्रबंधक भोवरा एरिया नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	ह०/ सेक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

साक्षी

1. ह०/-अपठनीय
2. ह०/-अपठनीय

तारीख 19-12-83

[संख्या एल-24013/1/83-डी-4 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 13th January, 1984

S.O. 296.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Limited, Bhowra Area No. XI, At & P.O. Bhowra (Dhanbad), and their workmen represented by Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC).

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 30th December, 1983.

AGREEMENT

(Under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Names of the Parties :

Representing employers—The General Manager, Bhowra Area, Bharat Coking Coal Limited,

Representing workmen/workman—The Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Sri S. N. Hahay, Assistant Labour Commissioner (Central), Dhanbad-V, Office at Hirapur, Dhanbad, P.O. & District Dhanbad.

(i) Specific matters in disputes :

Whether the action of the Management of not regularising Smt. Banshi Mallik and 35 others piecerated O.B.R. of Bhulanbararee Colliery in Time Rated jobs and transferring them as Wagon Loaders to Bararee Colliery is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved :

The Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC), Michael John Smriti Bhawan, Rajendra Path, Post Box No. 22, Dhanbad-826001.

Vrs.

The General Manager, Bhowra Area (B.C.C.L.), P.O. Bhowra, District Dhanbad.

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workmen or workman in question.

The Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC).

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected : 36 workmen.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute : 36 workmen.

The arbitrator(s) shall make his (their) award within a period of two months (here specify the period agreed upon by the parties) or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties.

Sd/-

General Manager, Bhowra Area

Representing employer.

Sd/-

Secretary, R.C.M.S.

Representing Workmen

Witnesses :

(1) Sd/-

(2) Sd/-

[No. L-24013(1)/83-D.IV(B)]

New Delhi, the 10th January, 1984

S.O. 297.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Civil Engineering Department of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhawan, Post Office Koylanagar, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th January, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 119 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Civil Engineering Department of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Koyala Bhawan, P.O. Kovala Nagar Dist. Dhanbad

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri M. P. Baliase, Dy. CPM(O) East.

On behalf of the workmen—Secretary, Reshtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar. INDUSTRY . Coal.

Dated, the 31st December, 1983

AWARD

This is a reference under S. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), New Delhi by its order No. L-20012(190)/82-D.III(A) dated the 8th October, 1982 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Civil Engineering Department of M/s. Bharat Coking Coal Limited, at Koyala Nagar (Dhanbad) in stopping Sarvashri Prem Kumar, Jogeshwar Thakur, Kandar Parihar, Inderdeo Shaw, Rajendra Prasad, Ajay Sen and Ganga Prasad Mishra from their work with effect from the 9th December, 1981 and also in not paying to them wages as per the National Coal Wage Agreement-II is justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

Soon after the receipt of the reference notices were duly sent to the parties for filing written statement. Both the parties appeared and filed their respective statements. Thereafter several adjournments were granted by this Tribunal. Ultimately on 29-12-83 both the parties apeared and filed a memorandum of settlement. I find that the terms of settlement are fair and proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an award in terms of the memorandum of settlement. The settlement will form part of the ward as an annexure.

Memorandum of Settlement arrived at between the management of BCCL and their workmen represented by RCMS in respect of Ref. No. 119/82 S/Shri Prem Kumar and six others of Civil Engineering Department, Koyala Nagar, Dhanbad.

PRESENT :

For Management—Shri M. P. Baliase, Dy. Chief Personnel Manager (O) East.

For Union—Shri G. D. Pandey, Secretary, RCMS.

Short Recital of this case

The Union, RCMS, raised an Industrial Disputes before the RLC(C), Dhanbad for departmentalisation of 7 workers namely S/Shri (1) Prem Kumar (2) Jageshwar Thakur (3) Shikandra Parihar (4) Indradeo Shaw (5) Rajendra Prasad (6) Ajay Sen (7) Ganga Prasad Mishra, who were engaged for the job of construction in Civil Engineering Department during the period 1980 and 1981. The conciliation having failed, the matter was referred to for adjudication before the Central Govt. Industrial Tribunal No. II, Dhanbad. In the meantime the union/workmen approached for its amicable settlement and therefore, with a view to maintain Industrial peace and harmony, matter was discussed and it was settled amicably on the terms mentioned below :—

TERMS OF SETTLEMENT

(1) That is agreed that S/Shri Prem Kumar and 6 others, named above will be taken in employment w.e.f. the date they would report for duty, after the signing of the settlement, with an affidavit duly swered before the 1st Class Magistrate and two copies of passport size photograph with name, permanent home address and date of birth apearing on the chest.

(2) That the workman concerned in the case, will be appointed after proper verification and Medical examination in Cat. I pay scales of MCWA-II and will be designated as General Mazdoor.

(3) That since the matter has been settled amicably the question of payment of any dues or arrears whatsoever. Prior to the date of settlement shall not arise.

(4) That management shall be at liberty to verify the genuineness of all or any of the worman concerned and that in case any one is found ingenuine at any stage of time, the management shall take any action deemed fit under the circumstances including dismissal/removal from work and other legal action against the persons concerned.

(5) That the parties agreed to jointly file copies of the settlement before the Presiding Officer, Central Govt. Industrial tribunal No. II Dhanbad requesting for holding the terms of settlement as fair and passing award interims in terms of this settlement.

(6) That this settlement shall be registered under rules 58(4) of the ID Act (Central) Rules, 1957.

Management Representative	Union Representative
Sd/-	Sd/-
Shri M. P. Baliase,	Shri G. D. Pandey,
Dy. CPM(O) East.	Secretary, RCMS.
Witness :	Witness .
1. Sd/- Illegible	1. R. K Singh
2. Sd/- Illegible	2. Sd/- Illegible

Signatures of the concerned workmen

Sd/- Illegible

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(190)/82-D.III(A)]

New Delhi, the 12th January, 1984

S.O 298.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Automobile Workshop, Godhur of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th January, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (MP-2) DHANBAD

Reference No. 46 of 1982

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Automobile Workshop, Godhur of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen

APPEARANCES

On behalf of the employers—None.

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Dhanbad

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 2nd January, 1984

AWARD

This is an industrial dispute under S.10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No.L-20012(13)/82-D.III(A) dated 1st may, 1982 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

SCHEDULE

'Whether the demand of the workmen of Central Automobile Workshop, Godhur of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office kusunda, District Dhanbad that Sarvashri Sailendra Kumar Singh and Md. Muslim Ansari, Auto mechanics should be placed in category V with effect from the 1st August, 1979 is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. The case of the concerned workmen is that they were working in Central Automobile Workshop, Godhur. They were originally appointed as service men in category III in the year 1976. The management implemented the Coal Wage Board recommendation. They along with some other workmen were promoted as auto mechanics w.e.f. 1-8-79 by the office order dated. 1-8-79 (vide Ext. W.1). As per wage board recommendation the auto mechanics are entitled to category V and category VI. But the management with a malafide aim to victimise the concerned workmen has placed them in category IV w.e.f. 1-8-79 in violation of the mandatory provision of wage board recommendation, NCWA-I & II. The concerned workmen represented before the management against the illegal and arbitrary placing in lower category IV by drawing their attention to the provisions of the wage board recommendation and demanded category V w.e.f. 1-8-79. But their representation was not accepted. The minimum starting of workshop Auto machanic/Motor mechanic is category V. The Bihar Colliery Kamgar Union on behalf of Shri Osman Ansari challenged the wrong categorisation by raising an industrial dispute before the Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad and thereafter the management after appreciating the legal position placed Shri Osman Ansari in category V by entering into a conciliation settlement dated 26-6-81. S/Shri Karoo Prasad and Hassan Ansari were also placed in category IV which was challenged by Bihar Colliery Kamgar Union and the matter was referred to arbitration by Dy. Chief Labour Commissioner (C), Dhanbad. The arbitrator was pleased to pass an award in favour of S|Shri Karoo Prasad and Hassan Ansari by placing them in the minimum starting category V w.e.f. the date of appointment. The action of the management in placing the concerned workmen in violation of the mandatory provision of the wage board recommendation, MCWA-I and II was illegal, arbitrary, unjustified and against the principle of natural justice. The action of the management in denying category V to the concerned workmen was discriminatory in nature. The concerned workmen have, therefore, prayed for placing them in category V and passing an award in terms thereof with effect from 1-8-79.

3. The case of the management on the other hand, is that the concerned workmen were appointed as servicemen in category III and were attached to Central Automobile Workshop, Godhur in the year 1976. They were promoted in category IV w.e.f. 1-8-79 and were designated as auto-mechanics. The designation of servicemen and auto mechanics were not incorporated in the wage board recommendation and the designations were created by the management according to the job performed by them and the amount of skill possessed by them. There is provision for promotion of auto mechanics from category IV to category V and these persons after their promotion to category V are designated as motor mechanic, Grade II and as such they are also called auto mechanic category V. In the wage board recommendation there are two categories of motor mechanic, viz. grade I & grade II. During the period of private management there was no provision of engagement of service men or auto mechanic. After the establishment of Central Automobile Workshop for repairing and maintenance of large number of automobile vehicles, different types of workmen possessing different degree of skull were appointed for repairing and maintenance of motor vehicles. For the purpose of repairing of minor nature and for detection of ordinary fault auto mechanics were appointed in category IV, whereas for repairing and detection of major faults, auto mechanics in category V or category VI were employed. It is the management's function to give designation appropriate to nature of work performed by different workers. The wage board recommendation described the workmen as fitters in category IV and motor mechanics in category V and category VI. The management have described the fitters and motor mechanics as auto mechanics and they have been placed in category IV, V and VI. The fitters are performing the job of fitting and are placed in category IV and the auto mechanics engaged in the job of fitting and repairing are placed in category IV. The junior most and less experienced auto mechanics are placed in category IV and for performing the duties of fitters and repairing of minor nature and in the case of major repairing they work or assist in category V or VI. The concerned workmen after their promotion from service man in category III to auto mechanics in category IV are performing the duties of auto fitters and have actually been placed in category IV. The demand of the union for placing the concerned workman in category V w.e.f. 1-8-79, is without any justification.

4. The only question to be determined in this reference is whether the concerned workmen are to be placed in category V w.e.f. 1-8-79.

5. The workmen have exhibited Ext. W. 1 which is the office order dated 1-8-79 by which they along with some other workmen were promoted as auto mechanics. The said document is an admitted document. One of the concerned workmen viz. Mohd. Muslim Ansari has been examined as WW. 1. He has said that he along with other concerned workman Sri Sailendra Kumar Singh worked in Central Automobile Workshop, Godhur as auto mechanics. He has said that he along with Shri Sailendra Kumar Singh were originally appointed as service men in category III in the year 1976 and were promoted as auto mechanics vide office order, Ext. W. 1. He has further said that one Osman was also promoted as auto mechanic by the said office order, Ext. W. 1. and that the two concerned workmen and Osman were placed in category IV. It will further appear from his evidence that Osman raised an industrial dispute before the Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad for being placed in category V and that there was a settlement before the Regional Labour Commissioner (C) by virtue of which Osman was placed in category V w.e.f. the date of his promotion of the office order Ext. W. 1. He has further said that as motor mechanics their duties is to repair motor vehicles of different types and that he along with Shri Sailendra Kumar Singh were working in repairing of motor vehicles as motor mechanics. He has further reiterated that he and Shri Sailendra Kumar Singh do the same work which was being performed by Osman, Hassan Ansari and Karoo Prasad who have been already placed in category V. It will be relevant to refer the wage board recommendation. It will appear at Sl. No. 27, Page 49, Vol. II of the Coal Wage Board recommendation that motor mechanics have been placed in category V. From the job description stated in Sl. No. 27 it will appear that a workman having the general qualification of motor mechanic, Grade I but having less skill/experience and requiring some degree of guidance and supervision and placed as motor mechanic category V. I have looked into category IV but there is no mention of the fact that auto mechanic or motor mechanic is placed in category IV. Admittedly the management has accepted the recommendations of the Coal Wage Board and accordingly a workman who is performing the job of motor mechanic in accordance with the job description has to be placed in category V by the management. By the order Ext. W. 1 the management has admittedly designated the workmen as auto mechanic in category IV. The management has tried to show that the job of auto mechanics is of lower degree than that of motor mechanic and as such the workmen have been promoted in category IV from category III. It is said in the written statement of the management that the concerned workmen were placed in category IV as they were not found suitable for promotion to category V directly from category III

6. It will appear from the evidence of WW. 1 that they were performing the duties of motor mechanics as the description of their work was in accordance with the job description of a motor mechanic. The management has led no evidence to the effect that the workmen were not performing the duties as said by WW. 1. Even as per NCWA-II the auto mechanics have been placed in category V and the job description of auto mechanic is that he is capable of dismantling, the repairing and reassembling, petrol and disel engine and should be able to detect mechanical fault and rectifying the same independently. Thus, even by describing the workmen as auto mechanics as per Ext. W. 1 the management cannot get the advantage of placing the workmen in category IV. The workmen either described as motor mechanics or auto mechanics have to be placed in category V if the management takes the job as described above. It has therefore to be held that the management had no option to place the workmen in category IV and that the only category meant for their type of job is category V.

7. Ext. W. 1 shows that the two concerned workmen and Mohd. Osman as service men in category III were promoted as auto mechanics in category IV. WW. 1 has said that Osman raised an industrial dispute before the Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad for being placed in category V and there is settlement by virtue of which Osman was placed in category V with effect from the date of his promotion of the office order, Ext. W. 1, i.e. 1-8-79. The fact that Osman was placed in category V by virtue of settlement is not disputed. WW. 1 has said that he along with Shri Sailendra Kumar Singh and Osman used to do the same work such as changing of bushes and suspension and overhauling differentials and gear box. In view of the above, it will appear that Osman who was doing the same type of job was placed in category V and there is no reason as to why the concerned workmen should not be placed in category V.

8. Thus having considered all aspects of the case I hold the demand of the workmen of Central Automobile Workshop, Godhur of M|s. Bharat Coking Coal Limited. Post office Kusunda, District Dhanbad that S/Shri Sailendra Kumar Singh, Mohd. Muslim Ansari, Auto Mechanics should be placed in category V w.e.f. 1st August, 1979 is justified. Consequently, the concerned workmen are to be placed in category V w.e.f. 1-8-79 with all back wages and other emoluments.

This is my award.

I. N. SINHA, Presiding Officer.

[No. L-20012(13)/82-D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer.

New Delhi, the 13th January, 1984

S.O. 299.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 3, Dhanbad, in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri Yasin, Miner, TISCO's Jamadoba Colliery against the management of M/s. Tata Iron & Steel Company Limited, P.O. Jamadoba, which was received by the Central Government on the 3rd January, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Complaint Case No. 2/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Sri Yasin, Miner, T. No. 23283,
TISCO's Jamadoba Colliery,
C/o Mustaq, Haulage Khalasi,
No. 16 Colony, Ex-Gorakhpur Dhowra,
P.O. Jamadoba, Dist. Dhanbad ...Complainant

Versus

The Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
General Manager (Collieries),
Jamadoba, P.O. Jamadoba,
District Dhanbad ...Opp. Party

APPEARANCES :

For the Complainant—None.
For the Opp. Party—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar.

Dated, the 27th December, 1983

AWARD

This is a Complaint u/s. 33A of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 filed by Sri Yasin, Miner. His case is that during the pendency of Reference Case No. 12/79 in which the complainant is a concerned workman has been punished by way of suspension for 10 days with effect from 6th February, 1982 on the basis of a charge-sheet dated 19th January, 1981. It is submitted that the said action of the management is illegal as no approval has been obtained.

2. On behalf of the opp. party the defence is that Reference Case No. 12/79 was in relation to Coal Transport Workers of Jamadoba Colliery and the applicant being a miner is not a workman concerned in that Reference. It is also stated that the complainant was suspended for 10 days on proved misconduct after holding domestic enquiry against him and that Reference case has nothing to do with the complainant.

3. From the order-sheet it will appear that the complainant absented himself on several dates and did not come up for hearing though several fresh notices for hearing of the case were issued against him. On certain dates his representative Shri B. N. Sharma appeared but he was not ready to proceed with the case. From 7th September, 1983 the complainant started remaining absent on all the dates of hearing. Fresh notice was also issued to him but still neither he nor his representative appeared. Thus it is clear that the complainant is not interested in the case and that he has no evidence to prove that he is a concerned workman in Reference Case No. 12/79. The complainant has thus failed to prove the allegations made by him.

4. In such circumstances it is held that no provision of Section 33 of the Industrial Disputes Act has been violated by the opp. party and the complainant is not entitled to any relief.

5. The award is given accordingly.

[No. L-19014(2)/83-D.IV/B]

J. N. SINGH, Presiding Officer.

New Delhi, the 16th January, 1984

S.O. 300.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Poidih Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd January, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 60/81

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur Colliery of M/s. E.C.L., P.O. Dishergarh (Burdwan).

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers—Sri B. N. Lala, Advocate.
For the Workman—Sri D. Mukherjee, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 26th December, 1983

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the

dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(38)/81-D.IV(B) dated the 26th November, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of Agent, Poidih Colliery in superannuating Shri Dhumraj Pandey, Clerk of Poidih with effect from 1st July, 1981 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. The case of the workman is that he was born in 16th June, 1927 and he joined Colliery service at Poidih Colliery in 1945 at the age of 18 years and served in different services of the said colliery which was previously under Bengal Coal Company Limited. It is submitted that Form B registers are maintained under the Mines Act and Rules besides Provident Fund books and other form and registers are maintained under the Coal Mines Provident Fund Act. In both Form B register and Provident Fund Form his date of birth is recorded correctly as 1927, but the management ignoring the same superannuated him and stopped his work with effect from 1st July, 1981 which is unjustified, wrongful and illegal. He has therefore prayed that he should be reinstated with full back wages as he was retired before attaining the age of 60 years.

3. The defence of the management is that no dispute was ever raised with the management and the present Reference has arisen out of the representation made on 1st July, 1981 by the West Bengal Khan Mazdoor Sangh and so there is no industrial dispute between the employer and their workmen. On facts it is stated that the concerned workman Sri Dhumraj Pandey became the employee of the present management viz. Eastern Coalfields Ltd., with effect from 1st May, 1973 when the coal mines were nationalised and prior to that he was an employee of the erstwhile management Bengal Coal Co. Ltd. The concerned workman was appointed on 1st February, 1945 as Lamp Clerk at Poidih Colliery and he worked in different capacities there. It is stated that the Bengal Coal Co. Ltd., had been maintaining a service card of their employees and in the service card which bears the signature of the concerned workman his year of birth is recorded as 1921. As per said entry the concerned workman attained the age of 60 years and hence he was retired with effect from 1st July, 1981. It is submitted that in the Form B register manipulation has been made at the instance of the concerned workman. It is also stated that the concerned workman was also referred to the Age Determination Committee who also determined his age as 60 years and therefore the order of superannuation is legal, valid and justified. It is prayed that the Reference be decided in favour of the management.

4. The point for consideration is as to whether the action of the management in superannuating the concerned workman with effect from 1st July, 1981 is justified. If not, to what relief is he entitled.

5. It is not denied that age of retirement in the colliery has been fixed at 60 years. It is also not denied that as per circular issued by the authority in cases where no date of birth is given and only year of birth is known the 1st July is to be considered the date on which a person is superannuated on attaining the age of 60 years. In this particular case we have to see as to whether the superannuation of the concerned workman is proper and justified or not. In this connection the first document to be considered is the Form B register which was prepared by the erstwhile management viz. Bengal Coal Co. which was prepared in the year 1960. The name of the concerned workman appears at Sl. No. 536. In the column of age 42 has been written but from a very look and a close scrutiny of this entry it will appear that originally a different year was written on it but that has been erased and the letter 42 is written. It is on this basis that the management did not rely on Form B register and placed reliance on other documents which are more authentic. Ext. M-2 is the photostat copy of the service card of the concerned workman prepared by the erstwhile management in the year 1957. In this document the year of birth is 1921 and it bears the signature of the concerned workman also.

6. In this connection it may be stated that from the record it appears that the management had filed the original service card in this case but subsequently it was taken back on the ground of getting photostat copy of the same. The Secretary handed over the original service card for preparing photostat copy and thereafter the original service card was returned back to the Secretary and an endorsement to that effect was taken by him on the application itself. The said original service card is missing from the record and it is contended that it was surreptitiously taken away by somebody while inspecting the record. The Secretary, however, has been asked to be careful in future and a direction has been issued that inspection of records will be made in presence of the Secretary or other responsible staff of the Court. The photostat copy, however, clearly shows that the year of birth is 1921 and there is nothing to show that there is anything wrong in this entry. It admittedly bears the signature of the concerned workman and was prepared in ordinary course of business. The next document is the increment list prepared by the management in the year 1972. It was prepared by Industrial Business Machine. It is a very old document and entry No. 40493 is in respect of the concerned workman. In this also year of birth is 1921. Thus the service card as also the increment list Ext. M-2 and Ext. M-3 respectively clearly indicate the year of birth as 1921. Besides this it will appear that the concerned workman was also sent to the Medical Board for determination of his age. Ext. M-12 is the report of the Age Determination Committee and it shows that on the date of his examination he was above 60 years. MW-2 is Dr. M. N. Mukherjee, Area Medical Officer who was one of the members of the Age Determination Committee. He has stated that he examined the concerned workman and found him above 60 years. It will, however, appear that on this report originally 59 years had been written which was later converted into 60 years. The Doctor has explained this fact in his deposition. In paragraph 14 he has stated that the workman requested them to write 59 years so that he can work for a year more and so the committee wrote 59 years originally, but the decision was changed after fresh consultation. This, however, does not make any difference being 59 or 60 years as it does not tally with the age as stated by the concerned workman.

7. As against this the concerned workman has placed reliance on Ext. W-1 which is Form A of the Coal Mines Provident Fund and in this the date of birth of the concerned workman as recorded is 16-6-1927. The contention of the managemtnt is that this document has been prepared subsequently at the instance of the concerned workman. This form is printed in green ink. It will appear that the bottom portion of the right hand side of this form has been torn away. On the bottom of the right hand side of the back page of such forms the year of printing is printed which will appear from a similar blank form filed by the management. This form would show that this type of form was printed on 4th November, 1959. The writings on Ext. W-1 are of the year 1949 and it was contended on behalf of the management that Ext. W-1 was prepared sometime in the year 1959 or afterwords. The workman in his evidence has admitted that he was for sometime dealing with Provident Fund record which will also appear from Ext. M-13 which is the old Provident Fund register in which also the age has been subsequently written as 1927. Further it will appear that the same printing mistake which is in Ext. M-11 is also in Ext. W-1 on page 2 where declaration is printed. The last word on the fourth line is name and thereafter there is semi-colon and thereafter the letter 's' is written and a dash is given. The same printing mistake is on Ext. W-1. This clearly indicate that both these forms were printed at one time in the year 1959. The management has also filed specimen copy of Form A which was in use in the year 1949-50 and has been marked Ext. M-11/1. There is no such printing mistake in this form and it shows that it was prepared in the year 1949-50. Thus it is clear that Ext. W-1 is not a genuine document but was brought into existence subsequently at the instance of the concerned workman. The last document filed on behalf of the workman is Ext. W-2 which he claims to be his school leaving certificate. This appears to have been issued to him in the year 1943 and is dated 17-1-1943. From a very look of this certificate it will appear that the writings on it are quite fresh and further there is some over-writing in the date of birth recorded in it. The admission register of the school has not been filed to show that the entry made in this school leaving certificate is correct. In such circumstances no reliance can be placed on Ex. W-2 also. There is nothing to disbelieve the

service card as also the increment list which clearly mentioned the year of birth as 1921 and which is also supported by the report of the Medical Board.

8. The management has adduced one more circumstantial evidence against the case of the concerned workman. It is admitted that the son of the concerned workman Bikrama Pandey is also an employee in this very colliery since the time of the old management. Entry No. 40078 in the increment list (Ext. M-3) mentions the name of the son of the concerned workman and his year of birth has been shown as 1938. Now if the year of birth of the concerned workman is 1927 as contended by him then he could not have got a son at the age of 11 years only. The workman in his evidence, however, has stated that the age recorded regarding his son is wrong but it is not believable that the old management would record the age of both father and son wrongly. MW-1 is Sri P. N. Goswami, Sr. Personnel Officer who has stated that the concerned workman has been rightly superannuated on attaining the age of 60 years. He has further stated that there is erasion in the Form B register which was prepared in the year 1960. The concerned workman WW-1 has no doubt stated that his age was wrongly recorded but it is not supported from the evidence and circumstances discussed above. The service card of Bikrama Pandey has also been filed and has been marked Ext. M-9 and in that card also the age recorded is 1938. There is nothing to disbelieve the genuineness of this document.

9. Considering these I hold that the year of birth of the concerned workman is 1921 and so he was rightly retired from 1-7-81 on attaining the age of 60 years.

10. Considering the entire evidence on record and facts and circumstances of the case, I hold that the action of the management in superannuating the concerned workman with effect from 1-7-81 is legal, valid and justified and in the circumstances the concerned workman is not entitled to any relief.

11. The award is given accordingly.

[No. L-19012(38)/81-D.(IV.B)]
J. N. SINGH, Presiding Officer

New Delhi, the 13th January, 1984

S.O. 301.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on the 3rd January, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NEW DELHI

I.D. No. 167 of 1981

In the matter of disputes between :

Shri Satish Puri,
16/47, Gali No. 1.
Dr. Joshi Road,
Karol Bagh, New Delhi-5.

AND

The Medical Superintendent,
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital,
New Delhi.

APPEARANCES :

Workmen in person.
Mr. Narinder Chaudhary—for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-42012(28)/81-D. II(B), dated 15th November, 1981, made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in terminating the services of Shri Satish Puri Physiotherapist with effect from 8-12-1980 (AN) is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. Mr. Satish Puri joined as Physiotherapist in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and worked there during the period from 28-1-80 till 9-2-80. He worked in the scale of Rs. 455—700 with total emoluments of about Rs. 873 per mensum.

3. The workman claimed that he was not given any retrenchment compensation and that he was entitled to that compensation and for that reason, the termination of his service was in contravention of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 and is entitled to reinstatement in service with full back wages.

3. The Management of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital contested the claim and asserted that the Labour Court had no jurisdiction because the applicant-workman was not a 'workman' and, on merits, it was pleaded that the employment offered was purely temporary and on adhoc basis and that the post was reserved for a scheduled tribe candidate. The behaviour of Mr. Satish Puri was said to be not satisfactory and he was said to be habitual late-comer. The Medical Superintendent ordered termination of service on enquiry conducted by the Deputy Medical Superintendent where he was found guilty.

4. The evidence of Shri T. R. Kapoor, Office Superintendent and of the workman has been recorded. I have heard the arguments of the Management's representative and the workman.

5. That Dr. Ram Manohar Lohia Hospital is an 'industry' as the term is defined in the Industrial Disputes Act, 1947 is unquestionable on the ground of current definition of 'industry' accepted by the Supreme Court Since Bangalore Water Supply and Sewerage Board's case. That Mr. Satish Puri as a Physiotherapist was a technical employee included in the term 'workman' is again unquestionable. He had served for more than 240 days in the year 1980 and Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 was breached in his case.

6. However, relief cannot be given to Mr. Satish Puri by way of reinstatement in service, since the job is held by Mrs. Shabarkada since 25-6-1981 and she is a Scheduled Tribe candidate; the vacancy is meant for Scheduled Tribes.

7. In respect of his claim for back-wages, for the period 9-12-80 till to-date, nothing need be paid to him because he has already got by way of wages in England more than Rs. 1 lac, for the period from July 10, 1982 till August, 1983. If he paid 50 percent of that amount by way of tax, he still got more than Rs. 50,000, a figure higher than his wages' claim for the period December 1980 to December, 1983—amounting to Rs. 24,000 only. The result is that the workman is held entitled to no relief even though the termination of service was technically in violation of the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

8. The award is made in the terms aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

December 19, 1983.
Nangia

[No. L-42012(26)/81-D. II(B)]
O. P. SINGLA, Presiding Officer

New Delhi, the 16th January, 1984

S.O. 302.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of E.S.I. Corporation Indore (MP) and their workman which was received by the Central Government on the 30th December, 1983.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.), PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

Case No. CGIT/LC(R)(50) of 1982

Employers in relation to the Management of E.S.I. Corporation, Indore (MP).

AND

Their Workman (Mahadeo Rode).

PRESENT :

Mr. H. N. Upadhyay, Advocate and Shri A. K. Upadhyay, Adovacate—for the workman.

Mr. R. P. Johri, Advocate—for the Management.

INDUSTRY : Insurance.
DISTRICT : Gwalior
STATE : M.P.
Date of decision . 20-12-1983.

AWARD

This matter arises out of reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act) made by Central Government for adjudication of a dispute pertaining to termination of services of Shri Mahadeo Rode, Peon in the service of E.S.I. Corporation, Gwalior. By notification No. L-15012(2)|81-D.II. (B) dated 13-8-1982, the Central Government referred the dispute in the following terms :—

"Whether the action of the Regional Director, E.S.I. Corp., Indore in terminating the services of Shri Mahadeo Rode, Peon, E.S.I. Local Office, Tansen Road, Gwalior with effect from 16-12-1979 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

The facts in this case are not much in dispute except for contentions here and there. Mahadeo Rode was appointed as a Peon in the service of E.S.I. Corporation as a daily waged worker. No written orders appointing him were made. He applied for being given the post of Peon. His application was considered and he was appointed by an order dated 20-10-1978 for a period from 3-10-1978 to 2-1-1979. The appointment order expressly stated that the appointment was temporary and the appointment will cease on he expiry of the period. It was also stated in the order that his appointment was subject to such terms and conditions as laid down in the offer of appointment issued. He was appointed on a monthly initial pay of Rs. 196 P.M. in the pay scale of Rs. 196-3-220-EB-3-232 plus allowances as admissible under the rules of the Corporation. Finally, it was stated in the order that the appointment was made on a clear understanding that the services could be terminated at any time without assigning any reason therefor and that he will have no claim for continuance on regular basis.

After an interval of a few days on the expiry of the above period, he was given a second appointment letter dated 10-1-1979 for the same job of a Peon for a period commencing 4-1-1979 to 3-4-1979. The terms of appointment were the same as before. Then again on the expiry of the second term, he was given an appointment for a third term by an order dated 18-4-1979 for the period from 6-4-1979 to 5-7-1979. It appears that the person making the appointment did not have power to make appointment for more than three months. Therefore, when Rode was given appointment for the fourth term on 27-7-1979 for a period from 23-7-1979 to 22-10-1979, it was mentioned in the appointment letter that his earlier order would be deemed to be only up to 2-7-1979 instead of 5-7-1979. This was with a view to regularise the appointment as it could not be said that the order made was in excess of powers or void on account of the fact that the person appointing him had no valid authority to appoint him for more than 3 months. When Rode was running his fourth term of appointment, his services were terminated w.e.f. 3-9-1979 in terms of the order of appointment without any notice or without assigning any reason. Thereafter Rode was again appointed on daily rated basis whenever there was any need for work in the office. Thus he worked on daily wages between 12-9-1979 to 25-9-1979, 12-11-1979 to 15-11-1979 and 5-12-1979 to 15-12-1979. On 15-12-1979 he was asked finally not to come to the office as his services were not required at all. It is after this that Rode sought to raise the dispute through his Union.

His contention is that in terms of section 25-F of the Act, he has been in continuous employment for more than 12 months and, therefore, his services could not be terminated without observing the formalities and the requirements of section 25-F of the Act. His services have not been terminated because of any punishment being given as a result of disciplinary proceedings or because he reached the age of superannuation. His contention is that the termination of his services would constitute retrenchment under section (2-00) of the Act. It would constitute retrenchment if his services had been terminated for any reason whatsoever save exceptions provided in the section itself. His case was not covered by any of the excluded cases namely where the termination is by way of punishment inflicted by way of disciplinary action, or voluntary retirement of the workman on reaching the age of superannuation or on the ground of continued ill-health. It is also not the case of the management that the termination in the instant case was as a punishment inflicted by way of disciplinary action or because of continued absence on account of ill health. Therefore, the only question that has to be seen is whether the termination amounted to retrenchment and whether the management has complied with the conditions laid down in section 25-F of the Act ? If not, what would be the effect of the non-compliance of such requirements and the relief if any to which the workman was entitled.

The applicant had actually worked for the periods mentioned in the three tables below. The first table consists of the period when the workman was appointed on daily wages for which there was no regular order of appointment. The second table gives the details of the four appointments when the workman had worked as Peon on monthly rated basis for fixed periods as contained in the four appointment letters. As already stated above, during the subsistence of the fourth period, his services were terminated w.e.f. 3-9-1979. Lastly there is the third table when the workman had worked on daily wages after termination of his services on 3-9-1979 for which there was no written order of appointment.

Table I :

Period From	To	No. of days
Appointment on daily wages		
28-4-78	16-5-78	19
20-5-78	17-6-78	29
20-6-78	17-7-78	28
18-7-78	17-8-78	30
19-8-78	16-9-78	29
19-9-78	2-10-78	14

Table 2 :

Regular Appointment :

3-10-78	2-1-79	92
4-1-79	3-4-79	90
6-4-79	5-7-79	91
23-7-79	22-10-79	40

(services terminated on 3-9-79)

Table 3 :

Appointment again on daily wages :

12-9-79	25-9-79	14
12-11-79	15-11-79	4
4-12-79	15-12-79	12
	Total :	498 days

In terms of section 25-F of the Act, no workman who has been in continuous service for not less than one year under the employer, shall be retrenched by that employer until : (a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice : provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service; (b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and (c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette.

It is incumbent on the workman to show that he has been in continuous service for not less than one year under the particular employer who had retrenched him from service. The workman's services were finally terminated on 15-12-1979, and counting the number of days he worked within the period of 12 months from the date of termination, they would come to more than 240 days. Even if his service is taken to have been terminated on 3-9-1979, he had worked for more than 240 days within a period of 12 months from the date of termination and the sole question is whether he could be said to be in continuous employment for not less than one year from the date of termination? The Management merely seeks to rely on the fact that the appointments of Rode were specifically for three months each time and there was break in the subsequent appointments. The appointing authority was powerless to appoint him for more than 3 months and each time he had been given appointment, therefore, there had been a break in service with gaps of 2 or 3 days in between, and therefore, he could not be said to be in continuous employment. It was pointed out that continuous employment would be then the workman had the right or by a letter of appointment, given a right to work for a period of 12 months and that when he had within that period actually served for more than 240 days. The right to continue in employment expired at the end of the order of appointment and, therefore, the management contends that he had not been in continuous employment for a period of 12 months.

Section 25-B defines the expression 'continuous service'. As far as sub-section (1) of section 25-B is concerned, it could legitimately be said as contended by the management that the workman had not been in continuous service because his employment was interrupted However, sub-section (2) clearly covers his case. Sub-section (2) reads as under :-

> "Where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer—
>
> (a) for a period of one year, if the workman, during a period of 12 calendar months preceding the date w.r.t. which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—
>
> (i) 190 days in the case of a workman employed below ground in a mine; and
>
> (ii) 240 days, in any other case;
>
> (b) for a period of six months, if the workman, during a period of six calendar months proceding the date w.r.t. which calculation is to be made has actually worked under the employer for not less than—
>
> (i) ninety-five days, in the case of a workman employed below ground in a mine; and
>
> (ii) 120 days, in any other case.
>
> Explanation—for the purposes of clause (2) the number of days on which a workman has actually worked under an employer shall include the days on which—
>
> (i) he has been laid-off under an agreement or as permitted by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 or under this Act or under any other law applicable to the industrial establishment;
>
> (ii) he has been on leave with full wages, earned in the previous years;
>
> (iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out and in the course of his employment; and
>
> (iv) in the case of a female, she has been on maternity leave; so, however, that the total period of such maternity leave does not exceed 12 weeks."

Under sub-section (2) the workman need not be in continous service within the meaning of sub-section (1) for a period of one year but he will be deemed to be in continuous service under an employer for a period of one year if the workman during the period of 12 calendar months just preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under that employer for not less than 240 days. The position is now settled and no longer open to doubt by the decisions of Supreme Court. In Mohan Lal v. Management of M/s. B.E.L. AIR 1981 SC 1253, their Lordships observed that sub-section (2) specially comprehends a situation where a workman is not in continuous service. The contentions raised by the management were repelled in this case. The earlier decisions under the old law were no longer applicable. This has been fully discussed in para 13 of the above judgment. Their Lordships then quoted Chinnappa Reddy J's observations as under :

> "These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a workman who has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period 12 months shall be deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months. it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."

Similarly, Pathak J's observations in the concurrent judgment were also quoted as under :—

> "In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of Section 25B(2). Therefore, both on principle and on precedent it must be held that Section 25B(2) comprehends a situation where a workman is not in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12 calendar month commencing and counting backwards from the relevant date, i.e., the date of retrenchment. If he has he would be deemed to be continuous service for a period of one year for the purpose of Section 25B and Chapter VA."

The above observations would clearly indicate that it was no longer necessary that the workman should have had a right under the appointment letter to work for a period of 12 months before his tenure could be said to be continuous within the meaning of section 25-F of the Act. What was required was whether the workman had actually worked for 240 days within a period of 12 months going backwards from the date of termination of his services. These conditions are fully satisfied in the present case and, therefore, Rode would be taken to have continuously worked for an year before the date of his termination so as to attract the provisions of Section 25-F. Rode's termination would amount of retrenchment. The termination of Rode's services was void as there has been no compliance of section 25-F.

I have then to consider that in the circumstances of the case what relief can be given to the workman. The workman contended that he had been removed from service because the management wanted to appoint another person. This submission is not born out by the evidence and is clearly refuted by the management. There is no question of any mala fides in this case. The person who has been given the appointment was senior to Rode and his allegation that it was to favour him is wholly misplaced. The difficulty then in this case is that after his services were terminated on 3-9-1979 he was appointed on daily wages whenever the management wanted the services of an extra hand. Thus in the first instance he worked for about 14 days, then for 4 days and then again for 12 days when he was told that he should no longer come to the office. Under section 25-E a workman is not entitled to compensation in cases when he does not present himself for

work at the establishment at the appointed time during normal working hours at least once a day. There is absolutely no evidence that Rode had presented himself for duty at the appointed time during normal working hours on any of the days after the termination of his services. Therefore, though he may be deemed to be in employment he would not be entitled to back wages for the period he remained unemployed. The effect of non-compliance of section 25-F would be that the termination would be without any justification and the workman would be deemed to be in employment. The award, therefore, made as under :—

1. The termination of services of Mahadeo Rode, peon, with effect from 15-12-1979 was not justified as there had been a total non-compliance of the provisions of section 25-F of the Act.
2. Rode would be deemed to be in employment with effect from 16-12-1979.
3. Rode, however, will not get the back wages as there had been no compliance of section 25-E (2) of the Act as he had not presented himself for work during the office hours on any of the days.
4. Rode will present himself for work during duty hours now. If the management wants to retrench him, a compliance of section 25-F of the Act would be imperative.
5. The Management shall pay costs of Rs. 200 to the other party.

JUSTICE M. K. DUBE, Presiding Officer
20-12-1983.

[No. L-15012(2)/83-D.II(B)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1983

शुद्धि-पत्र

का० आ० 303:—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) के आदेश संख्या एल०-12012/19/83 डी०-II (ए) तारीख 29 सितम्बर, 1983 की अनुसूची में "1-2-1982" के स्थान पर "1-12-1982" पढ़ा जाए ।

[संख्या एल-12012/19/83-डी II(ए)]

New Delhi, the 6th December, 1983

CORRIGENDUM

S.O. 303.—In the schedule to the Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) Order No. L-12012/19/83-D. IIA dated the 29th September, 1983 for "1-2-1982" read "1-12-1982".

[No. L-12012/19/83-D. II(A)]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 304.—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) के आदेश संख्या एल-12012/173/82 डी०-II (ए) तारीख 25-6-1983 की अनुसूची में "30-1-80" के स्थान पर "27-8-80" पढ़ा जाए ।

[संख्या एल-12012/173/82-डी०-II (ए)]

एन० के० वर्मा, डैस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

S.O. 304.—In the Schedule to the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) Order No. L-12012/173/82-D. IIA. dated 25-6-1983, for "30-1-80" read "27-8-80".

[No. L-12012/173/82-D. IIA.]

N. K. VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 16th January, 1984

S.O. 305.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Travancore and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st December, 1983.

BEFORE THIRU T. ARULRAJ, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU MADRAS

(Constituted by the Government of India)
Wednesday the 21st day of December, 1983
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 18 OF 1982

[In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of State Bank of Travancore, Head Office, Trivandrum-1]

BETWEEN

Sri P. V. Sasidharan Pillai, Rasmi Nivas, Pallickal East, Thekkekara P.O., East Mavelikkara.

(Change of address as per High Court of Kerala's Order in W.A. No. 300/1983, dated 8-6-1983).

AND

The Managing Director, State Bank of Travancore, Head Office, Trivandrum-1.

Reference :—Order No. L-12012/174/81-D.II(A), dated 27th February, 1982.

This dispute after remand by the Kerala High Court as per Order in W.A. No. 300/1983, dated 8-6-1983, coming on this day for final hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiru P.V. Sasidharan Pillai, workman concerned and the Manager, Personnel Administration of the Management, and both of them having filed a joint memorandum of compromise and recording the same, the Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute arising out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 by the Government of India in Order No. L-12012/174/81-D.II(A), dated 27th February, 1982 for adjudication of the following issue :

> Whether the management of State Bank of Travancore was justified in discharging Shri P. V. Sasidharan Pillai from the services of the Bank with effect from 10-3-1980, and if not, to what relief is the workman entitled ?

2. On 14-6-1982, award was passed by my predecessor Holding that the action of the Management in discharging Thiru P. V. Sasidharan Pillai from the Bank's service with effect from 10-3-1980 is unjustified and the concerned workman would be deemed to be in continuous service of the Management Bank even from 6-5-1977 till date with full wages and other attendant benefits etc. Against this award, the Management Bank preferred writ petition in O.P. No. 6091/82 and the writ appeal in W.A. No. 300/83 in the High Court of Kerala at Ernakulam. As per judgement in W.A. No. 300/83 dated 8-6-1983, the above industrial dispute has been remanded to this Tribunal for fresh disposal in accordance with law. On receipt of the order of High Court of Kerala, notices were issued to the parties for appearance on 10-11-1983 and for want of notification from the Government of India for constituting me as the Presiding Officer, Industrial Tribunal, the matter was adjourned to 29-11-1983. In the mean time, Notification No. L-12012/174/81-D.II(A) dated 5-11-1983 from the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour was received on 11-11-1983. The case was posted to 6-12-1983 for enquiry. On 6-12-1983 both parties were present and requested to adjourn this case for reporting settlement and hence the dispute was adjourned to 21-12-1983.

3. Today when the dispute was called, the Petitioner-worker Thiru P. V. Sasidharan Pillai and the Manager, Personnel Administration of the Respondent-Management appeared and filed a joint memorandum of compromise praying to pass an award in terms of the Compromise Memo. I perused the Compromise Memo and find that the terms of Memorandum are fair and reasonable and hence it is recorded

4. An award is passed in terms of the Memorandum of Compromise which will form part of this Award.

5. No costs.

Dated, this 21st day of December, 1983.

(Sd.) T. ARULRAJ
INDUSTRIAL TRIBUNAL

ANNEXURE

Joint Statement Filed on behalf of the workman and the Management of State Bank of Travancore

It is respectfully submitted that the parties to the above Industrial Dispute have agreed to settle the dispute between themselves in the following manner :

1. The Management will reinstate Shri P. S. Sasidharan Pillai in service, with liberty to post him at any of the Bank's branches in Kerala State.

2. The said reinstatement of Shri P. V. Sasidharan Pillai in the service of the Bank will be without any liability on the part of the Management for payment of back wages and other attendant benefits for the period from the date of suspension, i.e., 6th June, 1977 to the date of reinstatement except for Rs. 21,500 already paid to him as per directions of the High Court of Kerala in O. P. No. 6091/82-B.

3. Shri P. V. Sasidharan Pillai will not be entitled to any increments falling due during the period from the date of suspension to the date of reinstatement which shall be treated as stopped with cumulative effect by way of punishment.

4. Shri P. V. Sasidharan Pillai will not be entitled to get credit of any kind of leave, medical aid, bonus etc., from the date of suspension to the date of reinstatement. However, there shall not be any break of service.

It is therefore, submitted that the Honourable Tribunal may be pleased to pass an award as stated above.

Dated this the 21st day of December, 1983.

(Sd).....
(P. V. SASIDHARAN PILLAI)
Workman

For the State Bank of Travancore
(Sd).....
Manager, Personnel
Administration.
(MANAGEMENT)

(Sd.) T. ARULRAJ
INDUSTRIAL TRIBUNAL

[No. L-12012/174/81-D. II (A)]

S.O. 306.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, and their workman which was received by the Central Government on the 3rd January, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 54 of 1983

In the matter of disputes

BETWEEN

Shri Tej Pal,
C/o Shri C. L. Bhardwaj,
Vice-President, National Organisation of Bank Workers, 898, Nai Sarak, Chandni Chowk, Delhi.

AND

State Bank of India, Lauris Hotel, Agra.

APPEARANCES :

Shri J. M. Sood with Shri C. L. Bhardwaj—for the workman.

Shri S. S. Sharma with Shri P. C. Gandhi—for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012(19)|82-D.II(A), dated 29th July, 1982, made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Branch Office, Clock Tower, Aligarh in not absorbing Shri Tej Pal, temporary Peon/Farrash in the Bank's services and terminating his services with effect from 20-8-1974, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The workman, Shri Tej Pal, worked on daily wages with the State Bank of India Aligarh at Rs. 5 per day for 103 days from April, 1974 till August, 1974 and was issued a certificate dated 13th August, 1979 in that respect by the Branch Manager.

3. The workman has claimed that he was entitled to one month's notice or notice pay in terms of Sastri Award before his services could be terminated and he had to be given priority in the matter of appointment, because he had worked for more than 90 days. He demanded reinstatement in service with full back wages. It was urged that this was a case of 'retrenchment' as the term is defined in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947.

4. The Management contested the claim and raised a preliminary objection that the reference is incompetent and the workman had served for less than 240 days and did not come within the purview of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. The following preliminary issue was framed :—

"Whether the reference is competent and the workman is entitled to any relief when he has worked for less than 240 days."

5. The arguments of the parties have been heard. The additional written arguments filed by the workman on 12-12-1983 have also been considered.

6. There is no order of appointment nor is there any written request for any such order and the termination is also oral because the employment is said by the Bank to be on daily basis. The Management's case is that it was a case of casual employment and the employment was not even temporary and he worked for only 4 days in April, 27 days in May, 25 days in June, 27 days in July and 20 days in August, 1974.

7. The case of the workman is that paragraph 522(4) of Sastri Award required 14 days notice and a written signed letter by the Management was required under Paragraph 522(5) of the Sastri Award and that he was covered by the Supreme Court authority in 'Sundermani's case reported in A.I.R. 1976 S.C. 1111 and the action of the Management in terminating the service was vitiated because the Management did not comply with the Sastri Award applicable to him, when it was a case of 'retrenchment' as the term is defined in the Industrial Disputes Act, 1947. The argument is that the workman was not covered under Para 16.9 of Desai Award which excluded the casual employee from that Award because the Bank nowhere showed that he was a casual employee, when he had worked for 103 days.

8. In my opinion the workman has absolutely no claim. He cannot swim into the harbour of Section 25-F of the Act, because he has not served in the Bank for 240 days, and the termination of service is not covered by the provisions of Section 25-F of the I.D. Act.

9. He was given no written order of appointment and the vacancy was never advertised for the public. He can, therefore, have no case for regular or permanent employment over the heads of others, who had no change of competing for this vacancy. Even in cases covered by Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, the law is that the Management's right to terminate services in accordance with the Bank Awards is not taken away and a simple termination of service is allowed, but the judicial view is that the Industrial Disputes Act, 1947 and Section 25-F thereof, as a special law, qualifies

and overrides the Bank Awards and must be complied with in cases where it is applicable. In this case, Section 25-F of the Industrial Disputes Act. 1947 is admittedly not applicable and the workman cannot claim the benefit of that Section.

10. Every statement made in the Awards is not mandatory in the sense that its violation would, ipso facto, render the action void. If that technique were to be adopted, even his appointment would be void when there was no written order for appointment.

11. I am of the clear opinion that it was a case of employment on daily wages at Rs. 5 per day, and it was a wholly casual employment, not covered by the Desai Award as mentioned in Para 16.9 of the said Award, and the workman is not entitled to any capacity or rank as a temporary employee and was not entitled to any notice or compensation. The claim is wholly unfounded and misconceived. The ruling in Sundermoni's case reported in A.I.R. 1976 SC 1111 is being relied upon by the workman without understanding its full import and true significance. The action of the Management in not absorbing Shri Tej Pal in bank service regularly is valid and justified and services of this daily-wager were terminated legally. His absorption in permanent service would have affected the constitutional rights of all other aspirants to Bank service, because when he was appointed to the service of the Bank, the others entitled to notice and to compete for the service in the Bank were never informed of the vacancy. The workman is not entitled to any relief.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

December 16, 1983.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/19/82-D. II (A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1984

का० आ० 307:—भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व समयुक्ता खादान मजदूर संघ, नंदिनी माइन्स जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अधीन उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री के० एस० कांग अतिरिक्त मुख्य कार्मिक प्रबन्धक ।
श्री एस० डी० दीक्षित प्रबंधक (पी०) माइन्स

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री सी० आर० बक्शी जनरल सैक्रेटरी, एस० के० एम० एस०
श्री डी० के० राव, सहायक जनरल सैक्रेटरी, एस० के० एम० एस०

मामलों का संक्षिप्त विवरण

समयुक्ता खदान मजदूर संघ द्वारा एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था जिसमें खान मुख्यालय के ड्राइंग और डिजाइन स्टाफ को राजहारा और नंदिनी के समतुल्य पर प्रोत्साहन की मांग की गई थी। उन्होंने खान खान (मुख्यालय) के डिजाइन और ड्राइंग स्टाफ को प्लांट के ड्राइंग और डिजाइन से अलग करने की भी चुनौती दी थी । कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन भिलाई स्टील प्लांट के खान प्रबंधतंत्र और एम० के० एम० एस० के बीच एक माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमे इस विवाद को श्री एस० के० सन्याल, रेजीडेंट इंजीनियर, एम० ई० सी० ओ० एन० के माध्यस्थम के लिए भेजा गया था । यह माध्यस्थम करार 19-8-1975 को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था ।

तथापि, कुछ कर्मकारों ने एम० पी० संख्या 1076-76 तथा भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधतंत्र ने एम० पी० संख्या 122-77 द्वारा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष इस करार को चुनौती दी । माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को रद्द कर दिया तथा मध्यस्थ को यह निर्देश दिया कि वह कानून के उपबन्धों के अनुसार नया पंचाट दे जिसमें उनके लिए उचित औचित्य दिया गया हो ।

तदंतर, मध्यस्थम श्री एस० के० सन्याल ने उच्च न्यायालय को सूचना देते हुए रांची से अपने स्थानांतरण और अपने बढ़े हुए कार्यभार के आधार पर अपने मध्यस्थम के कार्यभार से त्यागपत्र दे दिया । अतः दोनों पक्षकार अन्य मध्यस्थम नामित करने के लिए सहमत हो गए ।

करार

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री के शनमुधावल, सेवा-निवृत्त उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जो अब निरूवानीयुर मद्रास-41 में रह रहे हैं, के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : (i) क्या खान मुख्यालय के डिजाइन और ड्राइंग स्टाफ को, जिन्हें उत्पादन प्रोत्साहन योजना की परिधि से बाहर रखा गया है, वैध रूप से राजहारा और नंदिनी यंत्रीकृत खानों की उत्पादन प्रोत्साहन योजना की परिधि के अंतर्गत लाया जा सकता है ? यदि हां, तो कैसे तथा किस तारीख से ?

(ख) क्या ओ० एम० क्यू० के डिजाइन और ड्राइंग विभाग के स्टाफ को प्लांट के डिजाइन और ड्राइंग स्टाफ से अलग करना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमे अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

प्रबन्धक,
भिलाई स्टील प्लांट,
स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड,
भिलाई, पिन सं०-490001,
जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में अंतर्गस्त है, या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो, उसका

नाम समयुक्त खदान मजदूर संघ, (एटक से सम्बद्ध),
नंदिनी माइन्स, पिन सं०-490036,
जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 12022 (बारह हजार बाईस)

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 40 (चालीस).

(IV) मध्यस्थ अपना पंचाट राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा। यदि पूर्व-वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता, तो माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वत: रद्द हो जाएगा और पक्षकार नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

(V) मध्यस्थ का खर्च तथा फीस, जिसमें आनुषंगिक प्रभार शामिल है, प्रबंधतंत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — हस्ता०
के० एस० कांग,
अतिरिक्त मुख्य कार्मिक प्रबंधक
हस्ता०
एस० डी० दीक्षित
प्रबन्धक (कार्मिक) खान
मुख्यालय

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले — हस्ता० सी० आर० बक्षी
जनरल सैक्रेटरी, एस० के० एम० एस०
हस्ता०
डी० के० राव,
सहायक जनरल सैक्रेटरी
एस० के० एम० एस०

साक्षी :

ह० 1. (टी० के० राय)

ह० 2. (जी० पी० पीटर)

स्वीकृत

हस्ता०

4-1-1983

(के० शानमुघावल)

[सं० एल-26015/1/83-डी-III(बी)]
नंद लाल, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1984

S.O. 307.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bhilai Steel Plant, Steel Authority of India Limited, Bhilai and their workmen represented by Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Nandini Mines, District Durg (Madhya Pradesh).

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement;

AGREEMENT

(Under Section 10(A) of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

NAME OF THE PARTIES

Representing the Employers :

Shri K. S. Kang,
Addl. C.P.M.

Shri S. D. Dikshit,
Manager (P) Mines.

Representing the workmen.

Shri C. R. Bakshi,
General Secy., SKMS
Shri D. K. Rao,
Asstt. Genl. Secy.,
SKMS

SHORT RECITAL OF THE CASE

An industrial dispute was raised by the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh demanding incentive to the Drawing and Design Staff of Mines H.Q. at par with Rajhara and Nandini. They had also challenged separation of Design and Drawing staff of Mines (HQ) from the Drawing and Design of the Plant. No settlement could be arrived at, but an Arbitration Agreement U/s. 10(A) of the I.D. Act was signed between the Mines Management of Bhilai Steel Plant and the SKMS for referring the dispute for Arbitration of Shri S. K. Sanyal, the Resident Engineer, MECON. The Arbitration Agreement was published in the Gazette of India on 19th August, 1975.

This award was however challenged before the High Court of M.P. by some of the workmen vide M.P. No. 1076/76 as well as by the Management of Bhilai Steel Plant vide MP No. 122/77. The Hon'ble High Court quashed the award given by the Arbitrator and directed the Arbitrator to give a fresh award in accordance with the provisions of the law giving full justification for the same.

Subsequently, the Arbitrator, Shri S. K. Sanyal resigned from his assignment under intimation to the High Court on the ground of his transfer to Ranchi and his increased assignments. Both the parties therefore agreed for nominate another Arbitrator.

AGREEMENT

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the Arbitration of Shri K. Shanmughavel, retired Dy. Chief Labour Commissioner (C), now residing at Tiruvaniyur, Madras-41.

(i) Specific matters in Dispute :

(a) Whether the Design and Drawing Staff of Mines Head Quarters who have been excluded from the purview of the Production Incentive Scheme can be legitimately brought within the coverage of Production Incentive Scheme of Rajhara and Nandini Mechanised Mines. If so, how and from what date ?

(b) Whether the separation of Design and Drawing staff of OMQ Department from the Design and Drawing staff of the Plant was justified ? If not, what relief the concerned workmen are entitled to ?

(ii) Details of the parties to the Dispute including the name and address of the Establishment or undertaking involved.

The Management of
Bhilai Steel Plant, Steel Authority of India Ltd.,
Bhilai—Pin No. 490001.
District Durg (MP).

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the Dispute or the name of the Union, if any, representing the workmen in question.

The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh,
(Affiliated to AITUC),
Nandini Mines. Pin-490036.
District Durg (MP).

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking effected. 12022 (Twelve Thousand Twenty Two).

(v) Estimated number of workmen effected or likely to to be effected by the Dispute. 40 (Forty).

(IV) The Arbitrator shall make his award within a period of three months from the date of publication in the Gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and the parties shall be free to negotiate for fresh arbitration.

(V) The cost and fees of the Arbitrator including incidental charges will be borne by the Management.

Signature of the Parties

Representing the Employers :

Sd/-
(K. S. Kang)
Addl. Chief Personnel Manager.

Sd/-
(S. D. Dikshit)
Manager (Pers) Mines Hq.

Representing the Workmen :

Sd/-
(C. K. Bakshi)
Genl. Secy., SKMS

Sd/-
(D. K. Rao)
Asst. Genl. Secy., SKMS.

Witnesses :

1. Sd/- (T. K. Roy)
2. Sd/- (G. P. Peter)

ACCEPTED

Sd/-
(K. SHANMUGHAVEL)
4-1-1985

[No. L-26015/1/83-D.III.B]
NAND LAL, Under Secy.

New Delhi, the 20th January, 1984

S.O. 308.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Surguja (M.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th January, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.) PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case No. CGIT/LC(R)(59)/1980

Employers in relation to the Management of North Chirimiri Colliery of the Western Coalfields Ltd.

PO : Galhapani, Dist. Surguja (MP)

AND

Their Workman

PRESENT :

Shri Rajendra, Advocate, for the Management.

Shri S. K. Rao, Advocate, for the workman.

INDUSTRY : Coalmine STATE : MP

Dist. : Surguja.

Date of decision : 30-12-1983.

AWARD

The Central Govt., in exercise of its powers under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide its Notification No. L-22012(21)/79-D.IV(B), dated 25-8-1980 referred the following dispute regarding the age of superannuation of Kala Chand Roy for adjudication. The question referred is in the following terms :—

"Whether the action of the management of the North Chirimiri Colliery of the Western Coalfields Ltd. in retiring from service Shri Kala Chand Roy, Safety-cum-Production Assistant with effect from 4-7-1979 over-looking the statutory records is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

Shortly stated, the facts necessary to be stated are these, Kala Chand Roy joined the services of North Chirimiri Colliery in about the year 1954. The Colliery was then under a private ownership. On nationalisation of the mines in the year 1973, Kala Chand became an employee of the second party. According to the workman, when he had joined the services, he had given his date of birth to be 20th July, 1925 and this was accepted and continued to be acted upon even after nationalisation till the year 1978. According to the Management, the date of birth given by Kala Chand at the time of entry in the service was 30th January, 1918. He had given a mining Sirdar's certificate in which his date of birth was shown as 20th July, 1925. On the basis of this, the Management referred to the Commissioner of Coal Mines Provident Fund, Jabalpur to change the date of birth of the workman. It may be stated that the employees in the coalmines have to become members of the Coal Mines Provident Fund and usually a declaration in form 'A' (which is statutory) is submitted by the employees to the Coal Mines Provident Fund Commissioner. The date of birth of Kala Chand Roy was recorded as 30th January, 1918 with the Coal Mines Provident Fund Commissioner. The Commissioner by his letter No. CPF/MP/A/II/Misc.|4828 dated the 18th October, 1978 turned down the suggestion for correction of age of Kala Chand Roy. Kala Chand Roy was, therefore, retired from 3-7-1979 as having reached the age of superannuation taking 30-1-1918 as his date of birth.

The workman produced the Sirdar certificate under Coal Mines Regulations 1957—Mines Act, 1952 dated 19-1-1963 which clearly mentioned his date of birth as 20-7-1925, and his identity card which had been issued by the Management of the Mines also indicated his date of birth as 20-7-1925. Similarly, the Coal Testing certificate under the Mines Act, 1952 issued on 5-7-1963 recorded his date of birth as 20-7-1925. The other documents from which his date of birth could be checked and which supported his case are letters by Manager, North Chirimiri Collieries dated 5-11-1978 and 2-12-1978 addressed to Regional Commissioner, Coal Mines Provident Fund, the insurance policies with LIC taken in the year 1961 and another in the year 1971, his horoscope and the electoral rolls of different periods giving the age of the workman. He has also submitted an affidavit sworn by his mother regarding his date of birth when the controversy arose which has supported his case. He has also stated that his service record with the Colliery be examined and it would be clear from it that his correct date of birth accepted by the management has been 20-7-1925. He alleges that his case as to his date of birth has been reopened for extraneous reasons because his son happens to be the Joint Secretary of a Union at whose behest the workers struck from working. He contended that he was wholly illitrate and though he could sign in English he could not read or write English nor could understand English or Hindi. The entry in the register of Regional Commissioner, Coal Mines, Provident Fund, Jabalpur was not made at his instance but by some person just to put in some date in the date of birth column. The register of the Commissioner was most unreliable for the purposes of correct dates of birth of workman. The Commissioner, Dhanbad in a letter to the General Managers expressed a good deal of doubt about the date of births in the registers of the Commissioner, Coal Mines Provident Fund. Therefore, that records should not serve as the basis for arriving at a definite conclusion regarding the real date of birth of the workman. It was then stated that if the date of birth was taken to be as contended by the Management to be 30-1-18, the date of superannuation would fall on 30-1-1978. But the workman had been continued in service after that date. On 30-8-1978, the D.P.C. met and considered his case of promotion and he was promoted to the post of Safety-cum-Production Assistant. The workman continued till 1979 and it is only because of the Union activities of his son which were concerned in a strike that his case has been taken up by the colliery vindictively. It was lastly contended that there is no provision for superannuation in the Standing Orders applicable to the workman and, therefore, he could not be retired at any particular age.

It would be necessary first to determine the date of birth of Kala Chand Roy as his superannuation would depend on it. According to the Management, he gave his date of birth

at the time of entering into service and the same date has been given by him in form submitted to the Regional Commissioner, Coal Mines Provident Fund, Jabalpur. The application giving the date of birth by Kala Chand Roy is said to be signed by him in English. The above evidence would undoubtedly be entitled to carry great weight unless it was impeached on the ground that the source of information had actually not been Kala Chand Roy and the evidence which purports to be emanating from him in the form of dates given at the time of entry into service and in the application to the Coal Mines Provident Fund Commissioner were not in fact by him. It is in this background that I mean to weigh and examine the evidence produced by the workman.

To begin with, he has produced Sirdar's Certificate. This was received on 19-1-1963 giving his date of birth as 20-7-1925. Simularly, the Gas Testing Certificate issued on 5-7-1963 gives the date of birth as 20-7-1925. Both these certificates would show that at that time, Kala Chand Roy could not sign and his thumb impressions have been taken on these certificates. The certificates have been issued sufficiently earlier when Roy was in service. Since Kala Chand Roy did not pass the matriculation examination, he could not produce the Matriculation Certificate. Whatever qualifications—academic or technical—he had, he had tendered the certificates of having qualified himself from the institutions he had joined. On the basis of the two certificates, he secured promotion in service and the date of birth given in them must have attracted the attention of the authorities of the establishment.

Then we have the identity card signed by the Manager which also gives the same date of birth. There are two letters one dated 1-12-1978 and another dated 5-11-1978 in both of which the Manager, North Chirimiri Colliery referred to the Director General of Mines Safety, Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Dhanbad about the discrepancy in age of Kala Chand Roy. According to these letters, the Manager asserted that he had verified the age of Kala Chand Roy and it was found that his actual date of birth happens to be 20-7-1925 and the necessary correction may, therefore, be made in the record about this. The above evidence would point out that the Management had taken the date of birth of Kala Chand Roy to be 20-7-1925 as claimed by him.

The other evidence is when the applicant declared, on about 30-12-1981 while taking out an insurance policy, his date of birth. His age in 1961 was shown to be of 36 years. The voters' list of Bekunthpur region of 1975 also showed his age as 49 years in 1975. According to this, he could not have reached the age of superannuation in 1979.

In the minutes of the meeting held between the Management of the Western Coalfields Limited and representatives of Bharatiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh at Nagpur on 26th and 27th February, 1979, an item of business pertained to record of date of birth of workmen. The Minutes File of this meeting would show that for the purpose of date of birth, the entries in 'B' form register and Provident Fund records were to be taken into account and in case of any discrepancy in the entries in 'B' form register and Provident Fund records, reliance would be placed on entry in 'B' form register. In the absence of any record or proof of the date of birth, the case would be referred to the Medical Board for determining the age. As it happens, in both form 'B' register and the Provident Fund record the date of birth of Kala Chand Roy is shown as 30-1-1918. Now, I have had the occasion to see the Provident Fund register where in the date of birth of Kala Chand Roy was recorded. This register makes a peculiar showing. Where his date of birth is recorded as 30-1-1918, there are atleast two dozen persons whose dates of birth have been recorded on the same page and all of them having the same dates of birth i.e. 30-1-1918. This clearly shows that for some reasons known to the person making the entry, 30-1-1918 was considered convenient as the date of birth of all those persons recorded on that folio. The same practice is to be found on other folios and it clearly shows that the date of birth recorded in this register cannot be taken to be true. It is difficult to imagine so many persons born on the same day, entering in the service of the colliery on the same day or near about the same day. This clearly gives out that the dates of birth were not as given by the workmen concerned but taking advantage of the illiteracy the person recording the date of birth has put in a date which he felt convenient for reasons best known to him. Kala Chand Roy has stated that he is wholly illiterate and could not know what was written in the register. His illiteracy seems established from the certificates he has furnished where his thumb impressions were taken. Kala Chand Roy asserted that he had joined service at the time when the Mine was not nationalised. That record was with the company and such a record would clearly establish that his date of birth was not 30-1-1918 but as asserted by him in 1925. The Management had all the opportunity to disprove this by producing such record but they have not been able to do so.

There is yet another circumstance which is not without significance. His services were continued till 20-3-1979 by the present management though the superannuation age would fall on 30-1-1978 if 1918 date of birth is taken to be correct. On 30-8-1978, he appeared before the D.P.C. for the promotion post of Safety-cum-Production Assistant. While considering the question of promotion, the age factor is also examined. It would be necessary to know the period for which the candidate was likely to serve on the promoted post by knowing his age. If Kala Chand Roy had already reached the age of superannuation, he would never have been considered for promotion post by the D.P.C. This circumstance really goes to establish that what the workman is saying is true that his age was accepted to be as asserted by him, namely 20-7-1925 and not 30-1-1918.

I am, therefore, clearly of the view that despite the entry in form 'B' register or the age shown in the Coal Mines Provident Fund register, the date of birth of Kala Chand Roy is 20-7-1925. He has been retired on a misconception as to the correct date of his birth. I, therefore, direct that he be taken on the same post and be given the necessary increments that fell due to him had he been in service all these days. However, as regards back wages, since he had not worked for this period, and had not presented himself for work, he would not be entitled, but he would be entitled to wages from 30-12-1983.

ORDER

I, therefore, render this Award and order as under :—

(a) The date of birth of Kala Chand Roy is 20-7-1925 and the registers of the establishment and those of the office of Regional Commissioner, Coal Mines Provident Fund, Jabalpur, be corrected accordingly.

(b) Kala Chand Roy would be taken in service forthwith and shall draw his emoluments from 30-12-1983.

(c) He would be entitled to all the increments due to him for fixing his present emoluments as though he had been in service all these years.

(d) He would also be entitled to other benefits treating him to be in service except wages, and

(e) There shall be no order as to costs.

Sd/-

Justice K. K. DUBE, Presiding Officer

New Delhi, the 20th January, 1984

S.O. 309.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division III and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th January, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ANDHRA PRADESH, HYDERABAD

PRESENT :

Sri M. Srinivasa Rao, M.A.,LL.B., Industrial Tribunal (Central).

Industrial Dispute No. 27 of 1982

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-III, Godavarikhani, Karimnagar District.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-III, Godavarikhani, Karimnagar District.

APPEARANCES :

Sri N. Seshachari, Advocate—for the Workman.

Sarvashri K. Srinivasa Murthy and K. Satyanarayana Rao, Advocates—for the Management.

Reference.—No. L-21012(4)/82-D.IV(B) of Ministry of Labour, Government of India, New Delhi, dated 9th July, 1982.

AWARD

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited is justified in placing Shri B. Ramashanker, Mining Sirdar, Godavari Khani No. 8 Incline in Shot Firer's 'C' Grade with effect from 1st October, 1978 or whether he should be placed in 'C' Grade from 26th December, 1976 the date on which the employee passed the Mining Sirdar Examination or from 1st January, 1977 the date from which the employee is reported to have been acting as Mining Sirdar? If not, from 1st October, 1978 to what relief the workman is entitled?"

is the issue referred to this Tribunal for adjudication by the Government of India in the cited reference.

2. A claims statement and reply have been filed before this Tribunal. But it is not necessary to refer to the averment therein for this disposal. After the matter has been posted for enquiry, the workman never reported ready. To enable the workman to make out their case, the matter has been adjourned number of times even though neither the workman nor his representative is turning up. The Management is reporting ready throughout. Even this day, the Workman and their Counsel are called absent. The workman is thus not taking any interest in the matter and no material is placed by the workman in support of his claim. As there is no representation at all on his behalf, with reluctance, he is set ex-parte. In these circumstances, it has to be held that the workman has not made out his case and is therefore not entitled to any relief.

Award passed in these terms.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 29th day of December, 1983.

Sd/-
Industrial Tribunal.

[No. L-21012/4/82-D.IV(B)/D.III.B]
NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1984

का० आ० 310.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनाइटेड डायगनोस्टिक इंटरनेशनल लिमिटेड, 310, डाक्टर हाउस, 14 पेड्डार रोड, बम्बई-26 और जिसमें इसकी निम्नलिखित शाखाएं शामिल हैं :—

1. मैसर्स मंगलोर नेरोलीजिकल रिसर्च सेन्टर, भू खण्ड, पंजा बिल्डिंग, लाल बाग, मंगलौर।
2. बम्बई मेडिकल सेन्टर, भू खण्ड, गौतम बिल्डिंग, बिले पारले (डब्ल्यू) बम्बई 56।
3. मैसर्स पूना मेडिकल सेन्टर रूबी हाल क्लिनिक कम्पाउन्ड, 40, सासूना रोड, पूना 1

नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गयी है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35018/53/83 पी०एफ० 2]

New Delhi, the 11th January, 1984

S.O. 310.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Diagnostic International Limited, 310, Doctor House, 14, Peddar Road, Bombay-26 including its branches at (1) M/s. Mangalore Neorological Research Centre, Ground Floor, Punja Building Lal Bagh, Mangalore (2) Bombay Medical Centre, Ground Floor, Gautam Building Vile Parle (W) Bombay-56 (3) M/s. Poona Medical Centre Rubby Hall Clinic Compound, 40, Sasoona Road, Poona-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said estabilshment.

[No. S-35018(53)/83-P.F.II]

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1984

का० आ० 311.—मैसर्स पाईनीयर इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्रा० लि०, पो० बाक्स नं० 237, बड़ौदा 390001 (गुजरात/1778) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं: तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/76/83-पी०एफ-2]

S.O. 311.—Whereas Messrs Pioneer Equipment Company Pvt. Ltd., P.B. No 237, Baroda-390001 (GJ/1778) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premiums, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(76)/83-PF.II]

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1984

का० आ० 312.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात:--

"अनन्तपुर जिला के ताड़िपत्रि ताल्लूक में चिन्ना पोलामाडा, कोमाली, गिमल्ला दिने, चिन्ताकुण्टा, इगाडूर और गंगिरेड्डीपल्ली के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत पेड्डापोलामाडा ग्राम के यर्रागुण्टापल्ली उप-ग्राम के क्षेत्र और अलूरु हुस्सानीपुरम, नन्दालापाडू, टी० सकनारीपल्ली, गंजीवारीपल्ली, टी० सुक्कलूर और गाजुलादिन्ने के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत ताड़िपत्री ग्राम।"

[संख्या एस-38013/1/84-एच० आई]

New Delhi, the 12th January, 1984

S.O. 312.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 15th January, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"The area of Yerraguntapalli Hamlet of Pedapolamada Village within the Revenue Villages of Chinna Polamada, Komali, Gimmalla Dinne, Chintrakunta, Igadur and Gangireddipalli;

and

Tadipatri Village within the revenue Village of Aluru Hussanipuram, Nandalapadu, T. Sakanaripalli, Ganjeevaripalli T. Sukkalur and Gazuladinne in Tadipatri Taluk of Anantapur District."

[No. S-38013/1/84-HI]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1984

का० आ० 313.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मार्शल सिक्योरिटी एण्ड डिटैक्टीव ऐजन्सी कार्यालय 310, टेक हैण्ड नियर न्यू ओखला फेज-1 नई दिल्ली-110020 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्थापन के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/399/83/पी० एफ०-2]

New Delhi, the 13th January, 1984

S.O. 313.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Marshal Security and Detective Agency Office, 310 Tekhand Near New Okhla Phase-I, New Delhi-110020 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(399)/83-P. F. II]

का०आ० 314.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलैक्ट्रो, इक्वीपेमेंटस, 483, बर्तन मार्किट, सदर बाजार, दिल्ली-110006 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,.

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(398)/83/पी० एफ०-2]

S.O. 314.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electro Equipments, 483, Bartan Market, Sadar Bazar, Delhi-110006, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(398)/83-P. F. II]

का०आ० 315.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मूवर मोटर्स प्राइवेट लिमिटिड सी-4, को-ओपरेटिव इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बालानगर, हैदराबाद-500037, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/394/83/पी० एफ०-2]

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 315.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees relation to the establishment known as Messrs Mover Motors Private Limited, C-4, Co-operative Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S-35019(394)/83-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

का. आ. 316.—मैसर्स स्वामीजी मिल्स लिमिटेड, 76, पी.के.एस. स्ट्रीट, सिवाकासी पिन-626123 (तमिलनाडु/6357), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(306)/83-पी.एफ.-2]

New Delhi, the 6th January, 1984

S.O. 316.—Whereas Messrs Swamiji Mills Limited, 76, P.K.S. Street, Sivakasi Pin 626123 (TN/6357) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under

clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(306)/83-PF.II]

का. आ. 317.—मैसर्स लक्ष्मी आटोमेटिक लूम वर्क्स लि., होसूर इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स, होसूर-635126, धर्मपुरी जिला तमिलनाडु (तमिलनाडु/11479), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(303)/83-पी.एफ.-2]

S.O. 317.—Whereas Messrs Lakshmi Automatic Loom Works Ltd., Hasur Industrial Complex, Hosur-635126, Dharampuri District Tamil Nadu, (TN/11479), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the maintenance of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benetfis admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(303)/83-PF. II]

का. आ. 318.—मैसर्स नेशनल इन्स्ट्रूमेण्टस लिमिटेड, जादवपुर, कलकत्ता-700032 (पश्चिम बंगाल/1752) और इसकी शाखाएं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(302)/83-पी.एफ.-2]

S.O. 318.—Whereas Messrs National Instruments Limited, Jadavpur, Calcutta-700032 (WB/1752) and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benetfis admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(302)/83-PF. II]

का. आ. 319.—मैसर्स कास्टवाल फाउण्ड्री नारैच, हाथरस रोड, आगरा (उत्तर प्रदेश/6725), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन

फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भविष्य जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/301/83-पी. एफ.-2]

S.O. 319.—Whereas Messrs Castwel Foundry Naraich, Hathras Road, Agra, (UP/6725). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Schem are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(301)/83-PF. II]

का. आ. 320.—मैसर्स हरसन को-आपरेटिव मिल्क प्राड्-यूशर्स सोसाइटीज यूनियन लि., डाक्टर नम्बर 1517, दीनामानी बिल्डिंग, सालागामा रोड, हरसन-573201 (कर्ना. 6740), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/300/83-पी.एफ.-2]

S.O. 320.—Whereas Messrs Hassan Co-operative Milk Producers Societies Union Limited, Dr. No. 1517, Dinamani Building, Salagama Road, Hassan-573201. (KN 6740). (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefit to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(300)/83-PF. II]

का. आ. 321.—मैसर्स वेमा इण्डस्ट्रीज, 32-सेक्टर, ई-इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा भोपाल-462023,) मध्य प्रदेश/4798), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह इक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(299)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 321.—Whereas Messrs Verma Industries, 32, Sector, E, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462023 (MP/4798) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(299)/83-PF II]

का. आ. 322.—मैसर्स वी. एम. टी. मशीन स्टेशन (वेल्लोर), 144, अन्ना रोड, मद्रास-600002 (तमिलनाडु/3045-बी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(312)/83-पी.एफ.-2]

S.O. 322.—Whereas Messrs V.S.T. Service Station (Vellore), 144, Anna Road, Madras-600002, (TN/3045-B) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(312)/83-PF. II]

का. आ. 323.—मैसर्स वी. एस. टी. सर्विस स्टेशन (गैरेज) 144, अन्ना रोड, मद्रास-600002 (तमिलनाडु/3045-ए), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त- तमिलनाडु के पूर्व

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसके स्थापन पहले अपना चन्दा हैं अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(313)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 323.—Whereas Messrs V.S.T. Service Station (Salem), 144, Anna Road, Madras-600002. (TN/3045-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approal give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(313)/83-PF. II]

का. आ. 324.—मैसर्स वी. एस. टी. मोटर्स प्रा. लि., 144 अन्ना रोड, मद्रास-600002 (तमिल नाडु/3045) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम,

1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(314)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 324.—Whereas Messrs V.S.I. Motors Pvt. Ltd; 144, Anna Road, Madras-600002 (1N|3045) (hereinafter refered to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

No. [S-35014/314/83-PF. II]

का. आ. 325.—मैसर्स ओसवाल आयरन फाउन्ड्री, 11/46, राम बाग, हाथरस रोड, आगरा (उ. प्र./4728), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(298)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 325.—Whereas Messrs Oswal Iron Foundry 11/45, Ram Bagh, Hathras Road, Agra (UP/4728). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/298/83 PF. II]

का. आ. 326.—मैसर्स वी. एस. टी. सर्विस स्टेशन प्रा. लिमिटेड, 182-अन्ना रोड, मद्रास-600006 (तमिल नाडु/1134) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सब सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/315/83-पी.एफ.-2]

S.O. 326.—Whereas Messrs V.S.T. Service Station Pvt-Limited, 182, Anna Road, Madras-600006. (TN/1134) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014/315/83-PF-II]

का.आ. 327.—मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, खारीग्राम, डाकघर—गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान/2150) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/297/83-पी.एफ.-2]

S.O. 327.—Whereas Messrs Rajasthan Spinning and Weaving Mills Limited, Kharigram, P.O. Gulabpura District, Bhilwara (RJ/2150) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hareinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/297/83-PF-II]

का. आ. 328.—मैसर्स राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनैन्स सोसाइटी लिमिटेड, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान/1680), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/296/83-पी.एफ.-2]

S.O. 328.—Whereas Messrs Rajasthan State Co-Operative Housing Finance Society Limited, C-Scheme, Jaipur. RJ/-1680), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/296/83-PF. II]

का. आ. 329.—मैसर्स जैन फाउण्ड्री एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, राम बाग, हाथरस रोड, आगरा (उत्तर प्रदेश/4403), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से

पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (295)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 329.—Whereas Messrs Jain Foundary & Engineering Works, Ram Bagh Hathras Road, Agra (UP/4403) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(295)/83-PF-II]

का. आ. 330.—मैसर्स वी. एस. टी. सर्विस स्टेशन (दुद्दालौर), 144, अन्ना रोड, मद्रास-600002, [टी. एन./3045-ग], (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत जो अंशदान प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारियों को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (311)/83-पी. एफ. 21

S.O. 330.—Whereas Messrs V.S.T. Service Station, (Duddalore), 144, Anna Road, Madras-600002. (TN/3045-L) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(311)/83-PF-II]

का. आ. 331.—मैसर्स माउदर्न पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, 97, माउंट रोड, गुइंडी मद्रास (तमिल नाडु/10139), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम से, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी पॉलिसी में कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (307)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 331.—Whereas Messrs Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd., 97, Mount Road, Guindy Madras. (TN/10139) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 ofthe Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(307)/83-PF-II]

का. आ 332 —मैसर्स चोलन इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रेलवे स्टेशन रोड, कुम्बाकोनम, (टी. एन / 9769), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (308)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 332.—Whereas Messrs Cholan Engineering Corporation Limited, Railway Station New-Road, Kumbakonam. (TN/9769). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(308)/83-PF. II]

का.आ. 333.—मैसर्स काल्लाकुरिची कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, मूंगीलथुराईपाट्टू, एस. ए. जिला (टी. एन./6139), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन

पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (309)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 333.—Whereas Messrs Kallakurichi Co-Operative Sugar Mills Limited, Moongilthuraipattu, S.A. District, (TN/-6139). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payments of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules, of the Gorup Insurance Schme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(309)/83-PF. II]

का. आ. 334.—मैसर्स वी. एस. टी. सर्विस स्टेशन, (त्रिची), 2-डी., डिंडुगल रोड, त्रिची-1, (टी. एन./6418), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (310)/83-पी. एफ. 2]

S.O. 334.—Whereas Messrs V.S.T. Service Station (Trichy), 2D. Dindugal Road, Trichy-1. (TN/6418) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payments of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-3514(310)/83-PF. II]

का. आ. 335.—मैसर्स इंडियन गैरेज एंड बी.टी. पद्मनाभन एंड ब्रादर्स, 144, अन्ना रोड, मद्रास-600002 (टी. एन./8236 एंड 8459), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से

कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादर्शक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (316)/83-पी. एफ. 2]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 335.—Whereas Messrs Indian Garage and V.T. Padmanaban and Brothers, 144, Anna Road, Madras-600002, (TN/8236 and 8459), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission or returns, payments of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Gorup Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-3514(316)/83-PF. II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983